

हरियाणा विधान सभा

की कार्यवाही

10 फरवरी, 2009

खण्ड 1, अंक 2

अधिकृत विवरण

## विशय सूची

मंगलवार, 10 फरवरी, 2009

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(2)1
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(2)23
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(2)29
निंदा प्रस्ताव/उसका वापिस लेना	(2)73
कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट में सं गोधन	(2)83
घोशणाएं	
<b>(क) अध्यक्ष द्वारा:</b>	
(i) चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची	(2)84
(ii) अनुपस्थिति के संबंध में सूचना	(2)84
(iii) अनुपस्थिति की अनुमति	(2)85
<b>(ख) सचिव द्वारा:</b>	
सदन के कार्यक्रम में परिवर्तन	(2)90

सदन की मेज पर रखे जाने वाले / पुनः रखे जाने वाले कागज-पत्र	(2)91
विशेषाधिकार मामलो के संबंध मे विशेषाधिकार समिति का प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढाना।	(2)94
वर्ष 1999-2000 से 2004-2005 तक की अवधि के दौरान सार्वजनिक सम्पत्तियो के हस्तांतरण / नीलामी / आबंटन की विस्तृत जांच करने के लिए हरियाणा विधान सभा की समिति का प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढाना।	(2)95
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा	(2)96
बैठक का समय बढाना	(2)137
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(2)137
राज्यपाल क अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(2)113

## हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 10 फरवरी, 2009

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 2.00 बजे (अपरान्ह) हुई। अध्यक्ष (डॉ० रघुवीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

### तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब सवाल होंगे।

#### **Grace Marks given by H.B.S.E.**

**\*1048. Sh. Karan Singh Dalal:** Will the Education Minister be pleased to state whether the Haryana Board of School Education gave grace marks to the students of 8<sup>th</sup> and 10<sup>th</sup> in the Annual Examination held in the year 2007-08; if so, the criteria and objective thereof:-

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता): श्रीमान् जी, एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखा जाता है।

#### वक्तव्य

हां श्रीमान् जी, निम्नलिखित मानदण्ड अपनाये गए:

1. कक्षा आठवीं

हिंदी

5 अंक

गणित 15 अंक

सामाजिक विज्ञान 18 अंक

अंग्रेजी 12 अंक

सामान्य कृपांक 2.5 प्रति गत यदि किसी विद्यार्थी को इसकी आवश्यकता हो।

2. कक्षा दसवीं

अंग्रेजी 9 अंक

गणित 9 अंक

विज्ञान एवं तकनीकी 9 अंक

सामान्य कृपांक 2 प्रति गत, यदि किसी विद्यार्थी को इसकी आवश्यकता हो।

**कृपांक देने का उद्देश्य**

सरकारी स्कूलों में आमतौर पर समाज के गरीब तबके के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। कृपांक देने का उद्देश्य स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की दर को कम करना है। क्योंकि विशेषकर 8वीं व 10वीं में असफल होने पर बहुत से विद्यार्थी स्कूल छोड़ देते हैं।

**श्री कर्ण सिंह दलाल:** अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट सदन के पटल पर रखी है उसमें इन्होंने बताया है कि क्लास 8वीं व 10वीं के लिए इन्होंने ये ग्रेस मार्क्स दिये हैं। अध्यक्ष महोदय, जब इन्होंने यह कार्यक्रम बनाया था उस समय पर हरियाणा के शिक्षाविदों ने काफी टिप्पणियां की थीं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या ये इस बात से सहमत नहीं होंगे कि इस तरीके से ग्रेस मार्क्स देना शिक्षा प्रणाली और खासतौर से हमारे बच्चों की ऐलिमेंटरी एजुकेशन के हिसाब से ठीक नीति नहीं थी। क्या मंत्री जी इस मामले में कोई कमेटी बनाकर इस पर दोबारा विचार करेंगे? क्या इसकी समीक्षा करेंगे कि इस प्रकार का फैसला क्यों लिया गया?

**श्री मांगे राम गुप्ता:** अध्यक्ष महोदय, यह कोई परमानेंट पॉलिसी एडाप्ट नहीं की गई है। पिछले साल सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर कुछ कारणों से नीचे आ गया था उसके कारण सरकारी स्कूलों के रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आ रहे थे। सरकारी स्कूलों में ज्यादातर गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। अगर बच्चे ज्यादा फेल हो जाएंगे तो उनके दिमाग में टैंगुआ हो जाती है और स्कूल छोड़ने की, ड्रॉप आउट करने की सम्भावना बढ़ा जाती है। अध्यक्ष महोदय, सरकार की कोशिश यह रही है कि सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट करने की बजाय ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। अध्यक्ष महोदय, पढ़ाई का स्तर नीचे

जाने के दो चार कारण रहे हैं। एक तो सरकारी स्कूलों में टीचर्स की भारी कमी रही है। अध्यापकों की भर्ती के उपर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी जिससे सरकारी स्कूलों में लगभग 20 हजार टीचर्स की कमी हो गई थी। अध्यक्ष महोदय, दूसरा कारण रहा स्मैस्टर सिस्टम। एक रिपोर्ट आई थी कि स्मैस्टर सिस्टम बहुत अच्छा है और इसके लागू होने से शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। उसको बोर्ड ने लागू कर दिया। अध्यक्ष महोदय, स्मैस्टर सिस्टम लागू होने के कारण पहले स्मैस्टर में बच्चों को इसको समझने में परेशानी आई। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि सरकारी स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चों ही पढ़ते हैं और उनके माता पिता भी ज्यादातर अनपढ़ ही होते हैं। वे उनको समझाने में असमर्थ रहते हैं जिसका असर बच्चों की पढ़ाई के उपर पड़ा। जिन बच्चों के माता पिता पढ़े लिखे हैं वे बच्चों प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। यही कारण रहा कि सरकारी स्कूलों का ऐलिमेंट एजुकेशन का रिजल्ट डाउन आया। सरकार ने देखा कि इतनी तादाद में बच्चों फेल हो गये तो बहुत से बच्चों ड्रॉप कर जायेंगे जो ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने ड्रॉप को बचाने के लिए ग्रेस मार्क्स देने का यह अस्थाई फैसला लिया ताकि उनको कुछ ग्रेस मार्क्स देकर रिजल्ट को कुछ अप किया जाये। इस ग्रेस मार्क्स की बुराई को दूर करने के लिए हमने कुछ फैसले लिए हैं ताकि हमारे सरकारी स्कूलों में ऐजुकेशन इम्प्रूव हो सके। अगर अच्छे टीचर्स होंगे, वैल क्वालिफाईड टीचर्स होंगे। तो पढ़ाई अच्छी होगी। अध्यक्ष महोदय, हमने पाठ्य पुस्तकों की कमी को दूर करने का

फैसला लिया है। पहले पूरा साल बीत जाता था, इम्तिहान आ जाते थे लेकिन किताबे नहीं मिलती थी। जब बच्चे के पास किताबे ही नहीं होंगी तो वह पढेगा क्या। अब हमने यह फैसला लिया है कि सत्र भुरु होने के पहले दिन से ही किताबे उपलब्ध होंगी। इससे काफी इम्प्रूवमेंट होगी। इस मामले में सरकार काफी चिंतित है। सरकार नहीं चाहती कि शिक्षा के मामले में कोई कमी रहे। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा में सुधार करने के लिए सरकार ने और भी बहुत से फैसले लिये हैं। मैं माननीय साथी से कहना चाहता हूँ कि शिक्षा में सुधार के लिए सरकार हर संभव कदम उठायेगी। पूरी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी हुई है उसमें माननीय साथी देख सकते हैं।

**श्री कर्ण सिंह दलाल:** अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के प्रयासों की हम सराहना करते हैं लेकिन मैं इस बात से उनके इत्तेफाक और राय नहीं रखता हूँ। मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब वे अपने जवाब में खुद मान रहे हैं कि गरीबों के ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में पढते हैं, उनके अच्छी पढाई करवाना, उनके लिए शिक्षत्व का अच्छा इंतजाम करना उनका काम है। अगर उनकी पढाई कमजोर है तो उस व्यवस्था के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए थी क्योंकि व्यवस्था ठीक न होने के कारण ही उनकी पढाई ठीक नहीं हो रही थी। बजाये इसके कि हम ग्रेस मार्क्स दे कर बच्चों को पास करें और कमजोर नीवों को आगे बढ़ाएं, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री जी



से फिर से यह जानना चाहता हूं कि चलिये कि इन्होंने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिये लेकिन क्या उन शिक्षकों ने, जिन्होंने बच्चों को ठीक पढाई नहीं करवाई और बच्चों को ऐसी हालत होने लगी है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे?

**श्री मांगे राम गुप्ता:** स्पीकर सर, माननीय सदस्य की चिंता बिलकुल वाजिब है। महकमा सरकार की हिदायत के मुताबिक इस पर विचार कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा है कि किन हालात में ऐसा फैसला लेने में मजबूर हो गये कि लडकों को फेल न किया जाए। अगर गरीबों के लडकों फेल हो जाएंगे तो वे ड्रॉप आउट कर जाएंगे। बड़ी मुश्किल से उन बच्चों को स्कूलों में लाया जा रहा था और यदि वे फेल कर दिए जाएं तो वे स्कूल छोड़ कर चले जाएंगे। उन गरीब बच्चों को पढाना हमारे लिए बहुत जरूरी था। हमने कहा कि टीचर्स में कुछ कमी थी जो ज्यादा क्वालीफाईड नहीं थे या फिर सिफारिसी थे या और भी कुछ कारण रहे हो जिनके कारण वे पढाई ठीक से नहीं करवा रहे थे उनके खिलाफ हमने ऐक्शन लिया है और सख्त से सख्त कार्यवाही हम उनके रिजल्ट्स देखकर कर रहे हैं। ऐसे टीचर्स जो पढाई में इन्ट्रस्ट नहीं रखते और जिनके कारण बच्चों की पढाई का नुकसान हो रहा है उनके बारे में हमने रिपोर्ट मांग रखी है। ऐसे टीचर्स में से कुछ टीचर्स के खिलाफ हमने कार्यवाही की है और कुछ के खिलाफ जल्दी ही कार्यवाही करेंगे। अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो चिंता आपने महसूस की है इससे हम सहमत हैं कि

पढाई का स्टैण्डर्ड उंचा होना चाहिए, इसमे कई ऐसे प्रयास किये गये है जिनसे इस साल की पढाई के रिजल्टस मे बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो जाएगी।

**श्री एस एस सुरजेवाला:** स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी इस बात से सहमत होंगे। कि हरियाणा मे पढाई का जो लेवल है वह भार्मनाक हद तक नीचे है और इस सरकार ने इसको इम्प्रूव करने के लिए कई फैसले लिये है जिनके दूरगामी रिजल्टस होंगे जिनका पता बहुत देर के बाद लगेगा। एक तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आज से पता नही कितने साल पहले यह फैसला लिया गया होगा कि पास मार्क्स 33% और फर्स्ट डिवीजन 61% मार्क्स होंगे। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि जब 50% मार्क्स पास के लिए और फर्स्ट डिवीजन 75% से भुरु करेंगे। स्पीकर सर, अगर आप ऐसा नही कर सकते तो यह कोई पढाई वढाई नही है। जहां तक गरीब आदमी के बच्चो की बात है, यह सच बात हे कि वि शेतौर से गावों मे और छोटे भाहरो मे भी पढाई का लेवल बहुत नीचे है। सरकार ने एक बहुत अच्छी बात की है कि जे बी टी का भौक्षणिक स्तर 10 जमा 2 को जे बी टी मे दाखिला नही करेंगे। इसी प्रकार से साईस, इंगलि 1 और टैक्नोलोजी की पढाई मे वे बिलकुल जीरो है। जब तक यह नही होगा हरियाणा मे समूचे प्रदे 1 मे हम तरक्की नही कर सकेंगे और गरीब आदमी की भी तरक्की नही होगी। स्पीकर सर, मैंने

इसके लिए यह जो मार्क्स की बात कही है क्या सरकार इस बारे में कोई आवासन देगी?

**श्री मांगे राम गुप्ता:** स्पीकर सर, 33% पास मार्क्स का सिस्टम होते हुए यह रिजल्ट इतना डाउन आया है। अभी तो हमने रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए यह किया है ताकि लडके फेल न हो। 33% मार्क्स में इतने ज्यादा लडके फेल हो गये अगर पास मार्क्स 50% कर देंगे तो फिर लडको का पास होना बहुत मुश्किल हो जाएगा और रिजल्ट और भी बहुत ज्यादा डाउन हो जाएंगे। हमने ऐजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए यह किया है कि टीचर्स अच्छी क्वालिटी के होंगे। स्पीकर सर, जैसे कि आप खुद सहमत हुए हैं कि हमने सैट टेस्ट लागू किया है और इसमें बी ए की क्वालिफिकेशन कम से कम की है। रिजल्ट्स अच्छा न आने की और भी कई वजहें थीं। किताबें समय पर नहीं मिलती थीं। गरीब बच्चों को सरकार की तरफ से समय पर फ्री किताबें दी जाएंगी ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई पूरे जोर भाव से कर सकें। रिजल्ट एकदम सामने नहीं आता है उसमें समय लगता है। हम अभी इसको देख रहे हैं। इस साल का रिजल्ट अभी सामने आएगा तो पता चलेगा कि इसमें कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। अगर इस बार हमारे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, हमारे बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं तो हम पासिंग परसेंटेज को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के बारे में विचार करेंगे। जहां तक सुरजेवाला साहब ने साईंस और अंग्रेजी मीडियम की बात कही है, हमने इस बारे में प्रयास किए हैं, अब की

बार हमने हरियाणा मे अंग्रेजी मीडियम के स्कूल भी भुरु किए है। हालांकि इसमे भुरु मे बहुत दिक्कत आ रही है। अंग्रेजी मीडियम मे हर सब्जैक्ट को पढाने मे टीचर्ज भी दिक्कत महसूस कर रहे है लेकिन फिर भी हम कोि । । कर रहे है इसके अलावा साईंस के लिए हमने बहुत से स्कूलो को सिलैक्ट किया है। इस स्कीम के तहत बहुत से साईंस और कार्म्स स्ट्रीम के स्कूल चालू हो रहे है।

**श्रीमती सुमिता सिंह:** अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मेरी सप्लीमेंटरी सुरजेवाला जी ने पूछ ली है जो कि मै पूछना चाहती थी। फिर भी मै मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि अगर अगले समैस्टर मे भी बच्चे फेल हो गए तो क्या उनको दोबारा से ग्रेस मार्क्स देकर पास किया जाएगा क्या इसके बारे मे विचार किया गया है क्योंकि इतनी जल्दी मार्क्स इम्प्रूव नही होंगे।

**श्री मांगे राम गुप्ता:** अध्यक्ष महोदय, इस बारे मे मैने पहले ही कहा है कि यह ग्रेस मार्क्स देने की हमारी कोई परमानेंट पालिसी नही है। अब की बार के हालात के मुताबिक विचार करके यह टैम्परेरी फैसला लिया गया था। हमे उम्मीद है कि इस बार जो फर्स्ट और सैकेंड समैस्टर के रिजल्ट आएंगे वे अच्छे आएंगे और भायद ग्रेस मार्क्स देने की जरूरत नही पडेगी।

**डा० सीता राम:** अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब मे बताया है कि सरकारी स्कूलो का रिजल्ट अच्छा नही आया था और इन्होने ड्राप आउट को रोकने के लिए सरकारी स्कूलो मे ग्रेस

माक्स दिए है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल से अपीयर होता है तो क्या ये ग्रेस माक्स उसको भी दिए जाते है? इन्होंने अपने जवाब मे माना है कि गरीब लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलो मे पढते है और उनको ही ग्रेस माक्स दिए गए है।

**श्री मांगे राम गुप्ता:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि ग्रेस माक्स का जहां तक ताल्लुक है, वह चाहे प्राइवेट स्कूल का बच्चा हो या सरकारी स्कूल का बच्चा हो उन सबको दिए गए है। इससे मैं एक बात और क्लीयर करना चाहूंगा कि जो बच्चा प्वायंट पर फेल हो रहा था उन्ही को ग्रेस माक्स दिए गए है। इसमे किसी के साथ भेदभाव नही है। हम यह मानकर चलते है कि प्रावईवेट स्कूलो के रिजल्टस गवर्नमेंट स्कूलो से बहुत अच्छे है।

**प्रो० छतर पाल सिंह:** अध्यक्ष महोदय, आज सदन मे जो शिक्षा कि ढांचे पर चर्चा हो रही है यह बहुत अच्छा सवाल सदन मे उठाया गया है। मंत्री जी इसके बारे मे बहुत अच्छा जवाब दिया है। मंत्री जी ने जब ग्रेस माक्स के सवाल का जवाब तैयार किया होगा तो उस वक्त इन्होंने महकमो से भी पूछा होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब से हरियाणा बना है.....

**श्री अध्यक्ष:** क्या आप यह सोचते हैं ये अपने जवाब दे रहे हैं? आपको भी पता है कि सवाल का जवाब देने से पहले महकमे से डिस्कान होती है, कंसलटेडान ली जाती है। जब आपको बस कुछ पता है तो आप व्यवस्था का प्रश्न क्यों उठाते हैं। आप सिर्फ अपना सवाल पूछें।

**प्रो० छतर पाल सिंह:** स्पीकर सर, मेरा सवाल इस बात पर आधारित है कि आप और मंत्री जी यह न कह दे कि यह पोसिबल नहीं है। स्पीकर सर, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि वर्ष 2007-2008 के अलावा अब तक कितने सालों में 8वीं और 10वीं में ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं? मंत्री जी ने आज जवाब दिया है कि हमें इस पर लोट आफ इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। प्रजातांत्रिक सिस्टम में अगर सच पूछें तो देहात के अंदर मास्टर सबसे बड़ा राजनीतिक व्यक्ति है। वह सरकार के बस का मसला नहीं है। मैंने यह सवाल जो पूछा था वह पैदा होता है कि 8वीं और 10वीं तक कितने सालों तक ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। प्राइवेट सिस्टम में और सरकारी सिस्टम में कम्पीटीशन नहीं हो पा रहा है। हम प्राइवेट सिस्टम से बहुत नीचे खड़े हैं। हमारे पास आई ए एस अधिकारी है, एजुकेटिड आफिसर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, यहां तक कि सारा तामझाम है, इसके बावजूद हम स्कूलों में अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। क्या सरकार ने इस बारे में कोई प्रमानेंट सोल्यूशन निकाला है। जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा क्या उसकी सैलरी में डिडकट करके उसकी अकाउंटेबिलिटी की जाएगी। इसके

अलावा सरकार की ट्रांसफर पालिसी है कि अगर एक मास्टर 4-5 साल एक स्कूल में पढाएगा और उसका रिजल्ट अच्छा आएगा तो उसको इन्सैंटिव देंगे। क्या ऐसा कोई परमानेंट सोल्यूशन है so that we may have a better system of education in the Village Government Schools. क्या सरकार ने ऐसा किया है और कितने ग्रेस मार्क्स अब तक दिए गए हैं?

**श्री मांगे राम गुप्ता:** अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा कि ग्रेस मार्क्स की जहां तक बात है, यह कोई परमानेंट सिस्टम या पालिसी नहीं थी। यह तो जरूरत के मूताबिक किया गया फैसला था क्योंकि लड़के ज्यादा फेल हो गए थे। छतर पाल जी, आपको भी पता है कि सी बी एस ई में 10वीं की फाइनल परीक्षा से पहले इन्टरनल एग्जाम्ज होते हैं। हमारी कोशिश यह रही है कि बच्चे फेल न हों। हमने आठवीं कक्षा का भी इम्तीहान लिया है लेकिन जब यह महसूस किया गया कि गरीब बच्चे अगर फेल हो जाएंगे तो वह ड्रॉप कर जाएंगे इसलिए ग्रेस मार्क्स देने की बात सोची गयी। स्पीकर सर, मैंने शिक्षा के स्तर को इम्प्रूव करने के लिए दो तीन रीजंज दिए हैं। पहले तो सरकारी स्कूलों में टीचर्स ही न हों तो पढाई की वीकनेस तो रहेगी ही। इसके अलावा किताबों की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। पूरा साल निकल जाता था लेकिन किताबें भी समय पर छपकर नहीं आती थी इसलिए हमने इसको भी इम्प्रूव किया है। स्पीकर सर, हमने हार्ड फैसला लिया है कि जब पढाई का नया सेशन शुरू होगा तो उस समय ही बच्चों के हाथों में फ्री किताबें सरकार देगी। किताबों की

कोई कीमत नहीं होगी और न ही ये बाजार से खरीदनी पड़ेगी। जहां तक ग्रेस मार्क्स देने का प्र न है, मेरे पास सारी सूचना है इसलिए मैं इनको बता देता हूं कि वर्ष 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 और 2008 में भी ग्रेस मार्क्स देकर कुछ बच्चे पास किए गए थे।

(यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा सदन में उपस्थित नहीं थे।)

**Maintenance of Existing By-Pass in Bhiwani by P.W.D (B&R)**

**\*1066. Dr. Shiv Shankar Bhardwaj:** Will the P.W.D (B&R) Minister be pleased to state it is a fact that half portion (Loharu road to Tosham road) of existing Bhiwani by Pass is under the control of HSAMB and other half (Tosham road to Hansi road) is under the control of P.W.D (B&R) Haryana; if so, whether there is any proposal to hand over the whole by pass to P.W.D (B&R) for proper maintenance?

**Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav):** Yes Sir, but there is no such proposal.

**डा० शिव शंकर भारद्वाज:** स्पीकर सर, एक ही भाहर में एक ही सड़क आधी किसी एक विभागी के पास है और आधी किसी दूसरे विभागी के पास है। आधी सड़क का रंग रूप कुछ और है और आधी सड़क का रंग रूप कुछ और है। आधी सड़क में बहुत ज्यादा गड़बड़ है और आधी सड़क में रैगुलर मेंटेनेंस अगर हो तो यह बहुत बुरा लगता है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से



जानना चाहूंगा कि अगर यह सडक एक ही विभागी के पास दे दी जाए तो इसमे क्या बुराई है? यह व्यवस्था बुरी है इसलिए क्या इसको ठीक करने के लिए मंत्री जी कोई प्रयत्न करेंगे?

**कैप्टन अजय सिंह यादव:** स्पीकर सर, माननीय मैम्बर ने जो अपना कंसर्न बताया है वह बिल्कुल सही है। जो यह बाईपास है इसका एक पो र्नि भिवानी-लोहारु से भिवानी-तो शाम तक तकरीबन साढे चार किलोमीटर खराब है। यह पो र्नि एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के पास है। भिवानी-तोशाम रोड से भिवानी-हांसी रोड तक का जो पो र्नि है वह ढाई किलोमीटर है जोकि पी डब्ल्यू डी (बी एण्ड आर) के पास है। इस सडक का जो टुकडा मार्केटिंग बोर्ड के पास है उसकी हालत बहुत खराब है। जो पो र्नि मार्केटिंग बोर्ड के पास है उसकी मैंटीनेंस के लिए 24 दिसम्बर को मार्केटिंग बोर्ड की तरह से टैंडर हो चुके है और इसका वर्क अलाट कर दिया गया है। हमे उम्मीद है कि मई, 2009 तक यह रिपेयर हो जाएगा। स्पीकर सर, इनकी बात बिल्कुल वाजिब है वहां पर पैसेंजर्स का युनिट तकरीबन 16-17 पी सी यू है यानि दिन मे उस रोड पर 6-7 हजार गाडियां रोजाना निकलती है। मै समझता हूं कि मार्केटिंग बोर्ड उस सडक के अपने पो र्नि की मैंटीनेंस नही कर पाएगा इसलिए मैने सैक्रेटरी, पी डब्ल्यू डी (बी एण्ड आर) को आदे ा दिये है कि वे सैक्रेटरी एग्रीकल्चर से इस बारे मे मीटिंग करे ताकि जो पो र्नि उस सडक का मार्केटिंग बोर्ड के पास है उसको हमारा विभाग टेक ओवर कर लें। उस

बाई पास पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है इसलिए वह रोड हमारे विभागी के पास होनी चाहिए। स्पीकर सर, हमारे विभागी के सैक्रेटरी उनसे बातचीत कर लेंगे।

**श्री अध्यक्ष:** कैप्टन साहब, आप केवल एक सडक के बारे में ही कह रहे हैं या फिर राज्य की दूसरी सडको के बारे में भी कह रहे हैं। मार्केटिंग बोर्ड की जो पुरानी सडके हैं उनकी मेंटिनेंस आपके विभागी के हाथ में है या मार्केटिंग बोर्ड के हाथ में है? सडक का मतलब तो पी डब्ल्यू डी (बी एण्ड आर) ही होता है। चटठा साहब को तो इस बारे में कोई याद नहीं करता।

**कैप्टन अजय सिंह यादव:** स्पीकर सर, मैं केवल इस बाई पास के बारे में ही कह रहा हूँ। जितनी भी सडके मार्केटिंग बोर्ड के पास हैं उन सबीक हम रिपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतने फंडज हमारे पास नहीं हैं। मार्केटिंग बोर्ड के पास फंडज हैं और जो रोडज वे बनाते हैं उनकी रिपेयर भी वे ही करते हैं। जो यह बाई पास है इसको हम एक ए स्पे गल केस टेक अप कर लेंगे ताकि इसकी मेंटिनेंस ठीक तरह से हो सके। वर्ष 2009-10 का हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हम इस सडक के अपने पोर्न की जरूर रिपेयर करेंगे। मार्केटिंग बोर्ड वाले उस सडक का अपना पोर्न ठीक कर देंगे लेकिन इस पूरी सडक को टेकओवर करने की प्रक्रिया हम शुरू कर देंगे।

**डा० वि० भांकर भारद्वाज:** अध्यक्ष महोदय, यह जो दादरी लोहारु रोड से तो गाम रोड और तो गाम रोड से हांसी रोड तक बाई पास है उस पर भारी तादाद में वाहन चलते हैं क्योंकि उस एरिया में रोडी की सप्लाई खानक से होती है, वह सारा माल इन रोडज से जाता है। मैं इस बात के लिए तो मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि इनहोंने यह बात स्वीकार कर ली कि इस रोड की मेंटिनेंस लोक निर्माण विभागी से करवाएंगे लेकिन साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या इसको थोड़ा सा और स्ट्रेंगथन करने का विचार है? दूसरे भिवानी में इसके अलावा और कोई बाई पास नहीं है। रोहतक रोड से मेहत रोड तक और रोहतक रोड से दादरी रोड तक कई वर्षों से बाई पास की सख्त जरूरत है, क्या मंत्री जी इस पर भी गौर करेंगे?

**कैप्टन अजय सिंह यादव:** अध्यक्ष महोदय, सडक कमी रिपेयर के बारे में मैं कह चुका हूँ कि उसमें हमारा जो ढाई किलोमीटर का पोर्न है उसकी रिपेयर हम कराएंगे। जो पोर्न मार्केटिंग बोर्ड के पास है उसके टैंडर कर दिये गए हैं। (विधन)

**श्री अध्यक्ष:** मंत्री जी, क्या दादरी से महम, रोहतक से दादरी और रोहतक से महम तक बाई पास बनवाएंगे?

**कैप्टन अजय सिंह यादव:** अध्यक्ष महोदय, अभी जो ऐग्जिस्टिंग बाई पास है मैंने उसकी रिपेयर की बात कही है। जो

माननीय सदस्य की नये बाई पास की मांग है उसके बारे में हम सर्वे कराएंगे और बाद ही मैं कुछ कह सकता हूँ।

**डा० सु गीला इन्दौरा:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सिरसा मिनी बाई पास का निर्माण कार्य पी डब्ल्यू डी (बी एण्ड आर) के पास है और चतरगढ पट्टी तक 200-300 गज का एरिया कई महीनों से अधूरा पडा है उसके बारे में क्या मंत्री जी कोई कार्यवाही करवाएंगे?

**कैप्टन अजय सिंह यादव:** अध्यक्ष महोदय, सिरसा में एक बाई पास प्रपोज कर रहे हैं। (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष:** इन्दौरा जी, यह कह रहे हैं कि बाई पास आल्लरेडी है उसके थोड़े से टुकड़े का निर्माण कार्य अधूरा पडा है।

**कैप्टन अजय सिंह यादव:** अध्यक्ष महोदय, उसके बारे में ये सैप्प्रेट नोटिस दे दें।

**श्री अध्यक्ष:** कैप्टन साहब, टुकड़ा अधूरा पडा है तो कह दे कि बनवा देंगे।

**कैप्टन अजय सिंह यादव:** अध्यक्ष महोदय, नार्मली बाई पास के निर्माण का कार्य पी डब्ल्यू डी (बी एण्ड आर) के पास होत है। 15.69 किलोमीटर का बाई पास सिरसा में प्रोपोजड है उस पर कंस्ट्रक्शन कास्ट 12 करोड रुपए आएगी। उसकी टोटल कास्ट 21.49 करोड रुपए है। वह हम प्रपोजल कर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष:** ऐसा है कप्तान साहब, इन्दौरा जी किसी नये बाई पास की बातज नही कर रहे है। ये मिनी बाई पास मे कह रहे है और वह भी अप्रूवड है उसका टुकडा बाकी है क्या उसको पूरा करवाओगे या नही, यह बताएं?

**कैप्टन अजय सिंह यादव:** अध्यक्ष महोदय, मै इसके बारे मे चैक करके ही कोई जवाब दे सकता हूं। हमें फंडज देखने पडते है, बजट प्रोविजन देखने पडते है। मै ऐसे कैसे कह सकता हूं। मुझे सारा मैटर देखना पडेगा। यह भी देखना पडेगा कि उस पर कितना ट्रैफिक है तभी इस बारे में मै कुछ बता सकता हूं।

**डा० सु गीला इन्दौरा:** अध्यक्ष महोदय, सिरसा मे एक ओवर ब्रिज बन रहा है उससे काफी ट्रफिक कंजै न होगा और लोगो को बडी भारी दिक्कत होगी। वहां बाई पास बन जाए और फाटक बन जाए तो काफी सुविधा हो जाएगी। क्या मंत्री जी इसको जल्दी करवाने की व्यवस्था करेंगे?

**कैप्टन अजय सिंह यादव:** अध्यक्ष महोदय, जो बाई पास प्रपोजड है उसमे इनका यह बाई पास भी कवर हो रहा है इसलिए इसके लिए ये सैपरेट नोटिस दे दे तभी देखूंगा।

**श्री अध्यक्ष:** कैप्टन साहब, इन्दौरा जी मिनी बाई पास की बात कर रहे है। उसका टैंडर भी हो चुका है और पैसे भी गए हुए है उसका कुछ पों न बाकी है।

**कैप्टन अजय सिंह यादव:** स्पीकर सर, वह अभी प्रपोजड बाई पास है।

**श्री अध्यक्ष:** इन्दौरा जी आप लिख कर भिजवा देना।

**श्री रमे । गुप्ता:** अध्यक्ष महोदय, वेसे मेरे सवाल का भारद्वाज साहब के सवाल से कोई लिंक नहीं है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र से ढांड और लाडवा से मुस्तफाबाद तक सडक की बहुत ही खस्ता हालत है। ये पी डब्ल्यू डी की सडके है और इन पर व्हीकल्स चलना तो दूर की बात है पैदल चलना भी मुश्किल है। हम कई बार इस बारे में विभागी के नोटिस में लाए हैं लेकिन अभी तक रिपेयर का काम भुरु नहीं किया गया है।

**श्री अध्यक्ष:** गुप्ता जी, आप इस बारे में नोटिस भिजवा देना।

**श्री जगबीर सिंह मलिक:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1996-97 में कुछ सडके पंचायती राज विभागी द्वारा बनाई गई थी। अब वह महकमा न तो सडको की मरम्मत कर रहा है और न ही निर्माण कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के की तीन सडके जो पंचायती राज के महकमे में बनाई थी वह बिल्कुल टूट गई है और वह महकमा उन सडको को ठीक नहीं कर रहा है। क्या मंत्री जी उन सडको को पी डब्ल्यू डी महकमे के अधीन टेक ओवर करके उनकी रिपेयर करवाएंगे?

**कैप्टन अजय सिंह यादव:** अध्यक्ष महोदय, जो सडके पंचायती राज महकमे ने बनाई थी हम उन सडको को टेक ओवर कर रहे है ओर उन सीी सडको की रिपेयर भी करवाएंगे।

**श्री साहिदा खान:** अध्यक्ष महोदय, तावडू भाहर मे एंट्री करते है तो कोई भी पी डब्ल्यू डी महमके की सडक ठीक नही है। चाहे नूह हेडक्वार्टर की सडके हो, चाहे भेगीपुर रोड हो और चाहे बावला रोड, छरोडा रोड जाता है इन सभी रोडज मे गडढे हो रहे है। ने नल हाई वे नं0 71 बी वाली सडक का भी हाल बुरा है। आदमी यह सोचकर जाता है कि यह ने नल हाई वे की सडक है परंतु उस सडक का भी बहुत बुरा हाल है। दूसरी सडके मेरे गांव िाकारपुर वाली सडक है उसाक भी बुरा हाल है। मोहमदपुर अहीर से नौरंगपुर होते हुए जो सडक गुडगांव को जाती है और जो पटौदी को सडक जाती है उसका भी बुरा हाल है। इस प्रकार से तावडू भाहर मे एक भी बढिया सडक से एण्ट्री नही है। अढाई साल हो गये है इन सभी सडको का बुरा हाल है जबकि मंत्री जी हमारी ग्रीवेन्सिज कमेटी के चेयरमेन भी रहे है। मैने पिछले सदन मे भी इस बारे मे बात की थी। अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इन सडको की मरम्मत करवाने का काम करेंगे? अगर मरम्मत नही तो कम से कम क्या वे इन सडको के गडढे भरवाने का काम करेंगे?

**कैप्टन अजय सिंह यादव:** अध्यक्ष महोदय, तावडू और नूह की सडक के बारे मे माननीय सदस्य ने जिक किया है। इस

सडक की हम वार्डनिंग और रिपेयर करवायेंगे। इन सडको को हमने एन सी आर के तहत ले लिया है और इनकी रिपेयर का काम भी भुरु हो गया है। दूसरा जो इन्होंने ने इनल हाई वे वाली सडक का जिक किया है, इसके लिए टैण्डर इन्वार्डिट कर दिया है और इस सडक की रिपेयर का काम हम करवाएंगे। गुडगांव से नूहं वाली सडक को भी हमने एन सी आर के तहत ले लिया है और 450 करोड रुपये अकेले मेवात के एरिया की सडको को ठीक रकने के लिए पास किये गये है और रिपेयर का काम भी भुरु कर दिया गया है।

**आई जी भोर सिंह:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पी डब्ल्यू डी या मार्केटिंग बोर्ड द्वारा जो सडके बनाई जाती है क्या उन सडको की क्वालिटी के बारे में उन अधिकारियों की कोई एकाउंटेबीलिटी होती है जिनकी देख रेख में ये सडके बनाई जाती है? अगर क्वालिटी सही नहीं पाई गई तो क्या उन अधिकारियों के खिलाफ विभागी द्वारा कोई कार्यवाही की जाती है?

**कैप्टन अजय सिंह यादव:** अध्यक्ष महोदय, वैसे तो पी डब्ल्यू डी महकमे द्वारा जो सडके बनाई जाती है उनकी क्वालिटी अच्छी होती है ओर विभागी ने एक क्वालिटी कन्ट्रोल विंग बनाया हुआ है जो बकायदा इसके बारे में चैक करता है। अभी तक तो मेरे नोटिस में ऐसा कोई केस नहीं आया है। अगर माननीय सदस्य के पास इस बारे में कोई स्पैसिफिक कम्प्लेंट है तो वह मुझे बताये



उसके बारे में इन्कवायरी करवाकर जो दोषी जाये जाएंगे उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही जरूर की जायेगी।

**श्री अमीर चन्द मक्कड:** अध्यक्ष महोदय, जैसा की यह सडको के बारे मे प्र न चल रहा है। मेरे हलके के गांव ढाणी कुतुबपुर और खरकडा से हांसी की जो रोड है वे आधी पी डब्ल्यू डी द्वारा बनाई गई थी और आधी मार्केटिंग बोर्ड द्वारा बनाई गई थी लेकिन वे सडके अब टूट गई है। कोई ऐसा प्रबंनध किया जाए कि सारी सडक एक ही विभागी द्वारा बनाई जाए ताकि उनको सही तरह से बनाया जा सके। इसी प्रकार से हांसी-उमरा की सडक पी डब्ल्यू डी द्वारा बनाई गई थी और वह सडक छह महीने से पहले ही टूट गई। क्या इस के बारे मे मंत्री जी कोई इन्कवायरी करवायेंगे? ठेकेदार बीच मे ही काम छोडकर गलत काम करते है। क्या मंत्री जी इन सडको को दोबारा से बनवायेंगे?

**कैप्टन अजय सिंह यादव:** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि कुछ रोड्ज पी डब्ल्यू डी ने बनाई थी वह टूट गयी है। वैसे तो रुरल एरिया मे कुछ सडके मार्केटिंग बोर्ड बनाता है ओर कुछ हमारा महकमा बनाता है। हांसी-उमरा सडक का जिक माननीय सदस्य ने किया है, इसके बारे मे विभागी बकायदा इन्कवायरी करवायेगा और जो अधिकारी दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी।

**चौ० अर्जन सिंह:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूँ कि मेरे हलके में जो पी डब्ल्यू डी की सड़क है या मार्कटिंग बोर्ड की सड़क है, ये सड़क कागजों में ही रह रही है। हमारे यहां के आर जोन होने के कारण हजारों गाड़ियां रोज यहां से गुजरती हैं। कोई छोटी सी सड़क भी हमारे यहां नहीं जोड़ी गई है। किसी सड़क को बनाने में डेढ़ साल लग जाता है लेकिन टूटने में देर नहीं लगती। हमारे यहां की बी के डी रोड ठीक नहीं हुई है। ट्रालियां भर भर कर इन सड़कों से गुजरती हैं और इन ट्रालियों की वजह से रोज कोई न कोई सड़क टूट जाती है।

**कैप्टन अजय सिंह यादव:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूँ कि बी के डी रोड के लिए हमने बी और डी बेसिज पर कॉन्ट्रैक्ट की लेकिन कोई भी बिडर नहीं आया। अब हमने हुडको से लोन लेकर केस उनको भेज दिया है। बी के डी रोड जल्दी ठीक करवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, इनके एरियाज में क्वैरिज रोड है इसलिए दिक्कत आ रही है। इनके यहां की सड़कों से ट्रक इतने ओवर लोडिड होकर गुजरते हैं कि कोई भी सड़क बना दो वह टूट जाती है इसलिए या तो आर टी और के आफिसर्स से चैक करवाया जाए कि इन सड़कों से गाड़ियां ओवर लोडिड न जाएं। ओवर लोडिड गाड़ियों की वजह से हड़ी इन सड़कों की हालत खराब है। इनके एरियाज

मे ज्यादा क्वैरीज रोड है जिसकी वजह से हालत खराब है, अगर हम रिपेयर करवा भी देते हैं तब भी टूट जाती है।

**श्री अध्यक्ष:** कप्तान साहब, आप इसका स्पैसिफिके इन बढा दो।

**कैप्टन अजय सिंह यादव:** अध्यक्ष महोदय, इन सडको पर गाडियां 60-60 टन तक माल उठाकर चलती है जिसकी वजह से ये सडके टूट जाती है।

**श्रीमती गीता भुक्कल:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि न केवल कलायत में बल्कि पुरे हरियाणा में सडको का जला बिछा हुआ है। हमारे कलायत भाहर में मेन रेलवे रोड है उसाक काम 2006 में भुरु हुआ था। आज भी उसमें कभी डिवाइडर बन जाता है, कभी सडक बन जाती है कभी सडक टूट जाती है। एस्टीमैटस रिवाईज होने के बाद भी उसमें गढडे पडे हुए है। हमने लिखित में भी मंत्री महोदय जी को रिक्कायते की है क्योंकि वहां काफी पानी भरा रहता है जिसकी वजह से रोज एक्सीडेंट्स होते हैं और कई मौते भी होती है।

**कैप्टन अजय सिंह यादव:** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने कलायक हल्के की रेलवे रोड का जिक्र किया है, हम अधिकारियों से कहकर इस सडक की रिपेयर करवा देंगे।

**प्र० छतर पाल सिंह:** अध्यक्ष महोदय, जिला हिसार मे कैनाला गांव से दौलतपुर गांव तक 1990 मे पी डब्ल्यू डी (बी एण्ड आर) विभागी द्वारा कुछ लाख रुपये से आधी सडक को बनाया गया था लेकिन उस की कम्पली इन के उपर कोई काम नही किया गया। पिछले सै इन मे भी मैने यह सवाल किया था। जो पैसा लगा हुआ है वह बेकार जा रहा है, विलेजिज का लिंक जब तक पुरा नही होता, तब तक बसे उस पर नही चल सकती और उसका लोग फायदा नही उठा सकते।

**श्री अध्यक्ष:** पिछले सै इन मे आपने क्या सवाल किया था?

**प्र० छतर पाल सिंह:** अध्यक्ष महोदय, पिछले सै इन मे मैने सवाल किया था कि कैनाला से दौलतपुर जो सडक है वह अनकम्पलीट है।

**श्री अध्यक्ष:** उस समय आपको क्या जवाब मिला था?

**प्र० छतर पाल सिंह:** अध्यक्ष महोदय, इन्होने आ वासन दिया था कि उसको कम्पलीट करवाएंगे लेकिन अभी तक कम्पली इन का काम नही किया गया है।

**कैपटन अजय सिंह यादव:** अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी बताएंगे कि यह सडक नई है या पुरानी है।

**प्रो० छतर पाल सिंह:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि यह नई सड़क है।

**कैप्टन अजय सिंह यादव:** अध्यक्ष महोदय, जहां तक सड़क अधूरी होने का सवाल है, मेरी नालेज में नहीं है कि इन्होंने पिछले सै। न में इस सड़क का जिक्र किया हो। हम इसको चैक करवा लेंगे और अगर यह सड़क अधूरी बनी हुई है तो इसको पुरा करवा देंगे।

**श्री अध्यक्ष:** कैप्टन साहब, आप कैपेबल मंत्री हैं और आपकी टीम बड़ी कम्पिटेंट है। ये जो चारों तरफ सड़को की बात हो रही है। आनरेबल मैम्बरज के जो सुझाव हैं, उनकी जो प्रोब्लज हैं वह आप देखें। कोई मैम्बर कह रहा है कि उनकी सड़क 6 महीने में टूट जाती है कोई कह रहा है कि उनके यहां की सड़क पूरी नहीं हुई और कोई बाई पास के बारे में कह रहा है। आप पूरी तरह से मोनीटरिंग करके काइंडली पर्सनल अटैं। न लेकर इन सड़को को ठीक करवाएं।

**कैप्टन अजय सिंह यादव:** अध्यक्ष महोदय, हम मोनीटरिंग कर रहे हैं और हम पर्सनल अटैं। न लेकर इन सड़को को ठीक करवाएंगे।

**श्री उदय भान:** स्पीकर सर, पलवल से हसनपुर वाया रसूलपुर-बडौली सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत किया गया था, यह सड़क 6 महीने के अंदर ही

टूट गई। मैंने यह बात पिछले सै। इन के दौरान भी मंत्री जी के ध्यान में लाई थी और उस समय मंत्री जी ने अ. योर किया था कि प्रायरटी के आधार पर जल्दी ही इन सडको को ठीक करवा दिया जायेगा या दोबारा बनवा दिया जायेगा लेकिन अभी तक इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई। दूसरा जो रसूलपुर से हसनपुर रोड है वह भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। पहले इस सडक का निर्माण भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के तहत करवाये जाने की बात कही गई थी लेकिन अभी तक इस बारे में भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इन सडको को कब तक ठीक करवा दिया जायेगा?

**कैप्टन अजय सिंह यादव:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के तहत जिन सडको का निर्माण किया जाता है उनकी रिपेयर का पीरियड तीन साल का होता है। तीन साल के अंदर अगर सडक टूटती है तो उसकी रिपेयर संबंधित कंट्रैक्टर को करनी होती है। जहां तक पलवल से हसनपुर सडक की बात है हम इसको एग्जामिन करवाकर इसकी रिपेयर करवायेंगे और अगर जरूरत पडी तो हम इसको दोबारा भी बनवायेंगे। स्पीकर सर, उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है क्योंकि हमें पी एम जी एस वाई कार्यालय या नाबार्ड, जिससे भी हमें नई सडक बनवानी होती है, उनको कम्पलीट केस भेजना पडता है। जहां तक रिपेयर

की बात है, रिपेयर भी एकदम नहीं हो सकती क्योंकि उसके लिए भी कुछ आरम्भिक कार्यवाही करनी अपेक्षित होती है। मैं माननीय सदस्य को आवासन देना चाहूंगा कि हम इस सड़क को जल्दी से जल्दी रिपेयर करवायेंगे। दूसरा जो इन्होंने रसूलपुर हसनपुर रोड का जिक्र किया है हम इसको भी एग्जामिन करवाकर रिपेयर करवायेंगे।

**श्री रामफल चिडाना:** स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से गोहाना बाई पास की लेटैस्ट पोर्जी लाने के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि इसको कब तक बनावा दिया जायेगा?

**कैप्टन अजय सिंह यादव:** स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि गोहाना बाई पास का निर्माण ने नेशनल हाईवेज आथॉरिटी आफ इंडिया द्वारा किया जायेगा और इसका निर्माण कार्य वर्ष 2011 के अंत तक पूरा हो जायेगा।

**श्री रामफल चिडाना:** स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूँ कि ड्रेन नम्बर 8 बाई पास के ऊपर पुल कब तक बनवा दिया जायेगा?

**कैप्टन अजय सिंह यादव:** स्पीकर सर, इस प्रकार से मेरे लिए सभी माननीय सदस्यों को जवाब देना मुश्किल हो जायेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अनुरोध करूंगा

कि वे इसके लिए मुझे अलग से लिख कर दे दें तो मैं उनको वास्तविक स्थिती से अवगत करवा दूंगा। जहां तक ड्रेन नम्बर 8 पर बनने वाले पुल का संबंध है, उसका निर्माण मार्केटिंग बोर्ड द्वारा किया जायेगा।

**श्री राम कुमार गौतम:** स्पीकर सर, एक सडक बड छप्पर से पुठी तक है जिस पर पिछले लगभग सात साल से काम अधुरा पडा है। इस सडक का सवाल मैंने कई बार उठाया है लेकिन अभी तक भी उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। वह सडक काफी समय से ऐसी की ऐसी पडी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस सडक का निर्माण कार्य कब तक पुरा करवा दिया जायेगा?

**श्री अध्यक्ष:** गौतम जी, क्या आपने पहले भी इस बारे में सवाल पूछा था?

**श्रीराम कुमार गौतम:** जी सर, मैंने पहले भी इस बारे में सवाल पूछा था?

**श्री अध्यक्ष:** उस समय आपको इसका क्या जवाब दिया गया था?

**श्री राम कुमार गौतम:** स्पीकर सर, उस समय मुझे यह बताया गया था कि जिस ठेकेदार को उक्त सडक का काम सौपा गया था वह भाग गया है और सरकार द्वारा उसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। स्पीकर सर, मैं तो यही चाहता हूं कि



उस सडक का निर्माण जल्दी से जल्दी करवा दिया जाये क्योंकि उसके अण्डर कंस्ट्रक्शन होने से लोगों को बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है।

**कैप्टन अजय सिंह यादव:** स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हम एग्जामिन करवाकर भीध्र ही इस सडक को कम्पलीट करवा देंगे।

**श्री महेन्द्रग प्रताप सिंह:** अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह सवाल खास था लेकिन अब यह सडको का सवाल आम हो गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कुछ जानना चाहूंगा कि एक सुझाव भी देना चाहूंगा। जब से यह सरकार बनी है तब से हर विभागी के बजट में बेतहाशा वृद्धि हुई है। पी डब्ल्यू डी विभागी का बजट भी बहुत बढ़ा है और सरकार द्वारा बहुत सी सडके बनाने का प्रयास भी किया गया है। हाउस में इस सवाल के उपर खास चिंता जाहिर की गई है कि इतना बजट होने के बावजूद भी बहुत सी सडके अधूरी पडी है और जो बनी हुई है उनकी भी यही दिक्कत है कि वे भी टूटी पडी है। सभी सदस्यों को यही आकायत है कि सडके टूटी पडी है उनमें गडढे हो गये है। मैं अपने हल्के के बारे में तो इसलिए नहीं कहना चाहूंगा कि यह सवाल ही दूसरा था लेकिन स्थिती मेरे हल्के की भी ऐसी ही है। सडके बनने के कुछ दिन ही बाद टूट गई है चाहे वे प्रधानमंत्री सडक योजना की सडके हो या नाबार्ड की सडके हो। अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि इसके

लिए हाउस की या उच्च अधिकारियों की कमेटी बनाए जो इस मामले की जांच कर सके या सर्वे करके रिपोर्ट सौंप सके?

**कैप्टन अजय सिंह यादव:** अध्यक्ष महोदय, हाउस की चिंता वाजिब है। पिछले साल बारिश बहुत हुई थी इसलिए सड़के ज्यादा टूट गई हैं। जहां तक कमेटी की बात है, इस मामले में हम हाउस कमेटी की बताए अधिकारी स्तर पर चैक करवा लेंगे। जहां जहां ऐसी सड़के हैं जिनकी हालत बहुत खराब है उनको हम चैक करवा लेंगे। अगर सैन्स आफ हाउस होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हाउस कमेटी भी बना दें और वह चैक कर लें लेकिन मैं समझता हूँ कि उसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 2009-10 में हमने तकरीबन 750 करोड़ रुपये सरकार से मांगे हैं, बजट में प्राविजन किया जाये ताकि हम सड़को की रिपेयर कर सकें लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारे पास कुछ फण्डज की कमी थी जिसके कारण इस साल में हम सारी सड़को की रिपेयर नहीं कर सके। जितना काम इस योजना में सड़को के उपर हुआ है उतना आज से पहले कभी नहीं हुआ चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हो चाहे नाबार्ड के तहत हो। जहां तक सवाल है सड़को के टूटने का, तो जहां जहां ऐसी रिपोर्ट आयेगी उनको हम चैक करवायेंगे और जांच भी करवा लेंगे और जहां भी कमी होगी हम उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही भी करेंगे।

**बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला):** अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से माननीय सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की सड़कों के बारे में प्रश्न उठाये और माननीय मंत्री जी ने सभी क्षेत्रों की जो जानकारी इस समय उपलब्ध थी वह सदन के सामने रखी है। माननीय साथी चौधरी महेन्द्रग प्रताप सिंह जी ने भी यह प्रश्न उठाया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पिछले 4 साल में बी एण्ड आर की 551 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण करवाया है जो अपने आप में एक रिकार्ड है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि वर्ष 2008-09 में जैसा कि मंत्री जी ने बताया जो इस समय चालू साल है, केवल कंस्ट्रक्शन और रिपेयर पर तकरीबन 800 करोड़ रुपये सरकार खर्च कर रही है। हमारे विपक्ष और पक्ष के साथियों ने जो प्रश्न उठाये हैं उनकी बात वाजिब है। इस समय हमारे पास 734 नई सड़कों की मांग है जिनकी लम्बाई 2464 किलोमीटर है। अगर सरकार इन सारी मांगों को मानती है तो उसके लिए कम से कम 600 या 700 करोड़ रुपये का खर्च केवल रिपेयर और इम्प्रूवमेंट पर आयेगा। हमारे पास सीमित साधन हैं उसके बावजूद भी पी डब्ल्यू डी (बी एण्ड आर) जिस प्रकार से पिछले चार साल से काम कर रहा है वह सराहनीय है। चाहे सड़कों की बात हो या रेलवे ब्रिजिज की बात हो मुझे नहीं लगता कि हाउस कमेटी के गठन की कोई जरूरत है। ओवरलोड की वजह से या क्वालिटी की कमी की वजह से सड़कें टूट जाती हैं

तो इस मामले में जिस भी साथी की कोई रिपोर्ट है वह लिखकर माननीय मंत्री जी को भेज दें हम जांच करवायेंगे और जांच रिपोर्ट की एक कॉपी माननीय साथी को भी भेज दी जायेगी।

**श्री अध्यक्ष:** मंत्री जी, इसमें जनरली जो बात आई है उसमें पूवर क्वालिटी की बात है, मैम्बर्ज की तरफ से कहा गया है कि बनने के साथ ही सड़के टूट जाती है। इसके साथ ही रोडज को कम्पलीट नहीं किया उन ठेकेदारों के खिलाफ क्या ऐक्शन लिया गया है। हाउस के मैम्बर्ज की चिंता बड़ी वाजिब है क्योंकि पूरा प्रदेश सड़कों के ऊपर रोजना निकलता है। मंत्री जी, आप अपने डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मांगें या डी सीज से रिपोर्ट मांगें कि कहां पर क्या क्या कमी है। 15 फरवरी से तारकोल बिछाने का काम शुरू हो जाएगा और अब दो या अढ़ाई महीने का समय इसमें रह गया है। मंत्री जी, इसमें ऐसा है कि आनरेबल मैम्बर्ज की जो चिंता है वह दूर की जानी चाहिए। आप अपने सोर्स से यह रिपोर्ट मंगवाएं कि कहां कहां सड़कों की कम्पलीटेशन बाकी है और कहां कहां सड़कों की मेंटीनेंस बाकी है। नई सड़कों को बनाने की बजाये अगर आप रिपेयर करवाएं तो it would be more better. नई सड़कों का काम बन्द करके जो सड़के बनी हुई हैं उनकी रिपेयर पर आप खर्च करें, यह काम आपके डिपार्टमेंट का है।

**कैप्टन अजय सिंह यादव:** अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस में पहले ही यह बता चुका हूँ कि वर्ष 2009-10 के लिए हमने सरकार से 750 करोड़ रुपये सड़कों की रिपेयर करने के लिए

मांगे है। स्पीकर सर, मैं मैम्बरज की मांग से सहमत हूँ कि नई सडके न बनाई जाए हम इस समय कोई नई सडक नहीं बना रहे हैं उनका काम बंद करके एक ही काम कर रहे हैं कि जो सडके टूटी हुई है उनकी रिपेयर की जाए। कुछ सडके ऐसी हैं जो ज्यादा टूटी हुई हैं लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सब जगह सडके टूटी हुई हो। कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ ऐसा हो रहा है हम उनकी जांच करवा लेंगे।

**श्री अध्यक्ष:** मंत्री जी, आप अपने ऐडमिनिस्ट्रेटिव से पता करे और जहाँ रिपेयर की जरूरत है वह करवाएं। (विधन)

### **Lining of Ditch Drain Safidon**

**\*1083. Shri Bachna Singh Arya:** Will the Irrigation Minister be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Hon'ble Chief Minister had accepted the demand for lining the ditch of Safidon City in the public meeting held on 11<sup>th</sup> June, 2006; and

(b) whether it is also a fact that the amount of Rs. 2 crore 80 lacs has been sanctioned in meeting of flood control Board; if so, the time by which the said amount is likely to be released?

### **Irrigation minister (Capt. Ajay Singh Yadav):**

(a) Sir, the ditch drain in Safidon City has been already lined.

(b) no Sir, The funds are to be allocated by the Flood Control Board, the next meeting of which is to be held shortly.

**श्री बचन सिंह आर्य:** अध्यक्ष महोदय, यह जो सफीदो ड्रेन है इसको गन्दा नाला भी कहते हैं। मेरा यह सवाल इरिगे टन डिपार्टमेंट से नहीं बल्कि पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित है। सफीदो भाहर के अंदर से यह नाला जाता है जिसे गंदा नाला कहते हैं। यह नाला सारे भाहर के बीच से जाता है। मेरा यह सवाल सिंचाई विभाग से संबंधित नहीं है पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर जी को मैंने इसके बारे में लिख कर भेजा था और इसके लिए 2 करोड़ 80 लाख रुपये सीवरेज को पक्का करने के लिए रिलीज करने थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी 11 जून, 2006 को इसे मंजूर करके आये थे। मुझे विदित हुआ रेट्स बढ़ गए और 3 करोड़ 10 लाख रुपये के एस्टीमेट्स बनाकर पब्लिक हैल्थ ने भेजे थे। मैंने इसके बारे में पता किया था। क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह पैसा स्वीकृत हो चुका है और यदि स्वीकृत हो चुका है तो यह पैसा कब तक रिलीज हो जाएगा।

**बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला):** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह प्र न इरीगे टन मिनिस्टर जी के पास फ्लड कंट्रोल प्रोग्राम के तहत भेजा गया था। फ्लड कंट्रोल प्रोग्राम के चेयरमैन माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और इनका विभाग इस काम को देखता है। इस पैसे के बारे में मंत्रणा पूरी हो चुकी है और माननीय इरीगे टन मंत्री जी से भी बात हुई है। फ्लड

कण्ट्रोल बोर्ड की मीटिंग फरवरी में होगी ओर मुझे अनुमान है कि इसी मितिग मे यह पैसा मंजूर हो जाएगा। बहुत जल्दी ही इसका काम भुरु हो जाएगा।

**श्री बचन सिंह आर्य:** स्पीकर सर, मेरा निवेदन है कि पहले भी फल्ट कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग मे पैसा मंजूर हो चुका था। अध्यक्ष महोदय, मै माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह पैसा कब तक रिलीज हो पाएगा?

**कैप्टन अजय सिंह यादव:** अध्यक्ष महोदय, मै अपने माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि बजट का प्रोविजन फल्ट कंट्रोल बोर्ड नहीं कर पाया था। फल्ट कंट्रोल बोर्ड की अगली मीटिंग होने वाल है उसमे हम इसको ले लेंगे।

**तारांकित प्र न संख्या 1042**

(इस समय माननीय सदस्य श्री राधे भयाम भार्मा अमर सदन मे उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्र न पूछा नहीं गया।)

**तारांकित प्र न संख्या 1110**

(इस समय माननीय सदस्य श्री धर्मबीर गाबा सदन मे उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्र न पूछा नहीं गया।)

**तारांकित प्र न संख्या 1109**

(इस समय माननीय सदस्य श्री नरे । यादव सदन मे उपस्थित  
नही थे इसलिए यह प्र न पूछा नही गया।)

### **Bridge on Yamuna River**

**\*1122. Sh Udaio Bhan:** Will the P.W.D (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a bridge on the Yamuna river near Hassanpur; if so, the details thereof?

**Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav):** No, Sir,.

**श्री उदय भान:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 18 दिसम्बर, 2005 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने होडल के अंदर इस पुल की धोशणा की थी और इसका सर्वे हुआ था। हसनपुर उंटासानी घाट ओर मालनघाट है। पहले उंटासानी घाट मे सर्वे हुआ था तो इन्होने नॉट फिजिबल की रिपोर्ट दी थी। फिर इस बारे मे कहा गया कि मालन घाट में उसको बनाया जाएगा। मंत्री जी ने भी कहा था कि इस बारे मे विचार कर रहे है और इसको बनवाएंगे। इन्होने यह भी बताया था कि इन्होने उत्तर प्रदे । सरकार से इस बारे मे लिखा पढी की हुई है लेकिन अब इन्होने एकदम इस बारे मे 'न' में जवाब दे दिया है। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बारे मे इनके द्वारा क्या कार्यवाही हुई है ओर अब इसकी लेटस्ट पोजी ।न क्या है?



**कैप्टन अजय सिंह यादव:** अध्यक्ष महोदय, उदय भान जी का जो प्र न है इस बारे में मैं इनको बताना चाहूंगा कि हम वहां पर पनटूम टैम्परेरी ब्रिज लगाते हैं जिसको हम 15 जून से 15 अक्टूबर तक हटा लेते हैं क्योंकि वहां पर पानी बहुत आ जाता है। अध्यक्ष महोदय, जहां की ये बात कर रहे हैं वहां से 24 किलोमीटर दूरी पर यूपी के एरिया में मथुरा के पास भी ब्रिज है। इनकी यह बात सही है कि इनके वहां पर बड़ी भारी दिक्कत है और इस ब्रिज को बनाने में तकरीबन 32.65 करोड़ रुपये लगेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारे सैक्रेटरी ने 31.1.2009 को यूपी गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी थी। इसमें दिक्कत यह है कि हरियाणा में अढाई किलोमीटर की अप्रोच रोड नहीं बनी हुई है और दूसरी तरफ भी उनके एरिया में 2.40 किलोमीटर में भी अप्रोच रोड नहीं बनी हुई है। हम बकायदा इसकी फिजिबल रिपोर्ट ले रहे हैं और हमने बकायदा यूपी गवर्नमेंट को भी चिट्ठी लिखी हुई है कि वे बी डी और बेसिज पर 50-50 भोयर के हिसाब से कर लें। अगर उनकी तरफ से स्वीकृति मिल जाती है तो हम आगे की कार्यवाही करेंगे।

**श्री उदय भान:** अध्यक्ष महोदय, 18 दिसम्बर, 2005 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पुल को बनाने के बारे में घोषणा की थी और यह बहुत ही जरूरी पुल है। मथुरा वहां से 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। अगर दूसरी साईड से जाए तो सैंकडो किलोमीटर का चक्कर काट कर जाना पड़ता है। इसके अलावा पलवल साईड से 50-60 किलोमीटर का चक्कर पड़ता है। अध्यक्ष

महोदय, यह हसनपुर से सीधा अलीगढ का रोड है। अगर यह पुल बन जाता है तो इससे दोनो प्रदे गो को हर तरफ से बहुत लाभ होगा। अध्यक्ष महोदय, खानापूरति करने के लिए चिटठी लिखी है। इन्होने पिछली तीन सालो मे कुछ नही किया आगे ये किस तरह से इस पर कुछ कर पायेंगे? इस पुल को बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी की घोशणा है। इस बारे मे लापरवाही क्यों बरती गई है और इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है?

**श्री अध्यक्ष:** यह लापरवाही की बात नहीं है, आप स्पैसिफिक प्र न पूछें।

**श्री उदय भान:** अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह बहुत ही आव यक पुल है। इस बारे मे मुख्यमंत्री जी ने घोशणा की थी और उसके बनाने के बारे मे आ वासन भी दिया था।

**कैप्टन अजय सिंह यादव:** अध्यक्ष महोदय, मैने पहले भी बताया है कि हम वहां पर पनटूम टैम्परेरी ब्रिज लगाते है और 15 जून से 15 अक्टूबर के बीच मे इसको उठा लेते है। इनकी जो मांग है वह बिल्कुल वाजिब है कि वहां पर ब्रिज होना चाहिए। इनकी इस जरूरत को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने यू पी गवर्नमेंट को बकायदा चिटठी लिखी है कि इस की बी और टी लैवल पर फिजिब्लिटी स्टडी ओर डी पी आर रिक्वायर्ड है। हमने यू पी गवर्नमेंट को कहा है कि वे इसके लिए अपनी कन्फ्रैस दे कि इसकी जो टोटल कॉस्ट है उसका 50 प्रति ात भोयर वे देंगे और

50 प्रति त भोयर हम देंगे। जैसे ही इस बारे में उनकी स्वीकृती आ जाएगी तो इस बारे में हम कार्यवाही करेंगे।

**Up-gradation of 132 KV Power Station with 25 MVA  
Transformer**

**\*1101. Maj Nirpender Singh Sangwan:** Will the Power be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade 132 KV Power Station with 25 MVA transformer at village Atela in Charkhi Dadri; and

(b) the time by which the 33 KV Power Station at village Chappar will start functioning?

**Power Minister (Sh Randeep Singh Surjewala):**

(a) Augmentation of 132 KV Sub Station Atela Kalan with 1x20/25 MVA, 132/33 KV transformer is an approved work at an essential cost of Rs. 200 lac. I will tell the Hon'ble Member that as on today it stands commissioned. Although, the reply is that it will be commissioned by 20<sup>th</sup> Februday, 2009 but we have already commissioned it.

(b) 33 KV Sub Station Chappar with 10 MVA, 33/11 KV transformer stands commissioned since 3/2008 at no load. Speaker Sir, load now will be put by the end of this month as the earlier from where the connectivity had to come.

**Maj. Nirpender Singh Sangwan;** Speaker Sir, though the transformer has been upgraded but the problem

remained the same. it needs to be uplifted and a control room to be made there for it. Until the control room is not made it remains idle standing there. The upgradation is made only 16 MVA to 25 MVA. rather than from 16 MVA plus 25 MVA.

### तारांकित प्र न संख्या 1173

(इस समय माननीय सदस्य श्री सोमवीर सिंह सदन मे उपस्थित नही थे इसलिए यह प्र न पूछा नही गया)

#### Installation of Tubewells

**\*1040. Sh Niram Singh:** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state the districtwise number of tubewells installed in Haryana Stte during the leat three years together with the number of tubewells which have failed during the said period?

#### **Power Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala):**

Sir, a statement is placed on the table of the House.

#### Statement

Sr No.	Name of District	No. of tubewells drilled during 2005-08	No of tubewells drilled and failed within the period 2005-08
1	Ambala	276	8
2	Bhiwani	57	0
3	Faridabad	65	0

4	Fatehabad	16	0
5	Gurgaon	167	0
6	Hisar	0	0
7	Jhajjar	36	1
8	Jind	63	0
9	Kaithal	210	0
10	Karnal	194	0
11	Kurukshetra	117	0
12	Mewat	200	15
13	Mohindergarh	296	20
14	Palwal	160	27
15	Panchkula	51	0
16	Panipat	175	1
17	rewari	140	23
18	Rohtak	0	0
19	Sirsa	76	0
20	Sonepat	103	0
21	Yamunanagar	244	5
	<b>Total</b>	<b>2646</b>	<b>100</b>

**श्री निर्मल सिंह:** स्पीकर सर, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि अम्बाला में 8 ट्यूबवैल अभी खराब है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इनको दोबारा से चालू करने में कितना समय लग जाता है? जल्दी ही इनकी रिपेयर करवानी चाहिए क्योंकि पीने का पानी बहुत जरूरत की चीज है तो क्या मंत्री जी इस बारे में ध्यान देंगे?

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला:** स्पीकर सर, माननीय सदस्य की चिंता ठीक है कि इनके विधान सभा क्षेत्र नग्गल में तीन ट्यूबवैल्ज ऐसे हैं जो वाटर लेवल नीचे जाने की वजह से खराब है। एक तो वीटा में ट्यूबवैल है इसका पानी नीचे चला गया है जिसकी वजह से यह ड्राई हो गया है। एक मंछौडा में जिसे चन्द्रपुरी भी कहते हैं, ट्यूबवैल है, इसमें भी वाटर लेवल नीचे जाने के कारण पानी का डिस्चार्ज कम हो गया था। इसी तरह से एक मुनहेडी में ट्यूबवैल था यह भी ड्राई हो गया था। स्पीकर सर, इस बैल्ट के अंदर वाटर लेवल जरूर नीचे जा रहा है। इनकी कांस्टीच्युएंसी में पुराने करीब 14-15 ट्यूबवैल्ज हमारे नोटिस में ऐसे आए थे जो धीरे धीरे सात आठ दस साल चलकर वाटर लेवल नीचे जाने की वजह से खराब हो गये थे। हमने इनके लिए आल्टरनेटिव प्रावधान करने का निर्णय लिया है। जब माननीय वित्त मंत्री जी अपना बजट पेश करेंगे तो उससे पहले माननीय सदस्य से इस बारे में हम राय ले लेंगे और इनके मुताबिक जहां पर पानी ठीक होगा वहां पर हम ट्यूबवैल मंजूर कर देंगे। वैसे

हम अपनी तरफ से भी सर्वे करवा लेंगे और टैस्ट करवा लेंगे। जहां पर लेवल ठीक होगा वहां पर हम इनके क्षे? में ऐडी गनल ट्यूबवैल मंजूर कर देंगे।

**श्री निर्मल सिंह:** स्पीकर सर, आठ ट्यूबवैल का जिक्र किया गया है इनमें से कई ट्यूबवैल ऐसे हैं जो लगते ही खराब हो गए हैं। वाटर लेवल नीचे जाने की वजह से यह बहुत पुराने ट्यूबवैल होने की वजह से तो खराब हैं ही लेकिन कई ट्यूबवैल ऐसे भी हैं जो लगते ही खराब हो गए हैं।

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला:** स्पीकर सर, इस प्रश्न आने के बाद मैंने इसके बारे में जांच करवायी थी। हमें पता चला है कि वहां पर पानी का स्तर नीचे चला गया है। फिर भी माननीय सदस्य के नोटिस में यदि कोई और विशय है तो वे हमें लिखकर दे दें, हम उसकी जांच करवा लेंगे।

**श्री फूल चन्द मुलाना:** स्पीकर सर, तीन साल में 2646 ट्यूबवैल इस सरकार ने लगवाए हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि 2000 से लेकर 2004-05 तक इस सरकार के बनने से पहले तक कितने ट्यूबवैलज लगे थे?

**श्री अध्यक्ष:** मुलाना साहब, इसके बारे में जानकारी लेकर क्या करेंगे?

**श्री फूल चन्द मुलाना:** ठीक है सर।

**Mr Speaker:** Hon'ble Member, Question Hour is over.

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित  
प्र नो के लिखित उत्तर

**Payment of Outstanding Electricity Bills**

**\*1088 Dr. Sushil Indora:** Will the Power Minister be please to state:

(a) whether it is a fact that the electricity bills are issued by adding the outstanding amount of electricity bill already deposited; and

(b) whether any fee is deposited to get the said bills rectified?

**बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला):**

(क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

**Construction of PHC at Bir-Pipli**

**\*1099. Sh. Ramesh Gupta:** Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Primary Health Centre on the land of Panchayat of Bir-Pipli at Pipli; if so, the time by which the work will be started thereon?



स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देवी): हां, श्रीमान् जी, ग्राम पंचायत द्वारा उपायुक्त भूमि उपलब्ध करवाए जाने पर निर्माण कार्य भुरु कर दिया जाएगा।

**Proper Drainage of Flood/Storm Water in Kalayat Town**

**\*1126. Smt. Geeta Bhukkal:** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government for proper drainage of flood/storm water in Kalayat town?

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): नहीं, श्रीमान् जी।

**Number of Government Highet Secondary Schools**

**\*1131. I.G. Sher Singh:** Will the Education Minister be pleased to state the number of Government Higher Secondary Schools functioning in Jind District togetherwith number of schools which have Science and Commerce Streams?

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता): श्रीमान् जी, जींद जिले मे 85 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है, जिनमे से 12 विद्यालय विज्ञान संकाय के तथा 10 विद्यालय वाणिज्य संकाय के है।

अनुबन्ध 'ए'

जींद जिले के विज्ञान संकाय के राजकीय वरिष्ठ  
माध्यमिक विद्यालयों के नाम:

विज्ञान संकाय के विद्यालय	वाणिज्य संकाय के विद्यालय
रा० माडल संस्कृति व० मा० वि० बेलरखां	रा० माडल संस्कृति व० मा० वि० बेलरखां
रा० व० मा० वि० ईक्कस	रा० व० मा० वि० ईक्कस
रा० क० व० मा० वि०, जींद	रा० क० व० मा० वि०, जींद
रा० व० मा० वि० जुलाना	रा० व० मा० वि० जुलाना
रा० व० मा० वि० नरवाना	रा० व० मा० वि० नरवाना
रा० व० मा० वि० पिल्लु खेडा	रा० व० मा० वि० पिल्लु खेडा
रा० व० मा० वि० उचाना मण्डी	रा० व० मा० वि० उचाना मण्डी
रा० व० मा० वि० दनौदा	रा० व० मा० वि० दनौदा
रा० व० मा० वि० हाट	
रा० क० व० मा० वि० नरवाना	

अनुबन्ध 'बी'

## शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

(i) छठी से बाहरवीं तक सभी कक्षाओं में सैमेस्टर प्रणाली का लागू होना, जिसके परिणामस्वरूप पढाई का बोझ कम हुआ है व सारा वर्ष पढाई में निरन्तरता बन पाई है। अनुभव के आधार पर सैमेस्टर प्रणाली में सुधार करने के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा को समाप्त कर दिया गया है। अब प्रथम सैमेस्टर की परीक्षा में भी संक्षिप्त वर्णनात्मक प्रश्न शामिल किए गए हैं।

(ii) अध्यापकों के सभी रिक्त पदों पर अतिथि अध्यापक लगाए गए हैं।

(iii) राज्य में लगभग 10000 विद्यालयों और महाविद्यालयों में एजुसैट की स्थापना की गई है।

(iv) कार्यपुस्तिकाओं की सहायता से अध्यापकों की आधुनिक प्रणालियों को आरम्भ किया गया है।

(v) सरकारी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों की सहायता के लिए मौलिक स्तर पर लगभग 22 लाख विद्यार्थियों को पुस्तकें व कार्यपुस्तिकाएं मुफ्त प्रदान की गई हैं।

(vi) भौक्षणिक सत्र 2008-09 के दूसरे सैमेस्टर से परियोजना आधारित शिक्षा आरम्भ की गयी है।

(vii) आगामी भौक्षणिक सत्र से 'सामान्य ज्ञान' विषय लागू किया गया है।

(viii) अध्यापको की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा आरम्भ की गई है। इस परीक्षा का सफल आयोजन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा किया गया था जिसमें 1.60 लाख उम्मीदवार बैठे और 32000 उम्मीदवारों को उत्तीर्ण घोषित किया गया।

(ix) विद्यालयों की मूलभूत सुविधाओं के लिए पर्याप्त राशि प्रदान की गई।

(x) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मासिक वजीफे व एकमुक्त भत्ते की योजना आरम्भ की गई है। इससे लगभग 8.5 लाख विद्यार्थी लाभ उठा रहे हैं।

(xi) बाह्य एजेंसियों की सहायता से लगभग 1100 विद्यालयों में विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है।

(xii) आगामी भौक्षणिक सत्र से 213 विद्यालयों में व्यापक कम्प्यूटर शिक्षा को चरणबद्ध तरीके से आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

(xiii) अध्यापको की स्थानान्तरण नीति में सुधार किया गया है। अब अध्यापको का न्यूनतम ठहराव का समय 3 वर्ष की अपेक्षा 5 वर्ष कर दिया गया है।

### अनुबन्ध 'सी'

राज्य सरकार द्वारा विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण

1. "एजुसैट" के माध्यम से ग्याहरवीं तथा बाहरवीं कक्षा के विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों के विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन व्याख्यान प्रसारित किए जा रहे हैं।

2. 'एजुसैट' के माध्यम से विज्ञान विषय के ग्याहरवीं तथा बाहरवीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के लिए प्रतिदिन गहन कोचिंग प्रदान की जाती है। यह कोचिंग कार्यक्रम 'उत्कर्ष सोसाईटी' द्वारा एक प्रसिद्ध भौक्षणिक संस्था के सहयोग से विकसित किया गया है तथा बड़े उत्साह से विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण किया जा रहा है।

3. विशेष रूप से सुविधाओं की चरणबद्ध स्तरोन्नति के लिए चयनित 213 विद्यालयों को 11.86 करोड़ रुपये विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए सरकार द्वारा वितरित किए गए हैं।

4. प्रयोग ालाओ के उपकरणे की खरीद के लिए 40000 रुपये प्रति विज्ञान संकाय वरिष्ठ माध्यमिक तथा 17397 रुपये प्रति गैर विज्ञान संकाय वरिष्ठ माध्यमिक व उच्च विद्यालय की दर से कुल 6.15 करोड रुपए वितरित किए गए है।

### **Adulteration of Milk**

**\*1137. Dr. Sita Ram:** Will the Health Minister be pleased to state:

(a) the district wise and year wise number of cases of adulteration in milk registered in the State since April, 2006 till date, together with the fate of the registered cases; and

(b) the steps taken by the Health Department to check the adulteration in milk together with the total number of samples taken in this regard?

स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देवी): श्रीमान् जी, सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है:'

(क) स्वास्थ्य विभागी द्वारा अप्रैल 2006 से दिसम्बर, 2008 तक दुध के कुल 683 नमून लिये गए, 224 नमूने अपमिश्रित पाए गए तथा इन केसो के बारे मुकदमा दायर किया हुआ है। यह सभी केस न्यायालय के विचाराधीन है।

जिलावार। तथा वर्ष वार ब्यौरा निम्न प्रकार से है:

क्रम संख्या	जिले का नाम	वर्ष वार लिए गए सैम्पलो की संख्या			अपमिश्रित पाए गए नमूनो की संख्या		
		2006	2007	2008	2006	2007	2008
1	अम्बाला	12	14	6		02	02
	भिवानी	06	23	38	02	05	12
	फतेहाबाद	02	02	02	02	02	02
	फरीदाबाद	17	02	07	04	01	01
	गुडगांव	26	30	18	09	12	08
	हिसार	23	10	38	02	01	04
	झज्जर	02	02	02	02	02	02
	जीन्द	02	04	07		03	03
	करनाल	02	04	07	02	04	07
	कैथल	44	23	32	05	06	06
	कुरुक्षेत्र	05	13	12	05	05	00
	मेवात			02			01
	नारनौल	01	01	02	01	01	02

	पानीपत	19	25	15	03	03	02
	पंचकूला	15	13	18	02	09	03
	रिवाडी	02	07	01	02	07	01
	रोहतक	01	11	02	01	11	02
	सोनीपत	02	15	02	02	15	02
	सिरसा	08	15	25	03	04	07
	यमुनानगर	13	14	17	05	03	09
	<b>कुल</b>		<b>683</b>			<b>224</b>	

(ख) विभागी ने अधिक से अधिक सैम्पलिंग तथा चैकिंग के लिए कदम उठाए हैं। प्रत्येक जिले में आठ उपसिविल सर्जन के पद स्वीकृत किए गए हैं। सभी उपसिविल सर्जन को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के तहत लोकल हेल्थ आथारिटी अधिसूचित किया गया है। इससे पहले केवल एक प्रोग्राम अधिकारी यानि जिला स्वास्थ्य अधिकारी इस कार्य को करता था।

### **Free Technical Education for Orphan Children**

**\*1192. Smt Sunita Singh:** Will the Technical Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration for the Government to provide



free Technical Education to the 10<sup>th</sup> Class passed orphan children; if so, the details thereof?

भाहरी विकास मंत्री (श्रीमान् ए सी चौधरी): श्रीमान् जी, नहीं।

### **Unauthorised Colonies in M.C. Faridabad**

**\*1150 Sh. Mahendra Partap Singh:** Will the Urban Local Boadies Minister be pleased to state:

(a) the number of unauthorized colonies in the area of Faridabad Municipal Corporation; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to regularize the above said colonies; if so, the time by which these colonies will be regularized?

भाहरी विकास मंत्री (श्रीमान् ए सी चौधरी):

(क) नगर निगम फरीदाबाद क्षेत्र में 51 अनाधिकृत कालोनियां चिन्हित की गयी हैं।

(ख) वर्ष 2006 में 51 अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था। परंतु माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा के CWP No. 1006 of 2007 & 17002/2006 में पारित निर्देशानुसार, अब से कोई भी कालोनी नियमित नहीं की जाएगी यदि वह सक्षम प्राधिकारी की वांछित स्वीकृति एवम् माननीय उच्च न्यायालय का अनुमोदन प्राप्त

किए बिना बनाई गई हो। मामला अभी तक न्यायालय के विचाराधीन है।

### **Opening an I.T.I at Madlaudha**

**\*1159. Smt. Raj Rani Poonam:** Will the Industrail Training & Vocational Education Minister be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open an I.T.I at Madlaudha; and

(b) if so, the time by which it is likely to be opened?

**भाहरी विकास मंत्री (श्री ए सी चौधरी):** हां, श्रीमान् जी।

(क) मतलौडा मे आई टी आई खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) इस समय आई टी आई खोलने की सीमा दी जानी सम्भव नही है।

### **Construction of Roads**

**\*1185. Sh. Dinesh Kaushik:** Will the Agriculture Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct following roads:-

(i) from Sanch-Sirsal road to purchase centre via Dera Baldev Singh Habri;

(ii) from Habri Canal Rest House to Dera Sisha Singh Nishoria; and

(iii) from village Ahun to Sangroli and Sangroli to village Pharal?

कृषि मंत्री (सरदार एच एस चटठा): नहीं, श्रीमान् जी।

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

**142. Sh. Naresh Yadav:** Will the Agriculture Minister be pleased to state;

(a) the number of roads constructed by the Haryana State Agricultural Marketing Board in Haryana during the period from 2005 to 2008.

(b) the number of roads for which sanction has been accorded which were under construction togetherwith the dcriteria for construction of roads; and

(c) the number of roads repaired by the marketing board during the year 2005 to 2008 togetherwith the details of the expenditure incurred thereon?

कृषि मंत्री (सरदार एच एस चटठा): श्रीमान् जी।

(क) हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वर्ष 2005 से 2008 के दौरान 551 सडको का निर्माण किया गया है, तथा

(ख) वर्ष 2005 से 2008 तक 702 नई सडको स्वीकृत की गई है। सडको के निर्माण बारे मापदण्ड अनुलग्नक 'क' पर उपलब्ध है।

(ग) वर्ष 2005 से 2008 के दौरान 1097 सडको की मरम्मत की गई है और इन सडको पर 149.10 करोड रुपये की राशि खर्च की गई है। जिलावार। संक्षिप्त विवरण अनुलग्नक 'ख' पर उपलब्ध है।

### अनुलग्नक 'ख'

सडको की नीति निम्नलिखित है:-

1. बोर्ड क्षेत्र की आवकतानुसार ग्रामीण पहुंच सडको का निर्माण कृषि मंत्री / मुख्यमंत्री महोदय की स्वीकृती उपरान्त करेगा।

2. बोर्ड माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा घोशित सडको का निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ करेगा तथा इसकी सूचना सरकार को भेज देगा।

3. बोर्ड उन्ही सडको का निर्माण करेगा जहां कम से कम 5 करड चौडा रास्ता उपलब्ध हो। जहां रास्ता 5 करम से कम हो और सडक बनानी जरुरी हो, वहां भूमि साथ लगती भूमि मालिको से मुफ्त प्राप्त की जायेगी। यद्यपि विशेष परिस्थितयों मे सरकार से इस मामले में ढील प्राप्त की जा सकती है।

4. सडको के निर्माण पर पट्टी कार्य बोर्ड द्वारा अपने फण्ड से करवाया जायेगा।

5. बोर्ड द्वारा स्कूल, मंदिर, मस्जिद तथा धर्म माला को जाने वाली सडको का निर्माण नहीं करवाया जायेगा।

6. बोर्ड द्वारा भाम मान घाट की ओर जाने वाली सडको का निर्माण नहीं करवाया जायेगा।

7. गांव की आंतरिक सडके, फिरनी सडको और रिंग बांधो का निर्माण विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा करवाया जायेगा।

8. तालाब के साथ लगती पहुंच/ ग्रामीण सडको के लिए रिटेनिंग वाल विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा करवाई जायेगी।

9. अन्तर्राज्यीय सडको का निर्माण लोक निर्माण विभागी (भवन व सडके) द्वारा करवाया जायेगा।

10. बोर्ड/मार्किट कमेटियो द्वारा निर्मित सडको की समयबद्ध मुरम्मत का कार्य बोर्ड द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार किया जायेगा।

**अनुलग्नक 'ख'**

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वर्ष 2005 से 2008 के दौरान पूर्ण की गई सडको की वि शेष मुरम्मत।

क्रम संख्या	जिला	सडको की संख्या	लम्बाई किलोमीटर में	खर्चा लाखों में
1	अम्बाला	47	107.54	335.36
2	भिवानी	61	146.73	829.86
3	फरीदाबाद तथा पलवल	58	89.80	1047.07
4	फतेहाबाद	127	287.45	1468.65
5	गुडगांव	18	43.94	430.64
6	हिसार	47	135.02	777.35
7	झज्जर	19	47.14	464.68
8	जींद	66	177.10	1169.28
9	कैथल	107	195.77	975.21
10	करनाल	85	193.96	1456.25
11	कुरुक्षेत्र	137	222.19	1593.87

12	महेन्द्रगढ	12	26.17	153.96
13	मेवात	11	23.39	126.10
14	पानीपत	28	62.68	573.70
15	पंचकूला	16	20.01	69.82
16	रिवाडी	27	52.63	340.79
17	रोहतक	32	78.71	736.60
18	सिरसा	115	253.75	1397.47
19	सोनीपत	50	127.03	607.64
20	यमुनानगर	34	55.70	355.68
		1097	2346.71	14909. 98

**Buses Remained off the Roads**

**144 Sh. Karan Singh Dalal:** Will the Transport Minister be pleased to state the depotwise and monthwise number of Haryana Roadways Buses alongwith the number of days for which they remained off the roads during the year 2008-09 till date due to non-availability of staff or non-availability of tyre-tubes separately?

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता): निम्नलिखित अनुसूचियां विधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत हैं:—

(क) वर्ष 2008—09 (अब तक) में हरियाणा रोडवेज बसों की डिपोवार तथा मासवार संख्या

(ख) अप्रैल 2008 से जनवरी 2009, (अब तक) अमले की कमी के कारण मार्ग पर नहीं भेजी गई बसों का ब्यौरा।

(ग) अप्रैल 08 से जनवरी 09 (अब तक) टायर ट्यूब की कमी के कारण मार्ग पर नहीं भेजी गई बसों का ब्यौरा।

(घ) हरियाणा राज्य परिवहन के आगारों में मार्ग पर नहीं भेजे गये औसत वाहनो का ब्यौरा।



अनुसूचि "क"

वर्ष 2008-09 (अब तक) में हरियाणा रोडवेज बसों की डिपोवार तथा मासवार संख्या

क्र. सं.	आगार का नाम	अप्रैल 08	मई 08	जून 08	जुलाई 08	अगस्त 08	सितम्बर 08	अक्टूबर 08	नवम्बर 08	दिसम्बर 08
1	चण्डीगढ़	232	230	219	219	223	229	229	229	229
2	अम्बाला	187	187	187	179	179	179	179	179	181
3	यमुनानगर	152	146	146	143	146	146	146	146	146
4	करनाल	160	161	162	162	162	162	162	162	162
5	कुरुक्षेत्र	154	154	156	156	155	155	155	155	155
6	सिरसा	156	155	154	153	154	155	155	155	155

7	पानीपत	113	107	109	109	110	110	112	112	112
8	फतेहाबाद	149	149	151	144	142	142	142	142	143
9	रिवाडी	117	117	115	116	118	114	118	122	122
10	सोनीपत	195	199	199	183	173	177	180	181	186
11	फरीदाबाद	202	203	203	204	200	210	214	215	219
12	दिल्ली	105	104	102	93	93	93	93	92	93
13	कैथल	132	130	130	130	131	131	131	131	131
14	रोहतक	147	150	150	146	146	152	156	160	162
15	जींद	150	150	146	148	147	148	148	148	148
16	गुडगांव	169	169	169	171	179	179	159	160	160

17	भिवानी	161	161	161	161	161	160	178	160	160
18	हिसार	181	181	177	176	176	177	177	177	179
19	झज्जर	115	115	112	117	117	120	119	120	120
20	नारनौल	103	103	103	102	104	104	103	103	104
	कुल जोड	3080	3071	3051	3012	3016	3043	3056	103	3067

### अनुसूचि "ख"

अप्रैल 2008 से जनवरी 09 (अब तक) अमले की कमी के कारण मार्ग पर नही भेजी गई बसो का ब्यौरा।

क सं	आगार का नाम	अप्रैल 08	मई 08	जून 08	जुला ई 08	अगस्त 08	सितम्ब र 08	अक्तुब र 08	नवम्ब र 08	दिसम्ब र 08	जनवर ी 08
------	-------------	-----------	-------	--------	-----------	----------	-------------	-------------	------------	-------------	-----------

1	चण्डीगढ	11	11	11	18	18	18	18	18	18	18
	दिनो की संख्या	30	31	30	31	31	30	31	30	31	27
2	अम्बाला	8	8	8	6	6	5	3	भून्य	भून्य	भून्य
	दिनो की संख्या	30	31	30	31	31	30	31			
3	यमुनानगर	4	4	4	2	6	5	3	भून्य	भून्य	भून्य
	दिनो की संख्या	30	31	30	31	31	30	31			
4	करनाल	11	7	9,1	2	6	5	3	भून्य	भून्य	भून्य
	दिनो की संख्या	30	30	30,2 7	31,2 1	31	30	31			
5	कुरुक्षेत्र	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य
			य	य							

	दिनो की संख्या										
6	सिरसा	3	4	4	4	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य
	दिनो की संख्या										
7	पानीपत	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य
	दिनो की संख्या										
8	फतेहाबाद	9	7	7	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य
	दिनो की संख्या	30	31	30							
9	रिवाडी	11	11	11	9	9	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य
	दिनो की संख्या	30	30	30	31	31					





1 7	भिवानी	6	5	6	3,1						
	दिनो की संख्या	30,15,20, 12,23,10	31	31	31,2 7						
1 8	हिसार	भून्य	भून य	भून य	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य
	दिनो की संख्या										
1 9	झज्जर	भून्य	भून य	भून य	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य
	दिनो की संख्या										
2	नारनौल	6	6	6	4	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य

















## अनुसूची 'घ'

हरियाणा राज्य परिवहन के आगारो मे मार्ग पर नही भेजे गये  
औसत वाहनो का ब्यौरा।

क्र सं	आगार का नाम	मार्ग पर नही भेजे गये औसत वाहनो का ब्यौरा	महीनो की संख्या
1	चण्डीगढ	16	12
2	अम्बाला	6	7
3	यमुनानगर	4	7
4	कैथल	6	7
5	सिरसा	4	4
6	फतेहाबाद	8	3
7	रेवाडी	10	5
8	फरीदाबाद	11	4
9	रोहतक	4	4
10	गुडगांव	10	4
11	भिवानी	5	4



12	नारनौल	6	4
	कुल जोड	90	65
	औसत	8	6

**Adulteration in Food Articles**

**\*137. Dr. Sita Ram:** Will the Health Minister be pleased to state the district wise details of samples taken by the Health Department for adulteration in the food articles in the State since, April, 2006 together with fate thereof?

स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देवी): श्रीमान जी, स्वास्थ्य विभागी द्वारा अप्रैल, 2006 से दिसम्बर, 2008 तक कुल 7503 खाद्य नमूने लिए गए, 971 नमूने अपमिश्रित पाए गए तथा इन केसो बारे मुकदमा दायर किया हुआ है। ये सभी केस न्यायालय के विचाराधीन है। जिलावार ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

क्रम सं०	जिले का नाम	अप्रैल 06 से दिस 08 तक लिये गए सैम्पलो की संख्या	अपमिश्रित पाए गए नमूनो की संख्या
	अम्बाला	477	27
	भिवानी	393	50
	फतेहाबाद	206	35

	फरीदाबाद	467	77
	गुडगांव	582	114
	हिसार	563	66
	जींद	333	31
	झज्जर	146	27
	कुरुक्षेत्र	258	46
	कैथल	449	62
	मेवात	617	40
	नारनौल	8	4
	पंचकूला	100	17
	पानीपत	397	76
	पलवल	440	62
	रिवाडी	25	2
	रोहतक	252	38
	सोनीपत	420	21

	सिरसा	288	61
	यमुनानगर	438	38
	कुल	7503	971

**145. Sh Karan Singh Dalal:** Will the Education Minister be pleased to state the districtwise number of Government and aided private degree and post graduate colleges in Rural and Urban area separately in the state alongwith the number in which Science faculty Medical or both is being run during the academic session 2008-09?

सूचना

जिला	राजकीय महाविद्यालय कुल संख्या			सहायता प्राप्त महाविद्यालय कुल संख्या			राजकी महाविद्यालय मे चलाये जा रहे कोर्स			सहायता प्राप्त महाविद्यालय मे चलाये जा रहे कोर्स		
	भाहरी	ग्रामीण	कुल	भाहरी	ग्रामीण	कुल	स्नातकोत्तर	मैडीकल कोर्स	नान मैडीकल कोर्स	स्नातकोत्तर	मैडीकल कोर्स	नान मैडीकल कोर्स
अम्बाला	2	1	3	6	3	9	1	1	1	6	3	4
पंचकूला	3	1	4	0	0	0	2	3	3	0	0	0
भिवानी	4	3	7	4	2	6	2	2	2	3	3	3
फरीदाबाद	3	1	4	5	0	5	1	1	2	2	2	3

गुडगांव	3	2	5	1	0	1	2	2	2	0	0	0
मेवात	0	2	2	1	0	1	0	0	0	1	1	1
हिसार	3	3	6	4	0	4	2	2	2	3	3	3
फतेहाबाद	2	2	4	1	0	1	1	0	1	0	0	0
कैथल	1	0	1	5	2	7	0	0	1	1	1	1
यमुनानगर	0	1	1	7	1	8	0	0	0	5	5	5
जींद	4	1	5	3	0	3	4	3	3	0	0	0
करनाल	2	2	4	4	0	4	3	1	1	2	2	2
पानीपत	1	1	2	5	0	5	0	0	0	3	3	3
महेन्द्रगढ	5	3	8	0	0	0	3	3	3	0	0	0

रिवाडी	1	3	4	3	1	4	3	0	1	2	2	2
रोहतक	3	2	5	7	0	7	1	1	1	2	2	2
झज्जर	2	4	6	2	0	2	1	2	2	4	4	4
सोनीपत	1	1	2	6	0	6	0	1	1	4	4	4
सिरसा	2	0	2	2	1	3	1	1	1	0	0	0
कुरुक्षेत्र	0	0	0	6	0	6	0	0	0	2	2	4

**Cases of Murder, Rape etc.**

**138. Dr. Sita Ram:** Will the Chief Minister be pleased to state the district wise and month wise total number of cases of murder, rape, dacoity and ransom registered since April 1<sup>st</sup> 2008 till date together with the Status thereof?

**मुख्यमंत्री (श्री भुपेन्द्र सिंह हुड्डा):** वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है ।

## सूचना

## हत्या

जिला	अप्रैल 08	मई 08	जून 08	जुलाई 08	अगस्त 08	सितम्बर 08	अक्तुबर 08	नवम्बर 08	दिसम्बर 08	जनवरी 09
पंचकूला	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1
अम्बाला	4	0	1	2	3	5	4	5	4	1
यमुनानगर	4	3	3	5	3	3	4	4	3	1
कुरुक्षेत्र	4	0	2	0	2	0	2	4	1	2
कैथल	3	4	3	1	3	1	4	2	0	2
हिसार	5	4	16	7	3	4	1	4	0	1



सिरसा	2	3	7	2	4	5	4	5	6	1
भिवानी	2	7	4	7	4	9	4	4	5	3
जीन्द	3	4	3	2	3	5	4	1	7	3
फतेहाबाद	2	2	0	1	5	1	2	4	0	1
गुडगांव	1	10	3	6	12	2	10	7	6	3
फरीदाबाद	4	4	4	12	6	5	8	3	1	3
पलवल	3	4	3	2	5	3	3	5	0	1
नारनौल	3	2	1	3	5	2	2	2	3	0
रेवाडी	2	1	4	2	1	2	4	2	3	1
मेवात	0	1	3	1	1	3	2	2	2	3

रोहतक	4	56	4	3	4	8	5	5	11	5
सोनीपत	4	10	10	9	2	4	12	7	10	2
करनाल	4	2	1	8	4	6	3	3	4	1
पानीपत	4	4	5	2	5	6	3	5	5	3
झज्जर	6	5	7	8	9	9	4	5	2	5
रेलवे	1	3	4	1	3	2	2	3	0	1
कुल	67	80	89	86	88	86	88	83	74	44

### बलात्कार

जिला	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तुबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी
------	--------	----	-----	-------	-------	---------	---------	--------	---------	-------

	08	08	08	08	08	08	08	08	08	09
पंचकूला	1	0	1	0	0	1	2	3	0	1
अम्बाला	0	4	6	3	4	4	4	3	2	0
यमुनानगर	1	1	6	4	1	3	6	3	0	1
कुरुक्षेत्र	3	5	5	6	4	4	6	3	0	2
कैथल	0	1	2	0	2	2	3	2	0	0
हिसार	1	4	2	3	3	3	1	0	1	1
सिरसा	1	2	2	4	6	3	2	3	2	1
भिवानी	2	3	5	6	4	4	1	1	1	6
जीन्द	2	3	4	6	5	2	5	2	0	3

फतेहाबाद	6	0	1	1	2	0	2	0	0	1
गुडगांव	7	0	4	3	7	6	3	1	2	2
फरीदाबाद	1	1	6	4	5	1	5	6	2	2
पलवल	2	2	3	1	6	4	2	3	0	1
नारनौल	0	2	1	2	3	0	3	3	0	1
रेवाडी	8	1	3	3	2	4	6	0	3	0
मेवात	3	2	2	1	2	5	4	1	2	1
रोहतक	4	2	3	7	1	3	3	3	2	3
सोनीपत	0	4	6	1	1	3	2	3	5	0
करनाल	1	3	8	9	6	3	4	2	5	1

पानीपत	1	2	3	2	1	4	6	0	5	3
झज्जर	0	3	5	1	2	1	2	3	3	0
रेलवे	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
कुल	46	46	78	67	67	60	73	45	35	30

### डकैती

जिला	अप्रैल 08	मई 08	जून 08	जुलाई 08	अगस्त 08	सितम्बर 08	अक्तुबर 08	नवम्बर 08	दिसम्बर 08	जनवरी 09
पंचकूला	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1
अम्बाला	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

यमुनानगर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
कुरुक्षेत्र	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
कैथल	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0
हिसार	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
सिरसा	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
भिवानी	4	1	2	1	0	0	0	1	2	0
जीन्द	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1
फतेहाबाद	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
गुडगांव	3	3	4	2	0	5	1	1	2	1
फरीदाबाद	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0









मेवात	0	0	1	3	0	1	1	1	2	0
रोहतक	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
सोनीपत	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
करनाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पानीपत	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
झज्जर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
रेलवे	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	0	0	2	0	0	1	1	1	2	0

बलात्कार

माह	पंचकूला	अम्बाला	यमुनानगर	कुरुक्षेत्र	कैथल
अप्रैल 08	न्यायालय मे लंबित 1	भून्य	न्यायालय मे लंबित 1 अनुसंधानाधीन 1	न्यायालय मे लंबित 2	भून्य
मई 08	भून्य	न्यायालय मे लंबित 3 बरी 1	न्यायालय मे लंबित 1	भून्य	न्यायालय मे लंबित 4
जून 08	न्यायालय मे लंबित 1	न्यायालय मे लंबित 5 रद्द 1	न्यायालय मे लंबित 6	रद्द 1 बरी 1 न्यायालय मे लंबित 4	भून्य
जुलाई 08	न्यायालय मे लंबित 2	न्यायालय मे लंबित 1 अनुसंधानाधीन 1	न्यायालय मे लंबित 3 अनुसंधानाधीन 2	भून्य	अनुसंधानाधीन 1
अगस्त 08	न्यायालय मे लंबित 1	न्यायालय मे लंबित 1 अनुसंधानाधीन	न्यायालय मे लंबित 1 अनुसंधानाधीन	चालान 1 अनुसंधानाधीन 1	न्यायालय मे लंबित 3

		1	1		
सितम्बर 08	न्यायालय मे लंबित 1	न्यायालय मे लंबित 2 अनुसंधानाधीन 3	अनुसंधानाधीन 3	भून्य	न्यायालय मे लंबित 1
अक्टूबर 08	अनुसंधानाधीन 1	न्यायालय मे लंबित 2 अनुसंधानाधीन 1	न्यायालय मे लंबित 2 अनुसंधानाधीन 2	अनुसंधानाधीन 2	न्यायालय मे लंबित 2 अनुसंधानाधीन 2
नवम्बर 08	न्यायालय मे लंबित 1	न्यायालय मे लंबित 1 अनुसंधानाधीन 4	न्यायालय मे लंबित 2 अनुसंधानाधीन 2	अनुसंधानाधीन 4	न्यायालय मे लंबित 1 अनुसंधानाधीन 1
दिसम्बर 08	अनुसंधानाधीन 1	अनुसंधानाधीन 4	अनुसंधानाधीन 3	अनुसंधानाधीन 1	भून्य
जनवरी 09	अनुसंधानाधीन 1	अनुसंधानाधीन 1	अनुसंधानाधीन 1	अनुसंधानाधीन 2	अनुसंधानाधीन 2

**डैकती**

माह	पंचकूला	अम्बाला	यमुनानगर	कुरुक्षेत्र	कैथल
-----	---------	---------	----------	-------------	------

अप्रैल 08	भून्य	भून्य	भून्य	न्यायालय मे लंबित 4	भून्य
मई 08	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य	न्यायालय मे लंबित 1
जून 08	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य
जुलाई 08	भून्य	भून्य	भून्य	अनुसंधानाधीन 1	भून्य
अगस्त 08	न्यायालय मे लंबित 2 अनुसंधानाधीन 4	अनुसंधानाधीन 1	भून्य	भून्य	भून्य
सितम्बर 08	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य
अक्तूबर 08	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य	न्यायालय मे लंबित 2
नवम्बर 08	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य	न्यायालय मे लंबित 1

दिसम्बर 08	भाून्य	भाून्य	भाून्य	भाून्य	भाून्य
जनवरी 09	अनुसंधानाधीन 1	भाून्य	अनुसंधानाधीन 1	भाून्य	भाून्य

हत्या के केसो की वर्तमान स्थिती (हिसार मण्डल)

माह	हिसार	सिरसा	भिवानी	जींद	फतेहाबाद
अप्रैल 08	न्यायालय मे लंबित 5	न्यायालय मे लंबित 1 रदद 1	न्यायालय मे लंबित 1 अनुसंधानाधीन 1	न्यायालय मे लंबित 3	न्यायालय मे लंबित 2
मई 08	न्यायालय मे लंबित 1 अनुसंधानाधीन 3	न्यायालय मे लंबित 3	न्यायालय मे लंबित 6	न्यायालय मे लंबित 2 अदमपता 2	न्यायालय मे लंबित 2
जून 08	न्यायालय मे लंबित 12 अनुसंधानाधीन 3 रदद 1	न्यायालय मे लंबित 7	न्यायालय मे लंबित 2 अनुसंधानाधीन 1 रदद 1	न्यायालय मे लंबित 2 अनुसंधानाधीन 1	भाून्य

जुलाई 08	न्यायालय मे लंबित 6 अनुसंधानाधीन 1	न्यायालय मे लंबित 2	न्यायालय मे लंबित 5 अनुसंधानाधीन 2	न्यायालय मे लंबित 2	न्यायालय मे लंबित 1
अगस्त 08	न्यायालय मे लंबित 2 अनुसंधानाधीन 1	न्यायालय मे लंबित 2 अनुसंधानाधीन 2	न्यायालय मे लंबित 2 अनुसंधानाधीन 2	न्यायालय मे लंबित 2 अनुसंधानाधीन 1	न्यायालय मे लंबित 5
सितम्बर 08	न्यायालय मे लंबित 2 अनुसंधानाधीन 2	न्यायालय मे लंबित 4 अनुसंधानाधीन 1	न्यायालय मे लंबित 5 अनुसंधानाधीन 2 रदद 2	न्यायालय मे लंबित 3 अदमपता 2	न्यायालय मे लंबित 1
अक्टूबर 08	न्यायालय मे लंबित 1	न्यायालय मे लंबित 3 अनुसंधानाधीन 1	न्यायालय मे लंबित 3 रदद 1	न्यायालय मे लंबित 3 अनुसंधानाधीन 1	न्यायालय मे लंबित 2
नवम्बर 08	न्यायालय मे लंबित 4	न्यायालय मे लंबित 2 अनुसंधानाधीन	न्यायालय मे लंबित 1 अनुसंधानाधीन	न्यायालय मे लंबित 1 अनुसंधानाधीन	न्यायालय मे लंबित 3 अनुसंधानाधीन

		3	3	1	1
दिसम्बर 08	भून्य	न्यायालय मे लंबित 1 अनुसंधानाधीन 5	रदद 1 अनुसंधानाधीन 4	अनुसंधानाधीन 7	भून्य
जनवरी 09	अनुसंधानाधीन 1	अनुसंधानाधीन 1	अनुसंधानाधीन 3	अनुसंधानाधीन 3	अनुसंधानाधीन 1

**बलात्कार**

माह	हिसार	सिरसा	भिवानी	जींद	फतेहाबाद
अप्रैल 08	रदद 1	न्यायालय मे लंबित 1	न्यायालय मे लंबित 1 बरी 1	रदद 2	न्यायालय मे लंबित 1 बरी 1
मई 08	न्यायालय मे लंबित 3 रदद 1	न्यायालय मे लंबित 2	न्यायालय मे लंबित 2 बरी 1	न्यायालय मे लंबित 2 रदद 1	भून्य
जून 08	न्यायालय मे लंबित 2	न्यायालय मे लंबित 2	न्यायालय मे लंबित 3 बरी 1	रदद 3 अनुसंधानाधीन 2	न्यायालय मे लंबित 1



			रदद 1		
जुलाई 08	न्यायालय मे लंबित 3	न्यायालय मे लंबित 2 अनुसंधानाधीन 1 रदद 1	न्यायालय मे लंबित 5 अनुसंधानाधीन 1	न्यायालय मे लंबित 5 रदद 1	न्यायालय मे लंबित 1
अगस्त 08	न्यायालय मे लंबित 3	न्यायालय मे लंबित 4 अनुसंधानाधीन 1	न्यायालय मे लंबित 3 अनुसंधानाधीन 2	न्यायालय मे लंबित 4 रदद 1	न्यायालय मे लंबित 1 रदद 1
सितम्बर 08	न्यायालय मे लंबित 1 रदद 1	न्यायालय मे लंबित 3	न्यायालय मे लंबित 2 अनुसंधानाधीन 1 रदद 1	न्यायालय मे लंबित 2	भाून्य
अक्टूबर 08	न्यायालय मे लंबित 1	न्यायालय मे लंबित 2	न्यायालय मे लंबित 1	न्यायालय मे लंबित 4 रदद 1	न्यायालय मे लंबित 2
नवम्बर 08	भाून्य	अनुसंधानाधीन 3	न्यायालय मे लंबित 1	न्यायालय मे लंबित 1	भाून्य

दिसम्बर 08	अनुसंधानाधीन 1	अनुसंधानाधीन 2	अनुसंधानाधीन 1	भाून्य	भाून्य
जनवरी 09	अनुसंधानाधीन 1	अनुसंधानाधीन 1	अनुसंधानाधीन 6	अनुसंधानाधीन 3	अनुसंधानाधीन 1

**डकैती**

माह	हिसार	सिरसा	भिवानी	जींद	फतेहाबाद
अप्रैल 08	भाून्य	भाून्य	न्यायालय मे लंबित 3 अनुसंधानाधीन 1	भाून्य	भाून्य
मई 08	भाून्य	भाून्य	न्यायालय मे लंबित 1	भाून्य	भाून्य
जून 08	भाून्य	भाून्य	न्यायालय मे लंबित 1	भाून्य	भाून्य
जुलाई 08	भाून्य	न्यायालय मे लंबित 1	न्यायालय मे लंबित 1	भाून्य	न्यायालय मे लंबित 1

अगस्त 08	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य
सितम्बर 08	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य
अक्तूबर 08	न्यायालय मे लंबित 1	भून्य	भून्य	भून्य	भून्य
नवम्बर 08	भून्य	भून्य	न्यायालय मे लंबित 1	भून्य	भून्य
दिसम्बर 08	भून्य	भून्य	न्यायालय मे लंबित 2	भून्य	भून्य
जनवरी 09	भून्य	भून्य	भून्य	अनुसंधानाधीन 1	भून्य

हत्या के केसो की वर्तमान स्थिती (फरीदाबाद मण्डल)

माह	फरीदाबाद	पलवल	नारनौल	रिवाडी	मेवात
अप्रैल 08	न्यायालय मे लंबित 3 रदद 1	न्यायालय मे लंबित 1 अनुसंधानाधीन 1 अदमपता 1	न्यायालय मे लंबित 3 अनुसंधानाधीन 1 रदद 1	न्यायालय मे लंबित 2	भून्य

मई 08	न्यायालय मे लंबित 2 अनुसंधानाधीन 2	न्यायालय मे लंबित 2 अनुसंधानाधीन 2	न्यायालय मे लंबित 2	न्यायालय मे लंबित 1	न्यायालय मे लंबित 1
जून 08	न्यायालय मे लंबित 4	न्यायालय मे लंबित 2 अनुसंधानाधीन 1	न्यायालय मे लंबित 2 अनुसंधानाधीन 1	न्यायालय मे लंबित 1 अनुसंधानाधीन 3	न्यायालय मे लंबित 2 बरी 1
जुलाई 08	न्यायालय मे लंबित 11 अनुसंधानाधीन 1	न्यायालय मे लंबित 1 रदद 1	न्यायालय मे लंबित 1 रदद 2	न्यायालय मे लंबित 1	न्यायालय मे लंबित 1
अगस्त 08	न्यायालय मे लंबित 2 अनुसंधानाधीन 3 अदमपता 1	न्यायालय मे लंबित 4 अनुसंधानाधीन 1	न्यायालय मे लंबित 3 अनुसंधानाधीन 2	न्यायालय मे लंबित 1	रदद 1
सितम्बर 08	न्यायालय मे लंबित 2 अनुसंधानाधीन 3	न्यायालय मे लंबित 3	न्यायालय मे लंबित 2	न्यायालय मे लंबित 2	भन्यायालय मे लंबित 3

अक्टूबर 08	न्यायालय मे लंबित 4 अनुसंधानाधीन 3 अदमपता 1	न्यायालय मे लंबित 3	न्यायालय मे लंबित 2	अनुसंधानाधीन 2	न्यायालय मे लंबित 1 अनुसंधानाधीन 1
नवम्बर 08	न्यायालय मे लंबित 1 अनुसंधानाधीन 2	न्यायालय मे लंबित 2 अनुसंधानाधीन 3	न्यायालय मे लंबित 2	न्यायालय मे लंबित 4 अनुसंधानाधीन 3	अनुसंधानाधीन 2
दिसम्बर 08	अनुसंधानाधीन 1	अनुसंधानाधीन 2	अनुसंधानाधीन 1	भाून्य	भाून्य
जनवरी 09	अनुसंधानाधीन 1	अनुसंधानाधीन 1	अनुसंधानाधीन 6	अनुसंधानाधीन 3	अनुसंधानाधीन 1

हत्या के केसो की वर्तमान स्थिती (पुलिस आयुक्त गुडगांव तथा  
रेलवे)

माह	पुलिस आयुक्त गुडगांव	रेलवे
अप्रैल 08	न्यायालय मे लंबित 1	न्यायालय मे लंबित 1
मई	न्यायालय मे लंबित 4	न्यायालय मे लंबित 2

08	अनुसंधानाधीन 4 अदमपता 2	रदद 1
जून 08	न्यायालय मे लंबित 2 अनुसंधानाधीन 1	न्यायालय मे लंबित 2 अनुसंधानाधीन 1 रदद 1
जुलाई 08	न्यायालय मे लंबित 3 अनुसंधानाधीन 3	रदद 1
अगस्त 08	न्यायालय मे लंबित 8 अनुसंधानाधीन 4	अदमपता 3 रदद 1
सितम्बर 08	न्यायालय मे लंबित 2	अदमपता 2
अक्तूबर 08	न्यायालय मे लंबित 2 अनुसंधानाधीन 7 रदद 1	अदमपता 3
नवम्बर 08	न्यायालय मे लंबित 1 अनुसंधानाधीन 6	अदमपता 3 अनुसंधानाधीन 1

दिसम्बर 08	अनुसंधानाधीन 6	भून्य
जनवरी 09	अनुसंधानाधीन 3	अनुसंधानाधीन 2

**बलात्कार**

माह	पुलिस गुडगांव	आयुक्त	रेलवे
अप्रैल 08	न्यायालय मे लंबित 6		न्यायालय मे लंबित 1
मई 08	भून्य		न्यायालय मे लंबित 1
जून 08	न्यायालय मे लंबित 3 अनुसंधानाधीन 1		भून्य
जुलाई 08	न्यायालय मे लंबित 2 अनुसंधानाधीन 3		भून्य
अगस्त 08	न्यायालय मे लंबित 7 अनुसंधानाधीन 4		भून्य
सितम्बर 08	न्यायालय मे लंबित 5 अनुसंधानाधीन 1		भून्य

अक्टूबर 08	न्यायालय मे लंबित 2 अनुसंधानाधीन 1	न्यायालय मे लंबित 1
नवम्बर 08	अनुसंधानाधीन 1	भून्य
दिसम्बर 08	अनुसंधानाधीन 2	भून्य
जनवरी 09	अनुसंधानाधीन 2	भून्य

### डकैती

माह	पुलिस गुडगांव	आयुक्त रेलवे
अप्रैल 08	न्यायालय मे लंबित 1 अनुसंधानाधीन 1 अदमपता 1	भून्य
मई 08	न्यायालय मे लंबित 1 अनुसंधानाधीन 1	भून्य
जून 08	न्यायालय मे लंबित 1 अनुसंधानाधीन 2 अदमपता 1	भून्य



जुलाई 08	अनुसंधानाधीन 2	भून्य
अगस्त 08	न्यायालय मे लंबित 1 अनुसंधानाधीन 1	भून्य
सितम्बर 08	न्यायालय मे लंबित 3 अनुसंधानाधीन 1	भून्य
अक्टूबर 08	न्यायालय मे लंबित 1	भून्य
नवम्बर 08	अनुसंधानाधीन 1	अदमपता 1 अनुसंधानाधीन 2
दिसम्बर 08	अनुसंधानाधीन 2	भून्य
जनवरी 09	अनुसंधानाधीन 1	भून्य

### फिरौती

अक्टूबर 08	अनुसंधानाधीन 1	भून्य
नवम्बर 08	रदद 1	

### Posting of Doctors

**150. Shri Naresh Yadav:** Will the Health Minister be pleased to state whether it is a fact that no doctor has been posted in the Community Health Centre Nangal Chaudhary?

स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देवी): श्रीमान् जी,

जी नहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नांगल चौधरी में 3 डाक्टर नियुक्त हैं।

**Junior Lecturers and Masters Working in SSA**

**146. Sh Karan Singh Dalal:** Will the Education Minister be pleased to state the district wise number of Junior Lecturers of Science faculty subject wise and the number of Science and Mathematics Masters working in SSA during the current academic session of 2008-09?

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता): इस प्रश्न का उत्तर निम्न प्रकार से है:-

(क) राज्य में वर्तमान भौतिक सत्र 2008-09 में 31.5.08 की स्थिति अनुसार तक 82 विज्ञान स्कूला प्राध्यापक सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूणकालीन कार्यरत थे, जिनका जिलावार। ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

क्रम सं०	मुख्यालय जिला	संख्या	विशय		
			भौतिक	रसायन	जीव

			विज्ञान	विज्ञान	विज्ञान
1	मुख्यालय चण्डीगढ	1	1		
2	अम्बाला	7		1	6
3	भिवानी	2		1	1
4	फरीदाबाद	7	3	3	1
5	फतेहाबाद	1			1
6	गुडगांव	1			1
7	हिसार	8		2	6
8	झज्जर	4	1		3
9	जींद	1			1
10	करनाल	9		1	8
11	कुरुक्षेत्र	6		1	5
12	कैथल				
13	मेवात				
14	महेन्द्रगढ	2			2

15	पंचकूला	3	2		1
16	पानीपत				
17	रिवाडी	2			2
18	रोहतक	17	2	4	11
19	सोनीपत	6	1	1	4
20	सिरसा	5		1	4
21	यमुनानगर				
	<b>कुल</b>	<b>82</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>57</b>

(ख) वर्तमान भौक्षिक सत्र 2008-09 मे 31.5.08 की स्थिती अनुसार तक सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 35 विज्ञान अध्यापक तथा 65 गणित अध्यापक पूणकालीन कार्यरत थे/है, जिनका जिलावार ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

क्रम सं०	मुख्यालय जिला	विशय	
		साईंस	गणित
1	मुख्यालय चण्डीगढ		1

2	अम्बाला		3
3	भिवानी	5	14
4	फरीदाबाद	2	1
5	फतेहाबाद		
6	गुडगांव		1
7	हिसार	5	5
8	झज्जर	1	5
9	जींद	6	3
10	करनाल		
11	कुरुक्षेत्र		4
12	कैथल	2	3
13	मेवात		3
14	महेन्द्रगढ़	5	6
15	पंचकूला		3
16	पानीपत		

17	रिवाडी		5
18	रोहतक	4	5
19	सोनीपत	1	
20	सिरसा	4	3
21	यमुनानगर		
	<b>कुल</b>	<b>35</b>	<b>65</b>

(ग) राज्य सरकार के निर्णय अनुसार ए० बी० आर० सी० के रूप में कार्यरत सभी प्राध्यापको, अध्यापको को उनके मूल संवर्ग में नियुक्ति के लिए आयुक्त एवं महानिदेशक, शिक्षा हरियाणा को लिखा गया है।

### **Opening of PHCs**

**151 Sh Naresh Yadav:** Will the Health Minister be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Primary Health Centre in the villages Backhood and Kanti in district Mahendragarh: and

(b) if so, the time by which the above said Primary Health Centres are likely to be opened?

**स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देवी):**

(क) हा श्रीमान् जी, उप स्वास्थ्य केन्द्र कांटी का दर्जा बढा कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र करना प्रस्तावित है। बाछौद मे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहले से कार्यरत है।

(ख) समय सीमा नही दी जा सकती।

### **Posts Lying vacant in DHBVN**

**139. Dr. Sita Ram:** Will the Power Minister be pleased to state:

(a) the total number of posts of technical staff like JE's, Lineman etc, and non technical staff like clerk, sweepers, chowkidar etc. in DHBVN Haryana together with the number of posts lying vacant and since when; and

(b) the total number of posts lying vacant in the said Nigam in Sirsa District; together with the time by which the such vacant posts are likely to be filled up?

**बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला):**

श्रीमान्, विवरण माननीय सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

### **विवरण**

(ए) कुल स्वीकृत पद तथा द० ह० बि० वि० नि० के अन्तर्गत खाली पदों को दाने वाला विवरण:—

द०ह०बि०वि०नि० के अन्तर्गत तकनीकी स्टाफ जैसे जे० ई०, ए० एफ० एम०, एल० एम०, तथा नाने टैक्नीकल स्टाफ जैसे

लिपिक, सफाई कर्मचारी, चौकीदार के कुल स्वीकृत पदों की संख्या तथा खाली पड़े पदों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्र सं०	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	31.12. 2008 को कार्यरत	खाली पद
1	सहायक भण्डार अधिकारी	5	1	4
2	एच एस के	4	3	1
3	स्टोर कीपर	10	12	2
4	स्टोर मु ि	15	8	7
5	स्टोर वेरीफायर	1		1
6	सी डी एम	3	3	
7	सी एच डी	8	8	
8	एच डी एम	37	36	1
9	ड्राफ्ट मैन	88	48	40
10	जे० ई० सिविल	24	21	3
11	जे ई 1	118	83	35



12	जे० ई०	371	262	109
13	फौरमैन	3		3
14	ए एफ एम	645	386	259
15	लाईनमैन	2504	2287	217
16	ए एल एम	6042	2676	3366
17	केबल ज्वार्इन्टर	1		1
18	एम एम ए	232	212	20
19	ए एस एस ए	472	405	67
20	एस ए	448	191	257
21	उपकरण मिस्त्री	1		1
22	वरिश्ठ लैब अटैन्डैण्ट	16	15	1
23	वरिश्ठ टैक्नीशियन	1		1
24	इलैक्ट्रिशियन	2	1	1
25	टैक्नीशियन ग्रेड 1	10		10
26	टैक्नीशियन ग्रेड 2	4		4

27	हैल्पर ग्रेड 2	42		42
28	लैब सहायक	6	6	
29	मेसन	1		1
30	कारपेन्टर	4	2	2
31	लैब अटेंडेंट	25	22	3
	<b>योग</b>	<b>11143</b>	<b>6688</b>	<b>4455</b>

**तकनीकी श्रेणी-IV**

1	स्टोर अटेन्डेंट	94	30	64
2	वर्क मेट / टी- मेट	50	44	6
3	हैल्पर ग्रेड 1	23		23
4	कुशल हैल्पर	7	5	2
5	पलम्बर पाईप फिटर	2	2	
	<b>योग</b>	<b>176</b>	<b>81</b>	<b>95</b>

**गैर तकनीकी श्रेणी-III**

1	अनुभाग अधिकारी	25	10	15
---	----------------	----	----	----

2	डिवीजनल अकाउंटेंट रैवेन्यू आडिटर	103	48	55
3	सर्कल अधीक्षक	8	8	
4	उप अधीक्षक	5	5	
5	सहायक मुख्यालय	63	62	1
6	हैड क्लर्क	34	22	12
7	सर्कल सहायक	15	13	2
8	वाणिज्यिक सहायक / सहायक लेखापाल	119	115	4
9	उच्च श्रेणी लिपिक (मुख्यालय)	59	47	12
10	उच्च श्रेणी लिपिक (फिल्ड)	577	253	324
11	निम्न श्रेणी लिपिक (मुख्यालय)	67	49	18
12	उच्च श्रेणी लिपिक (फिल्ड)	1144	810	334

13	मीटर रीडर	530	381	149
14	हैड मिस्ट्रस	1	1	
15	बी एड अध्यापक	6	1	5
16	जे बी टी अध्यापक	13	9	4
17	पी टी आई	1		1
18	मेट्रन / नर्स	1	1	
19	डी एम ए	1	1	2
20	पम्प ड्राईवर	8	6	2
21	केन ड्राईवर			
22	ड्राईवर (मुख्यालय)	6		6
23	ड्राईवर (फिल्ड)	18	18	
24	वर्क सुपरवाइजर	264	181	83
25	निजी सहायक	3	2	
26	वरिष्ठ आ तुलिपिक	13	13	
27	कनिष्ठ आ तुलिपिक	19	19	

28	आ टुटंकक	73	32	41
29	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	21	6	15
30	हिन्दी अनुवादक	18		18
31	कनिश्ठ फोटोग्राफर	2	2	
32	सुरक्षा अधिकारी	1		1
33	सुरक्षा हवलदार	3	1	2
34	चौकसी निरीक्षक	13	6	7
35	उप निरीक्षक	6	1	5
36	ए एस आई	7	1	6
37	मुख्य सिपाही	3	7	4
38	सिपाही	9	11	2
39	फार्मासिस्ट	15	10	5
40	रेस्टारर	12	7	5
41	कलचर सहायक		3	3
42	पब्लिसीटी काआर्डिनेटर			

43	लैब टेक्नियन (स्वास्थ्य)	3	1	
44	वरिष्ठ फार्मासिस्ट			2
	<b>योग</b>	<b>3289</b>	<b>2163</b>	<b>1126</b>

गैर तकनीकी श्रेणी-IV

1	बिल वितरक	367	145	222
2	हवलदार (मुख्यालय)	13	13	
3	हवलदार (फिल्ड)	8	5	3
4	दफ्तरी (फिल्ड)	7	2	5
5	मुख्य सफाई कर्मचारी	1	1	
6	सफाई कर्मचारी	57	54	3
7	संदे वाहक	118	115	3
8	संदे वाहक (फिल्ड)	346	303	43
9	संदे वाहक कम मेड	4	4	
10	सफाई कर्मचारी कम चौकीदार	2		2

11	चौकीदार	208	127	81
12	सिवर मैन	14	4	10
13	साहयक पम्प ड्राईवर	11	3	8
14	माली	48	42	6
15	वा र मैन	1	1	8
16	क्लीनर	15	7	
17	कूक	2	2	3
18	चौकीदार कम कूक	6	3	83
19	सुरक्षा गार्ड	94	11	
20	अटैन्डैंट	1	1	
	<b>योग</b>	<b>1323</b>	<b>843</b>	<b>480</b>

(मुख्य सारां त)

1	तकनीकी (श्रेणी III)	11143	6688	4455
2	तकनीकी श्रेणी IV	176	81	95
3	गैर तकनीकी श्रेणी III	3289	2163	1126

4	गैर तकनीकी श्रेणी IV	1323	843	480
	<b>योग</b>	<b>15931</b>	<b>9775</b>	<b>6156</b>

कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों की पदोन्नति / सेवानिवृत्ति / मृत्यु के कारण खाली हुए पदों को सीधी भर्ती या निम्न पदों से पदोन्नति द्वारा भरा जा रहा है। यह एक लगातार प्रक्रिया है।

(बी) उक्त निगम के जिला सिरसा में पड़े खाली पदों की संख्या निम्न प्रकार है:—

क्रम संख्या	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	खाली पद
1	सहायक कार्यकारी अभियन्ता / सहायक अभियन्ता	14	9
2	जे ई / जे ई 1 विधुत		
3	जे ई / सिविल	40	1
4	ए एफ एम	2	5



5	एस एस ए	64	4
6	ए एस एस ए	38	1
7	एस ए	41	39
8	लाइनमैन	60	27
9	ए एल एम	249	460
10	सर्कल सहायक	681	1
11	वाणिज्यिक सहायक	2	5
12	कनश्ठि आ णुलिपि	14	2
13	उच्च श्रेणी लिपिक	4	39
14	निम्न श्रेणी लिपिक (कै T)	56	34
15	निम्न श्रेणी लिपिक	44	26
16	मीटर रीडर	87	23
17	ड्राफ्ट मैन	51	2
18	ड्राईवर	8	12
19	ए पी डी	34	3

20	चौकीदार	4	9
21	दफ्तरी	32	1
22	बिल वितरक	1	26
23	सफाई कर्मचारी	45	6
24	सिवरमैन	3	1
	<b>योग</b>	<b>1616</b>	<b>736</b>

उपरोक्त खाली पदों को अगले वित्तीय वर्ष के दौरान अर्थात् वित्तीय वर्ष 2009-10 के अन्त तक खाली पदों को भरने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

निम्नलिखित पदों को भरने के लिए मांग हरियाणा स्टाफ सिलैब इन कमी इन को भेज दी गई है जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है।

क्र सं०	पद का नाम	मांगे गए पदों की संख्या
1	ए एल एम	1000
2	एस ए	100
3	यू डी सी	66

4	एल डी सी	142
5	लेखापाल	20
6	जे ई (ई)	100
7	ए ई (ई)	63
8	कम्पनी सचिव	1

**Number of Recognized Private Senior Secondary Schools**

**147. Sh Karan Singh Dalal:** Will the Education Minsiter be pleased to state the districtwise number of recognized private Senior Secondayr Schools in the state in Rural and Urban area separately in which Science faculty Medical and Non-Medical or both is being run during the current academic academic session 2008-09 alongwith the number of students enrolled in +1 and +2 in the above faculties?

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता ): श्रीमान् जी, अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार से है:—

जिला	निजी मान्यता प्राप्त ग्रामीण तथा भाहरी क्षेत्र मे पृथक पृथक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयो की संख्या जिनमे वर्तमान	वर्ष 2008-09 के दौरान चलाई जा रही संकाय की वर्तमान स्थिती	वर्तमान भौक्षणिक सत्र 2008-09 मे पंजीकृत
------	---	---	--

	भौक्षणिक सत्र 2008-09 मे विज्ञान संकाय चल रहा है।					दाखिल छात्रो की संख्या	
	ग्रामीण	भाहरी	मैडीकल	नानॅ मैडीकल	दोनो	10+1	10+2
अम्बाला	0	11	0	8	3	651	556
भिवानी	23	5	2	13	13	940	746
फरीदाबाद	2	22	0	15	9	1777	1682
फतेहाबाद	1	3	0	0	4	204	137
गुडगांव	7	4	0	10	1	605	500
हिसार	0	9	0	4	5	471	294
जींद	4	14	0	2	16	1880	1493
झज्जर	3	8	0	8	3	235	185
करनाल	7	4	0	10	1	288	193
कुरुक्षेत्र	2	6	0	6	2	413	303
कैथल	2	13	6	4	5	1011	1083

मेवात	0	0	0	0	0	0	0
नारनौल	5	7	0	6	6	614	458
पानीपत	9	5	0	6	8	1012	885
पंचकूला	0	2	0	0	2	30	41
रोहतक	7	10	0	7	10	872	932
रेवाडी	22	2	0	14	10	981	771
सोनीपत	10	18	0	15	13	1311	1216
सिरसा	5	10	0	4	11	370	282
यमुनानगर	2	11	0	7	6	1069	909

**Persons who got Benefit undr Ladli Yojana**

**143. Sh Naresh Yadav:** Will the Women & Child Development Minister be pleased to state the number of persons who got benefit under Ladli Yojana during the period from 2005 to 2008 together with the number of girls who have been provided the amount of marriage Shagun at the time of their marriage along with the date wise details thereof

**स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देवी):** श्रीमान् जी, वर्ष 2005 से 2008 तक की समय अवधि के दौरान लाडली योजना के अन्तर्गत 66423 व्यक्तियों/लडकियों को लाभ प्रदान किया

गया। लाडली योजना के अन्तर्गत विवाह भागुन का प्रावधान नहीं है।

### Upgradation of Schools

**140. Dr Sita Ram:** Will the Education Minister be pleased to state the constituency wise total number of schools upgraded from Middle to High School and High school to Senior Secondary School in the financial year 2008-09?

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता): श्रीमान जी, वित्ती वर्ष 2008-09 में माध्यमिक विद्यालय से उच्च विद्यालय एवं उच्च विद्यालय से वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सत्रोन्नत किए गए कुल सरकारी विद्यालयों की निर्वाचन क्षेत्रवार स्थिति निम्नलिखित है:-

क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	सत्रोन्नत किए गए स्कूल		
		माध्यमिक से उच्च	उच्च से वरिष्ठ माध्यमिक	कुल
1	अम्बाला भाहर	0	0	0
2	मुलाना	0	1	1
3	नारायण गढ़	0	0	0

4	नरुगल	0	4	4
5	अडुडलल ङलवनी	0	0	0
6	दलदरी	1	0	1
7	लुलहलरु	0	0	0
8	डुढलल सुलरुद	0	2	2
9	डवलनी खेडल	0	0	0
10	तुु गलड	0	1	1
11	डलवलनी	0	0	0
12	डलढडल	0	0	0
13	वलुलडगढ	0	0	0
14	डेवलल डहलरलकडुर	0	0	0
15	डरीदलडलद	0	0	0
16	डलवल	0	1	1
17	हसनडुर	0	0	0
18	हथीन	0	0	0

19	फतेहाबाद	2	2	4
20	रतिया	0	1	1
21	टोहाना	0	1	1
22	भटटूकलां	1	0	1
23	नूहं	0	0	0
24	तावडू	0	0	0
25	फिरोजपुर झिरका	0	0	0
26	गुउगांव	0	0	0
27	सोहना	0	0	0
28	पटौदी	1	0	1
29	हिसार	0	0	0
30	आदमपुर	0	0	0
31	धिराय	1	0	1
32	नारनौंद	0	2	2
33	हांसी	0	1	1



34	बरवाला	0	0	0
35	बादली	0	1	1
36	साल्हावास	2	1	3
37	बेरी	0	4	4
38	झज्जर	0	2	2
39	बहादुरगढ	0	1	1
40	जुलाना	2	3	5
41	उचाना कलां	0	0	0
42	सफीदो	1	1	2
43	जींद	0	2	2
44	नरवाना	0	0	0
45	कलायत	0	0	0
46	राजौंद	2	1	3
47	गुहला	2	2	4
48	पुंडरी	0	0	0

49	कैथल	0	1	1
50	पाई	0	3	3
51	असंध	1	0	1
52	नीलोखेडी	0	1	1
53	इन्द्री	1	2	3
54	घरौंदा	0	0	0
55	करनाल	0	0	0
56	जुडला	0	2	2
57	पेहवा	1	2	3
58	भाहबाद	2	2	4
59	थानेसर	0	0	0
60	अटेली	0	0	0
61	नारनौल	0	0	0
62	महेन्द्रगढ	0	1	1
63	कालका	0	0	0

64	समालखा	4	2	6
65	पानीपत	0	0	0
66	नौलथा	2	4	6
67	जाटूसाना	0	0	0
68	रेवाडी	0	1	1
69	बावल	0	1	1
70	हसनगढ	3	3	6
71	रोहतक	0	0	0
72	कलानौर	1	0	1
73	महम	4	5	9
74	किलोई	0	3	3
75	ऐलनाबाद	0	0	0
76	सिरसा	0	0	0
77	डबवाली	0	0	0
78	दडबाकलां	0	1	1

79	रोडी	0	0	0
80	बरौदा	0	0	0
81	सोनीपत	0	0	0
82	राई	0	0	0
83	गोहाना	1	0	1
84	कैलाना	1	1	2
85	रोहट	0	3	3
86	यमुनानगर	0	0	0
87	रादौर	0	0	0
88	सढौरा	0	1	1
89	छछरौली	1	1	2
90	जगाधरी	0	1	1
91	<b>कुल</b>	<b>37</b>	<b>75</b>	<b>112</b>

निंदा प्रस्ताव/ उसका वापिस लेना

15:00 बजे

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैने और हमारे साथियो ने एक निंदा प्रस्ताव आपकी सेवा मे भेजा है। (विघ्न)

**Mr Speaker:** Hon'ble Member, Please maintain silence.

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, इस सदन की मर्यादा होती है कि पहले दिन जब सदन बैठता है कि उस दिन सदन के अन्दर देश और हमारे प्रदेश की जो बड़ी हस्तियां दुर्घटनाओं में या आकस्मिक निधन से हमें हमें आ के लिए छोड़कर चली जाती है उनके बारे में भाग्य प्रस्ताव इस सदन में पारित किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख की बात है कि पहली मर्तबा इस हरियाणा की विधानसभा में इस मर्यादा से हटकर इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने जानबूझ कर एक ऐसा बर्ताव किया जिसकी हमें निंदा करनी चाहिए। जब छह तारीख को यह सदन इस देश की महान विभूतियों को श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा था जिसमें हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री आर वेंकटरमन, पूर्व प्रधान मंत्री श्री वि वनाथ प्रताप सिंह और हमारे ही अपने प्रदेश के बहुत बड़े महान सपूत जो संविधान सभा के आखिरी जीवित सदस्य बचे थे वे भी हमें छोड़कर चले गये हैं। उस वक्त हमारे कई माननीय सदस्यों ने लिखित प्रस्ताव भेजा। मुंबई के अंदर जो निर्दोश लोगों की हत्या हुई और असम इत्यादि में कई बम विस्फोट की घटनाएं हुई, मर्यादा के मुताबिक यह सदन हमें आ दिवंगतों को श्रद्धासुमन अर्पित करता है। अध्यक्ष महोदय, यकीन

नहीं आता कि छह फरवरी को किस तरीके से इस सदन के अंदर हरियाणा के पूर्व प्रधानमंत्री श्री औम प्रकाश चौटाला जी व दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल जी वापस चले गए। इससे जाहिर होता है कि या तो वे मात्र टी ए डी ए के बारे में सोचकर यहां आए और औम प्रकाश चौटाला जी और उनकी पार्टी के सभी माननीय सदस्य जो कि राज्यपाल के अभिभाषण के वक्त यहां मौजूद थे और जब उसके बाद अध्यक्ष महोदय ने अपने सदन को आधे घण्टे के बाद दोबारा इकट्ठा होने की इजाजत दी क्योंकि भाक प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी। उस मौके पर हमारे विपक्ष के ये साथी यहां सदन में मौजूद नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, यह हम सबके लिए भार्म की बात है और हरियाणा प्रदेश की जनता ने भी इस बात का बहुत बुरा माना है कि चौटाला जी और उनकी पार्टी के सदस्यों को व भजन लाल जी को ऐसा क्या हो गया था कि चौटाला जी और उनकी पार्टी के सदस्यों को व भजन लाल जी को ऐसा क्या हो गया था कि एक तरफ चौधरी रणबीर सिंह जी जैसी बड़ी हस्ती जो संयुक्त पंजाब में मंत्री रहे, हरियाणा में भी मंत्री रहे, भाखड़ा जैसे महत्वपूर्ण डैम का जिनकी निगरानी में निर्माण हुआ, जिनके समय में गुडगांव कैनल बनी, जो संविधान सभा के सदस्य रहे। अध्यक्ष महोदय, वे लोकसभा और राज्यसभा के भी सदस्य रहे और वे इस सदन के नेता चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के पिता भी थे। अध्यक्ष महोदय, यह हमारी सभ्यता है कि बुजुर्गों में और देश की सभ्यता में सबका सांझा अधिकार होता है। बुजुर्ग के प्रति हर किसी की इज्जत का सवाल होता है। श्री औम प्रकाश चौटाला

जी और इनकी पार्टी के सदस्यों ने एक दुर्भावना से बीमार मानसिकता का परिचय दिया है और इस तरह की दुर्भावना के कारण ये जान बुझकर सदन में नहीं आये। उस दिन दे आ की महान विभूतियों को ये श्रद्धांजलि नहीं देना चाहते थे। अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने इन माननीय सदस्यों को चुनकर भेजा है उन लोगों का इन्होंने अपमान किया है। विधान सभा में ये सदस्य जिन क्षेत्रों से चुनकर आये हैं उन क्षेत्रों के लोगों को यह उम्मीद होता है कि उनके नुमायंदे दे आ की महान विभूतियों को उनके इलाके के लोगों की तरफ से सदन में श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, श्री वी पी सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए तो श्री औम प्रका आ चौटाला जी को सदन में आना चाहिए था क्योंकि जब वे दे आ के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उनकी पार्टी के छह संसद सदस्यों को केन्द्र में मंत्री बनाया था। उन्होंने उस समय स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी को उप प्रधान मंत्री बनाया था और श्री औम प्रका आ चौटाला जैसे इन्सान को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया था इसलिए उनको तो श्री वी पी सिंह जी के भाोक प्रस्ताव में शामिल होना चाहिए था।

**डा० सु गीला इन्दौरा:** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कम से कम भाब्दो का इस्तेमाल तो ठीक रूप में करें आखिर यह सदन है इसमें ठीक भाब्दो का इस्तेमाल होना चाहिए।

**श्री अध्यक्ष:** ठीक है, डा० इन्दौरा जी, अब आप बैठ जाइये। बात तो हो गई है।

**श्री कर्ण सिंह दलाल:** अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भुपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के जो पिताश्री थे वे हरियाणा के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए एक बहुत बड़ी हस्ती थे जो हमें छोड़कर चले गये। उनके भाग्य पर प्रस्ताव पर इस सदन में चर्चा हुई। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने तो यह भी याद नहीं रखा कि जब स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी का निधन हुआ तब अध्यक्ष महोदय आप मैं और हमारे मुख्यमंत्री जी इस सदन के सदस्य हुआ करते थे और चौटाला जी की सरकार हुआ करती थी। उनको अपना बुजुर्ग मानकर उनके अच्छे कामों को याद किया था और हर तरीके से हमने उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए थे। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं अगर आपको याद हो तो कांग्रेस पार्टी ने चौटाला जी के कुर्सी के खिलाफ चौधरी देवी लाल जी के निधन से पहले पानीपत में एक बहुत बड़ी ललकार रैली रखी हुई थी। जब चौधरी देवी लाल जी का निधन हुआ तब हमारे जो आज मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बड़प्पन दिखाते हुए उस ललकार रैली को पोस्टपोन कर दिया था और कहा था कि हमारे बुजुर्ग हमें हमारे देश के लिए छोड़कर चले गये। उनको बुजुर्ग मानकर उन्होंने उनको श्रद्धासुमन अर्पित किये थे। स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी हमारे मुख्यमंत्री जी के खिलाफ रोहतक से चुनाव लड़ा करते थे, चुनाव जीतने के लिए सारे हथकण्डे अपनाया करते थे और हर तरीके का उत्पीड़न किया करते थे। इस अवसर पर हमारे विपक्ष के साथी अपनी छोटी मानसिकता को छिपा नहीं सके। अध्यक्ष महोदय, पर हमारे विपक्ष के साथी तो अपनी छोटी मानसिकता को छिपा नहीं



सके। अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब खुद तो चले गये साथ में अपनी पार्टी के सदस्यों को भी डरा धमकाकर अपने साथ ले गये। इनमें से किसी सदस्य की इतनी हिममत नहीं हुई कि भाजक प्रस्ताव में हिस्सा लें। अध्यक्ष महोदय, मैं 18 साल से इस सदन का विधायक बन कर आ रहा हूँ कई सरकारें मैंने देखी हैं लेकिन इस विधान सभा में इस प्रकार की घटना भाजक इस सदन में पहले कभी नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, इस मामले को सही मायने में प्रिविलेज कमेटी को दिया जाना चाहिए कि किस तरीके से दुर्भावना दिखाकर इन माननीय सदस्यों ने गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया है और इस सदन की अवमानना की है। राजनीति में विधायक आते हैं और चले जाते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जिन्होंने इस देश की सेवा की, जिन्होंने इस देश के अंदर इतने बड़े ओहदे प्राप्त करके लाखों करोड़ों लोगों का भला किया अगर उनके बारे में इस तरह की बात होती है तो ऐसे सदस्यों के खिलाफ अवमानना का एक मामला अलग से बनता है। ऐसे लोगों की तो सदस्यता तक समाप्त कर देनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इनको सामने बुलाकर एडमोनिशन करना चाहिए। ( गोर एवं व्यवधान)

**डा सीता राम: \*\*\*\*\***

**श्री अध्यक्ष:** सीता राम जी, जो भी बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

**श्री कर्ण सिंह दलाल:** अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक बीमार मानसिकता का परिचय दिया है, अपाहिज मानसिकता का परिचय दिया है। अध्यक्ष महोदय, अगर सदन में आप इनके प्रति कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होगा क्योंकि हरियाणा के लोगों के मन में इनके रवैये के प्रति दुःख आया है और लोगों में इनकी साख गिरी है। लोगों ने देखा है कि सदन के अंदर ऐसे लोग पहुंच गए हैं जो हमारे बुजुर्गों और हमारे पूर्वजों के प्रति इस तरीके का अ गौभनीय व्यवहार कर रहे हैं? ( गोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** आप अ गौभनीय या निंदनीय क्या कहना चाहते हैं?

**श्री कर्ण सिंह दलाल:** अध्यक्ष महोदय, यह एक निंदा प्रस्ताव है इसलिए इसको निंदा प्रस्ताव ही मानना चाहिए। अगर आप इजाजत दें तो इनके व्यवहार के बेसिज पर इनके खिलाफ प्रिविलेज में इन भी आना चाहिए और आपको इनके खिलाफ सुओ मोटो एक इन लेना चाहिए और इनको एडमोनि ा करना चाहिए। ( गोर एवं व्यवधान) इनको सिखाया जाए कि सदन में किस तरीके से मर्यादा का पालन करना चाहिए। इन लोगों को हरियाणा के बुजुर्गों के प्रति और देश के बुजुर्गों के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करने चाहिए। ( गोर एवं व्यवधान)

**श्री रामकुमार गौतम:** अध्यक्ष महोदय, \*\*\*\*\*  
( गोर)

डा सीता राम: अध्यक्ष महोदय,  
\*\*\*\*\* ( गोर)

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): डा साहब, राम कुमार गौतम जी आपकी एलायंस पार्टी के वरिष्ठ नेता है। बी जे पी आपकी एलायंस पार्टी है इसलिए इनको बोलने दीजिए। आप किस तरह का धर्म निर्वहन कर रहे हैं? ( गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सीता राम जी, राम कुमार गौतम जी ने पहले हाथ खडा किया था। ( गोर एवं व्यवधान)

डा सीता राम: अध्यक्ष महोदय, दोनों ने इकट्ठे हाथ खडा किया था।

श्री अध्यक्ष: अगर आपने इकट्ठे जवाब देना है तो इकट्ठे बोल लो।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, इनको तो वाक आउट करना है ओर कुछ नहीं करना।

डा सु गीला इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, अगर राजनीति करनी है तो इनकी सुनो और अगर रणबीर सिंह हुडडा जी का सम्मान करना है तो हमारी भी बात सुनी जाए। ( गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: डा साहब, आप एक मिनट बैठें।

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला:** अध्यक्ष महोदय, किसी व्यक्ति का कद किसी के कहने से छोटा या बड़ा नहीं हो सकता।

**डा सीता राम:** अध्यक्ष महोदय, रणबीर सिंह हुड्डा जी सबके लिए सम्मानित थे, वे केवल कांग्रेस पार्टी के ही नेता नहीं थे इसलिए आप हमारी भी बात सुने। हमारे बारे में जो ये रैलोल्यू इन लेकर आए हैं उसके बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं।

**श्री अध्यक्ष:** डा साहब, आप बैठें। यह कोई राजनीति की बात नहीं है। It is people democracy. यह सदन है और आप सब लोग इस सदन के आनॉरेबल मैम्बर हैं। यहां हर मैम्बर को बोलने का बराबर अधिकार है। It is not the parental property of anybody. it is the property of the people, it is the property of the people of the State. आप बताओ कि दलाल साहब ने कहा कि यह अभिमान है या निंदनीय है। (गौर) इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है मेरी भी तो अपनी लिमिटेड रैंज है। अगर कोई मैम्बर बोलने के लिए हाथ खड़ा करता है तो सीरीज से ही मैं सबको बुलवाऊंगा।

**डा सु गीला इन्दौरा:** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल जी यहां एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। (विधन) वह प्रस्ताव निंदा का है या \*\*\*\*\* पर है इस \*\*\*\*\* की।

**श्री अध्यक्ष:** इसमें सरकार की क्या बात है। मैम्बर ने अपनी बात कही है। Where is the Government? It is not the official resolution, it is non official resolution by the private member.

**डा सु गीला इन्दौरा:** चलो किसी की भी मानसिकता है। वह माननीय सदस्य की अपनी मानसिकता है।

**श्री फूल चन्द मुलाना:** अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्र न है। इन्होंने जो \*\*\*\*\* कहा है यह भाब्द कार्यवाही से निकलवा दिया जाए। ( गोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** ठीक है यह भाब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाए। एक आदमी ने अपने हिसाब से बात कही है। न पार्टी जोड़ी है ओर न सरकार जोडा है। एज ए मैम्बर आफ दि हाउस उन्होंने अपनी बात उठाई है।

**डा सु गीला इन्दौरा:** जो बात की है वह \*\*\*\*\* और \*\*\*\*\* का प्रतीक है। अध्यक्ष महोदय, यह क्यों है, यह इसलिए है कि पहले आपने खुद कहा है कि हाउस किसी की बापौजी नहीं है। आपके भाब्दो द्वारा देखा जाए तो यह हाउस जनता का हाउस है और यहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं।

**श्री अध्यक्ष:** \*\*\*\*\* ये भाब्द रिकार्ड न किए जाए।

**डा सु गीला इन्दौरा:** स्पीकर सर, कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि कोई यहां नहीं आ सकता तो ऐसी स्थिति में यहां पर कोई नहीं पूछता।

**श्री अध्यक्ष:** डा इन्दौरा, आनॉरेबल मैम्बर ने केवल एक ही बात पूछी है कि Was it a willful absence, or it was absence by per-chance? आप यह बता दो यह हाउस इस बात को जानना चाहता है।

**डा सु गीला इन्दौरा:** स्पीकर सर, मैं यही बताना चाहता हूं कि अगर हम यहां चर्चा करें चौधरी रणबीर सिंह हुडडा जी की जो की हमारे माननीय मुख्यमंत्री चौ० भुपेन्द्र सिंह हुडडा जी के पिता जी भी हैं, मैं बात खुलकर कहना चाहूंगा कि चौ० रणबीर सिंह हुडडा जी को जो व्यक्तित्व था जिसे उन्होंने संवारा और सजाया वह उनकी खुद की देन थी। निःसन्देह वे एक महापुरुष थे, संविधान सभा के सदस्य भी थे, संयुक्त पंजाब के समय वे विधान सभा के सदस्य और मंत्री थे, लोक सभा के सदस्य भी रहे। वे एक उच्च राजनेता होने के साथ साथ एक चिंतक और समाज सुधारक भी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि वे कांग्रेसी थे लेकिन कांग्रेस में रहते हुए भी वे सामाजिक चिंतन में गहरी आस्था रखते थे। अगर मानसिकता की बात की जाये तो जब चौधरी रणबीर सिंह जी बीमार थे तो स्वयं चौ० औम प्रकाश चौटाला जी उनका हाल चाल जाने के लिए गये थे जो की सामाजिक सभ्यता की बात है। अगर आप दूसरी बात करे तो

निधन के बाद जब चौधरी रणबीर सिंह जी का संस्कार हुआ उस वक्त भी चौधरी औम प्रकाश चौटाला जी पहले पहुंच गये थे और सबसे आखिर तक वहां रहे। इसलिए यहां पर यह कैसे मान लिया गया कि वे हाउस से विलफुली अबसैंट थे। आज भी हमारे चौ० रणबीर सिंह हुडडा जी माननीय व्यक्तित्व है।

**श्री अध्यक्ष:** मिस्टर इन्दौरा, यह हाउस यह जानना चाहता है कि आपकी पार्टी के नौ के नौ मैम्बर गवर्नर एड्रेस के समय हाजिर थे उसके बाद भी मैम्बर्ज यहा पर हाउस में प्रैजेंट रहे हैं लेकिन after half an hour as and when the obituary references started members of the Indian National Lok Dal was not present in the House. यह हाउस यह बात जानना चाहता है इसमें कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं है। चाहे कोई किसी भी पार्टी का सदस्य रहा हो, चाहे कोई किसी का दुःख मन भी रहा हो अगर उसका स्वर्गवास हो जाता है तो हम सभी को उसकी आत्मा की भांति के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। यह हमारी व्यवहार कृपा लता का प्रतीक है और हमारा यह सामाजिक दायित्व भी बनता है। यहां ओबीचुअरी रैफ्रेंसिज के दौरान आप अपनी पार्टी के सदस्यों के उपस्थित न रहने का कारण बता दें।

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला:** अध्यक्ष महोदय, यह एक व्यवस्था का प्रश्न है। गवर्नर एड्रेस के बारे में माननीय इन्दौरा जी जो कुछ भी कहना चाहे कह ले इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने एड्रेस में क्या कहा यहां

यह चर्चा का विषय नहीं है। ( गोर एवं व्यवधान) इन्दौरा जी, आप एक मिनट हमारी बात सुनने का मादा तो रखिए हम तो आपकी बात सुनने के लिए चुप बैठे रहे हैं। हम जाते हैं कि अब आप जाने वाले हैं और जाने का बहाना ढुंढ रहे हैं लेकिन हम आपको जाने का मौका नहीं देंगे। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने हरियाणा के एक सच्चे सपूत को अपने एड्रेस में श्रद्धांजलि दी है तो इसमें क्या गलत है। पूरा सदन उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ओबीचुएरी रैजोल्यूशन लेकर आया था इसमें क्या गलत बात है। इन्दौरा जी केवल यह बताने के लिए खड़े हुए थे कि ये उस समय क्यों भाग कर चले गये थे। उस समय ये क्यों नहीं आये। इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है लोकदल के साथी उस समय हाउस में हाजिर रहकर सरकारी परम्पराओं का उल्लंघन करके यहां से भाग गये और जब एक माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया तो अब ये उस बात को घुमा रहे हैं जबकि इनको सीधा जवाब देना चाहिए कि ये अमुक की वजह से नहीं आये। इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। लोकदल के साथी उस समय हाउस में हाजिर रहकर सरकारी परम्पराओं का उल्लंघन करके यहां से भाग गये और जब एक माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया तो अब ये उस बात को घुमा रहे हैं जबकि इनको सीधा जवाब देना चाहिए कि अमुक कारण की वजह से नहीं आये। ये लोग इस बात का सही जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर ये इस बारे में अपना सही जवाब दें तो माननीय



सदस्य की जिज्ञासा भांत हो जायेगी और वे अपना प्रस्ताव वापिस ले लेंगे।

**Mr Speaker:** Nothing is to be recorded. डा साहब, यहां एक बात यह आई है कि इनलो members were not present in the House at the time of the obituary references. आप इस बारे में कारण बता दें कि आप सदन में किस कारण से नहीं आये उसके बाद तो बात ही खत्म हो जाएगी। ( गोर एवं व्यवधान)

**डा० सु गीला इन्दौरा:** अध्यक्ष महोदय, चौधरी रणबीर सिंह हुडडा के प्रति हमारे दिल में भी बहुत आदर है। हाउस में उपस्थित होना दूसरी बात है।

**श्री अध्यक्ष:** इन्दौरा जी, माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि आप भाोक प्रस्ताव के समय क्यों सदन में उपस्थित नहीं थे। आज आप चार लोग उपस्थित हो अगर उस दिन एक सदस्य भी होता तो यह प्र न ही नहीं उठता। उस दिन विलफुल आबिच्युरी में एबसैंट थे। ( गोर एवं व्यवधान)

**डा० सु गील इन्दौरा:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि माननीय चौधरी रणबीर सिंह जी का जो चिंतन था अगर माननीय सदस्य अपनी विचारधारा को उनके चिंतन की दिा में मोड दे तो समाज के उत्थान के काम आ सकता है। अगर इनको माननीय चौधरी रणबीर सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो उनके विचारों पर चिंतन करना कि ये

मानसिकता की बात करें ( गोर एवं व्यवधान) हम हर जगह उपस्थित थे ये केवल सदन की बात करते हैं।

**श्री अध्यक्ष:** डा0 साहब, इन्होंने यह पूछा है कि श्रद्धांजलि के समय आप उपस्थित क्यों नहीं थे। ( गोर एवं व्यवधान)

**श्री रामकुमार गौतम:** अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी श्री कर्ण सिंह दलाल ने जो यह निन्दा प्रस्ताव सदन के सामने पे ा किया है, यह बहुत सही प्रस्ताव है और इन लोगों की जितनी निंदा की जाये उतनी कम है। असल मे तो ये अपराधी लोग हैं और इनका इस तरह की सभाओ से कोई लेना देना नहीं है। इस दे ा के इतने महान लोग चले गये, इस दे ा के पूर्व राष्ट्रपति डा0 आर0 वेंकटरमन चले गये और पूर्व प्रधानमंत्री श्री वि वनाथ प्रताप सिंह जी चले गये लेकिन इन लोगो के पास भाोक प्रस्ताव मे भामिल होने का भी समय नहीं है। ( गोर एवं व्यवधान)

**डा0 सीता राम:** अध्यक्ष महोदय, अपराधी तो ये खुद हैं। जिन लोगों से चुनकर आये हैं अब वे इनको देख रहे हैं। ( गोर एवं व्यवधान)

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला:** अध्यक्ष महोदय, ये किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। ( गोर एवं व्यवधान) डा सीता राम जी, भारतीय जनता पार्टी आपकी एलायन्स पार्टी रही है, उसके

सदस्य अपनी बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के आपके साथी आपकी कलाई और पोल खोल रहे हैं। ( गोर एवं व्यवधान)

**डा० सीता राम:** अध्यक्ष महोदय, अपराधी कैसे कह सकते हैं। ( गोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** डा सीता राम जी, आप अपनी सीट पर बैठें। ( गोर एवं व्यवधान)

**श्री रामकुमार गौतम:** अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी जलालत ओर क्या हो सकती है कि ये लागे टी० ए०, डी० ए० लेकर चले गये लेकिन श्रद्धांजलि में शामिल नहीं हुए। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। इनकी जितनी भी निन्दा की जाये कम है। ( गोर एवं व्यवधान)

**डा० सीता राम:** आप अपना तरीका सुधारो। आपको तो असैम्बली से बाहर कर देना चाहिए। ( गोर एवं व्यवधान)

**Mr Speaker:** It is not the way. (Interruptions and noises)

**डा० सु गील इन्दौरा:** अध्यक्ष महोदय, ये कैसे बोलते हैं?

**श्री रामफल चिडाना:** अध्यक्ष महोदय, ये अपराधी कैसे कह सकते हैं? ( गोर एवं व्यवधान)

श्री रामकुमार गौतम: अध्यक्ष महोदय, यह बात तो सारी दुनिया जानती है। (विधन)

**Mr Speaker:** Chiran Ji, please take your seat. I allow you to speak. (Noises and interruptions). Chirana Ji, please go to your seat. It is not the way. (Noises and Interruptions)

श्री रामफल चिडाना: अध्यक्ष महोदय, ये तो सदन में बोलने के ही लायक नहीं है।

श्री अध्यक्ष: मिस्टर चिडाना, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, आप अपनी सीट से बोलिए। ( गोर एवं व्यवधान)

श्री रामकुमार गौतम: अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति हाउस में न आये तो कोई बात नहीं है। अगर ये आ भी गये थे तो दस्तखत करके जाना नहीं चाहिए था। उसके बाद इतने महान लोगों को श्रद्धांजलि देने का इतना महान कार्य चल रहा था। डा० वैंकेट रमन कितने बड़े नेता थे, वि वनाथ प्रताप सिंह को श्रद्धांजलि देनी थी उनकी भाोक सभा चल रही थी। चौधरी रणबीर सिंह इतने बड़े फ्रीडम फाईटर थे उनके भाोक प्रस्ताव बदस्तुर थे। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि इन लोगों की, जो यहां आकर चले गए हैं, निंदा की जाए। इनके खिलाफ भाोक प्रस्ताव में भाामिल न होने पर निंदा प्रस्ताव पास होना चाहिए और हाउस में आप ऐसा प्रस्ताव ला सकते हैं कि यहां पर आकर चले गए उनकी निंदा की जाए। सभी

ने यहां से चले जाना है, भाोक प्रस्ताव मे जो लोग हाजिर नही हुए और बेकायदगी की बात की है वे इसके लिए माफी मांगे। अगर उन्होंने भाोक प्रस्तावो मे हिस्सा नही लेना था तो उनको यहां पर आने की जरूरत ही नही थी वे अपने घरों पर ही रहते। अगर यहां पर आकर इतने महान कार्य में हिस्सा नही लेना था तो यहां किस लिए आए, केवल कुछ पैसे के लिए यहां पर आए थे। चौ० कर्ण सिंह दलाल जी का जो प्रस्ताव है उसका पूरा समर्थन करता हूं कि इन लोगों की घोर निंदा की जाए।

**डा० सीता राम:** अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, \*\*\*\*\*

**श्री अध्यक्ष:** डा० साहब, यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नही है इसलिए आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) Nothing is to be recorded. (Interruptions) आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) समय बहुत ही कम है, काम ऐसे नही चलेगा। प्लीज आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न)

**प्रो० छतर पाल सिंह:** अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी चौधरी कर्ण सिंह दलाल जी ने जो प्रस्ताव हाउस के सामने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है उसमे अगर किसी के यहां कोई भी भाोक हो जाए या कोई व्यक्ति दुनिया से चला जाए, उसका निधन हो जाए तो सरबवाल मे उसके सम्मान मे उस बात को लेते है। आप जानते है कि जिनके बीच

आपस में गोलियाँ चल रही हों, हत्या हुई हो या केसिज चल रहे हों और दुःख मन के घर में भी अगर कोई डैथ हो जाती है तो किसी भी स्टेज पर उसमें कोई व्यक्ति यह नहीं कहता है कि अच्छा हुआ है और उसके दोलड़े पर बैठता है। स्पीकर सर, कोई नया सदस्य किसी वजह से हाउस में न आ पाए और किसी गम्भीर तकलीफ में हो तो अलग बात है लेकिन आबिच्युरी रैफरेंसिज में वर्तमान में सभी सीनियर लीडर्स को हाउस में हाजिर रहना चाहिए ताकि वह अपनी श्रद्धांजलि दे सकें। स्पीकर सर, यह बात सही है कि सभी सदस्यों को इस अवसर पर बोलने का मौका नहीं मिल पाता है लेकिन अपोजीटिव के जो सीनियर साथी बैठे हैं कम से कम उनको अपनी बात कहने का समय होता है। स्पीकर सर, आप भी इस सभ्यता से परिचित हैं। सारा हाउस जानता है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे अफसोस पर या ऑबिच्युरी रैफरेंस पर नहीं जाता है तो समाज उसकी निंदा करता है, चर्चा करता है कि देखो फलाने को आज भार्म आनी चाहिए कि वह आज के दिन भी नहीं गया जबकि उसको जाना चाहिए था। ये सारी बातें अपने समाज में चर्चा का विषय रहती हैं। स्पीकर सर, इस बारे में भजन लाल जी के बारे में जिक्र हुआ कि वो सिगनेचर मारकर चले गये। स्पीकर सर, वे हाउस के अंदर आकर आधा घंटा और बैठ जाते तो उनके प्रति भावनीय बात कही जाती। देश के पूर्व राष्ट्रपति आज हमारे बीच में नहीं रहे उनके प्रति ऑबिच्युरी थी, देश के प्रधान मंत्री जिन्होंने अपनी पार्टी में रहते हुए ही चुनौतीपूर्ण कार्य किया और फिर प्रधान मंत्री के ओहदे पर आए, वे एक रैवोल्यूशनरी व्यक्ति

के रूप में थे उनके बारे में ऑबिच्युरी आई थी। स्पीकर सर, इस दे 1 का संविधान हमारे लिए धर्म ग्रंथ है और हम इसके अंदर पूरी आस्था रखते हुए पूरे दे 1 की पापुले 1न के विकास की बात सोचते हैं। उसके एकमात्र अलाईव सदस्य आज हमारे बीच में नहीं रहे और को-इन्सीडेंटली वे इस हाउस के नेता के पिताश्री थे। ये दोनों ही बातें उस दिन की महत्ता को बहुत बढ़ाते थे। इसके अलावा भाहिदो, स्वतंत्रता सेनानी और हमारे कुछ सदस्यों के रिलेटिवज़ जो हमारे बीच में नहीं रहे उनके नाम भी ऑबिच्युरी में शामिल थे। यहां पर गवर्नर एड्रैस के बाद विशेष रूप से अपोजि 1न के सभी सदस्य हाउस के अंदर उपस्थित नहीं रहे। स्पीकर सर, ऑबिच्युरी रैफरेंसिस के बाद हमारे अपोजि 1न के कुछ सदस्य हाउस में दिखे। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी तरफ से ऑबिच्युरी रैफरेंसिस के बारे में कोई मैसीव डिस्मिशन लिया गया हो। एक मैसेज कही प्रिवेल हुआ, ऐसी स्मैल पूरे हाउस को आई। अपोजि 1न का कार्ड भी सदस्य यहां पर नहीं था, सब के सब हाउस से नदारद थे।

**श्री अध्यक्ष:** गौतम साहब तो हाउस में थे।

**प्रो० छतर पाल सिंह:** स्पीकर सर, गौतम साहब तो उनसे इत्फाक नहीं रखते हैं हालांकि इनकी पार्टी का इनेलो के साथ समझौता हुआ है। (विधन) डाक्टर सु गील इन्दौरा जी, मैं सारी सयानी बातें कहूंगा, आप सुनें तो सही। (विधन) डाक्टर साहब, कोई भी भाब्द ऐसा नहीं आएगा जिस पर आप आपत्ति कर

सको। लेकिन स्पीकर सर, ने जो इ तारा किया है और आपकी पार्टी के नेतृत्व में और उनकी पार्टी के नेतृत्व में जो फैसला लिया है उसके बारे में आप अखबारों में पढ़ते हैं। राम कुमार गौतम जी यहां पर भी जो बोलते हैं वह भी आप सुनते और देखते हैं। इनहोंने अपनी पार्टी की विचारधारा का आपकी पार्टी की विचारधारा के साथ मेल नहीं है उसके बारे में कहा है। यह तो इनकी हिम्मत है कि इन्होंने पार्टी में रहते हुए, पार्टी के विधायक होने के बावजूद विचारधारा के आधार पर पार्टी के फैसले का विरोध किया है। आज जितनी भी पोलिटिकल पार्टियां हैं, यदि उनकी इंटरनल डैमोक्रेसी मजबूत हो जाए तो आप जितने साथी यहां पर बैठे हुए हैं और आपके साथी जब आपस में बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपकी आत्माएं भी मजबूत हो जाएंगी। आप कई बार उनकी बातें मानने को मजबूर हो जाते हैं। (विधन)

**डा० सु गील इन्दौरा:** स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि बात का बतंगड चाहे जितना भी बना लो, वह अलग बात है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारी ऐसी कोई मं ता नहीं थी This is just a co-incidence. (विधन)

**Mr Speaker:** Nothing is to be recorded.

**Dr. Sushil Indora:** \*\*\*\*\*

**श्री अध्यक्ष:** डाक्टर साहब, इस बाप पर कोई राजनीति करे यह ठीक नहीं है। मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई राजनीति नहीं है। इस बारे में हाउस की एक इन्टेंशन थी



कि इतना बड़ा हुआ था (विधन) चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी बोलना चाहते हैं आप सभी एक मिनट बैठ जाएं। (विधन) डाक्टर इन्दौरा जी, आप लोग अपनी सीटों पर बैठ गए हैं आप भी बैठ जाएं। (विधन)

**डा० सु गील इन्दौरा:** सर, इन्होंने तो चौधरी रणबीर सिंह को बहुत सस्ता बना दिया। वे तो बहुत महान नेता रहे हैं।

**वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह):** स्पीकर सर, बड़ी सिम्पल बात है। कर्ण सिंह दलाल जी ने जो प्रस्ताव रखा है या कहिए कि उन्होंने जो बात कही है उस पर सीता राम जी जो कि इनेलो के डिप्टी लीडर हैं। (विधन) डा० इन्दौरा है कोई बात नहीं वे भी बैठे हुए हैं ये इस बारे में दो भावों में बता दें कि इनका अबसैन्ट होना अन-इंटेंशनल था या ये जानबूझकर अबसैन्ट हुए थे? इससे सारी बात खत्म हो जाएगी।

**Dr. Sushil Indora:** Sir, this was not intentional. It was co-incidental and it was not our intention.

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला:** स्पीकर सर, मेरी एक दरखास्त है। डाक्टर साहब ने चौधरी बीरेन्द्र सिंह के खड़ा होने से पहले बड़ा स्पष्ट कह दिया कि It was co-incidental and it was not our intention. इसलिए मैं माननीय सदस्य को कहूंगा कि in light of what Dr. Indora has said. I would request Shri Karan Singh Dalal to withdraw his resolution.

**श्री अध्यक्ष:** ठीक है, दलाल साहब, आप इस बारे में क्या चाहते हैं?

**श्री कर्ण सिंह दलाल:** स्पीकर सर, माननीय चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है इन्दौरा साहब मात्र बहाना बनाकर अगर ऐसी बात कहे तो ठीक नहीं है लेकिन अगर इनकी इंटैग्रेटी सही है तो माननीय चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने जो बात कही है वह बहुत ही अच्छी बात है इसलिए मैं इस चर्चा को यही समाप्त करने के लिए निवेदन करता हूँ।

**डा० सु गील इन्दौरा:** स्पीकर सर, मैंने पहले ही कह दिया है कि यह हमारी इंटैग्रेटी नहीं थी, यह महज को-इंसीडेंटल था।

**श्री अध्यक्ष:** डा इन्दौरा, चूंकि वह बात हाउस को अभिमान लगी इसलिए हाउस के मैम्बरज और मैं खुद भी यह जानना चाहते थे कि यह इंटैग्रेटी नहीं था या को-इंसीडेंटल था। जो व्यवहार किया गया वह अभिमान था। हाउस में इतना बड़ा इन्फोर्मेन्ट ऑबिच्युरी रैफरेंस जोकि राष्ट्रीय नेताओं के बारे में था, आया था लेकिन चलो, अब यह मामला खत्म हो गया।

**कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट में संशोधन**

**प्रो० छतर पाल सिंह:** अध्यक्ष महोदय, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे माननीय चीफ मीनिस्टर साहब के पिताश्री रणबीर सिंह जी की कल दोपहर को रस्म पगड़ी है और सभी माननीय सदस्य

वहां जाना चाहते हैं। मेरी गुजारि है कि यदि कल हाउस की कार्यवाही स्थगित कर दे तो सभी मैम्बर्ज वहां जा सकते हैं। यह सभी सदस्यों की भावना है कि कल हाउस की बैठक नहीं होनी चाहिए।

**आवाजें:** ठीक है जी।

**Mr Speaker:** Is it the sense of the House that there will be no sitting of this House on 11<sup>th</sup> February, 2009 and the business which was to be transacted on 11<sup>th</sup> February, 2009 will now be taken up in the first sitting of the House of Friday, the 13<sup>th</sup> February, 2009.

**Voices:** Yes, yes.

**Mr Speaker:** There will be no sitting of this House on 11<sup>th</sup> February, 2009 and the business which was to be transacted on 11<sup>th</sup> February, 2009 will now be taken up in the first sitting of the House on Friday, the 13<sup>th</sup> February, 2009.

**डा सीता राम:** स्पीकर सर, 12 तारीख को सै उन कितने बजे आरम्भ होगा?

**श्री अध्यक्ष:** 12 फरवरी, 2009 को सै उन 2:00 बजे (अपरान्ह) आरम्भ होगा।

**Dr. Sushil Indora:** Sir, we have no objection.

**श्री अध्यक्ष:** ठीक है, हाउस की सहमति के अनुसार कल दिनांक 1192.2009 को सदन की बैठक नहीं होगी। दिनांक 11.2.

2009 का बिजनैस दिनांक 13.2.2009 को प्रथम बैठक में टेकअप कर लिया जाएगा। (विधन) अभी बी० ए० सी० की रिपोर्ट आ रही है उसमें यह अमेंडमेंट इन्कलूड कर लेंगे।

## घोशणाएं

### (क) अध्यक्ष द्वारा

#### (i) चेयरपर्सन्स के नामों की सूची

**Mr Speaker:** Hon'ble Member, under Rule (13) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following Members to serve on the panel of Chairpersons:-

1. Sh Karan Singh Dalal, M.L.A
2. Sh Shadi Lal Batra, M.L.A
3. I. G. Sher Singh, M.L.A
4. Dr Sushil Indora, M.L.A

#### (ii) अनुपस्थिति के संबंध में सूचना

**Mr Speaker:** Hon'ble Member, I am to inform you that I have received a letter dated 10<sup>th</sup> February, 2009 from Shri Naresh Yadav, M.L.A vide which he has informed that due to road accident, he will not be able to attend the Session of Haryana Vidhan Sabha on 10<sup>th</sup> February, 2009.

#### (iii) अनुपस्थिति की अनुमति

**Mr Speaker:** Hon'ble Member, I have received a letter dated 10<sup>th</sup> February, 2009 from Shri Yadvendra Singh, M.L.A which reads as under:-

“Dear Sir,

Leave of Absence

I shall not be able to attend the Vidhan Sabha Session on 10<sup>th</sup>, 11<sup>th</sup> and 13<sup>th</sup> February, 2009. due to personal reasons.

I request you to kindly grant me leave of absence for the above dates.

Thanking You.”

**Mr Speaker:** Is it the pleasure of the House that leave of absence be granted to Shri Yadvendra Singh, MLA to remain absent for 10<sup>th</sup>,. 11<sup>th</sup> and 13<sup>th</sup> February, 2009?

**Voices:** yes, yes.

**Mr Speaker:** The leave is granted.

(ख) सचिव द्वारा

**Mr Speaker:** Now, the Secretary will make an announcement.

**सचिव:** महोदय, मैं उन विधेयको को दाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने मार्च, 2008 तथा दिसम्बर 2008 में हुए सत्रों में पारित किए थे तथा जिन पर

राज्यपाल महोदय ने अपनी अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूँ।

### **MARCH SESSION, 2008**

1. The Punjab Agricultural Procedure Markets (Haryana Amendment) Bill, 2008.

2. Guru Jambheshwar University of Science and Technology Hisar (Amendment) Bill, 2008.

### **SEPTEMBER SESSION, 2008**

1. Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences Rohtak (Amendment) Bill, 2008.

2. The Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill, 2008.

3. The Haryana Regulation of Property Dealers and Consultatnt Bill, 2008.

4. The Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Second Amendment) Bill, 2008.

5. The Haryana Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Bill, 2008.

6. The Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 2008.

7. The Haryana Municipal Public Disclosure Bill, 2008.

8. The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2008.

9. The Haryana Town Improvement Bill, 2008.

10. The Haryana Municipal Citizens' Participation Bill, 2008.

11. The Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill, 2008.

12. The Haryana Tax on Entry of Goods into Local Areas (Amendment) Bill, 2008.

### कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट

**Mr Speaker:** Hon'ble Members, now I request the time table of the various business fixed by the Business Advisory Committee.

The Committee met at 11:00 A.M. on Friday, the 6<sup>th</sup> February, 2009 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs, the Assembly whilst in Session, shall meet on Monday at 2:00 P.M. and adjourn at 6:30 P.m and on Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday will meet at 9:30 A.M and adjourn at 2:00 P.M without question being put.

On Friday, the 6<sup>th</sup> February, 2009 the Assembly shall meet immediately half an hour after the conclusion of the Governor's Address and adjourn after the conclusion of Obituary References. On Tuesday, the 10<sup>th</sup> February, 2009. the Assembly shall meet at 2:00 P.M and adjourn at 6:30 P.M without question being put.

On Thursday, the 12<sup>th</sup> February, 2009, the assembly shall meet at 2:00 P.m and adjourn at 6:30 P.M without question being put. On Friday, the 13<sup>th</sup> February, 2009. the Assembly shall meet at 9:30 A.M and adjourn at 1:30 P.M. without question being put and the Assembly shall meet again at 2:00 P.M and adjourn at 6:30 P.M without question being put. On Friday, the 20<sup>th</sup> February, 2009 the Assembly shall meet at 2:00 P.M and adjourn after the conclusion of the Business entered in the List of Business.

The Committee, after some discussion, further recommends that the Business on 6<sup>th</sup>, 10<sup>th</sup>, 13<sup>th</sup>, 16<sup>th</sup> and 18<sup>th</sup> and 20<sup>th</sup> February, 2009 be transacted by the Sabha as under:-

The House will meet immediately half an hour after the conclusion of the Governor's Address on the 6 <sup>th</sup> February, 2009.	1. Laying a copy of the Governor's Address on the Table of the House.
	2. Obituary References.
Saturday, the 7 <sup>th</sup> February, 2009	Holiday
Sunday, the 8 <sup>th</sup> February, 2009	Holiday
Monday, the 9 <sup>th</sup> February, 2009	Holiday.



Tuesday, the 10 <sup>th</sup> February, 2009 (2:00 P.M)	1. Questions Hour.
	2. Presentation and adoption of First Report of Business Advisory Committee.
	3 Papers to be laid/re-laid on the Table of the House.
	4. Presentation of 4 <sup>th</sup> Preliminary Report of the Committee of Privileges and extension of time for presentation of the final report thereon.
	5. Presentation of Preliminary Report of the Committee of the House
	6. Discussion of Governor's Address.
Wednesday, the 11 <sup>th</sup> February, 2009 (9:30 A.M)	Off day.
Thursday, the 12 <sup>th</sup> February, 2009 (2:00 P.M)	1. Question Hour.
	2. Non-official Business.
Friday, the 13 <sup>th</sup> February,	1. Questions Hour.

2009 (9:30 A.M) (1 <sup>st</sup> Sitting)	
	2. Motion under rule 121.
	3. Resumption of discussion on Governor's Address and Voting on motion of Thanks.
	4. Presentation Discussion and Voting on Supplementary Estimates (2 <sup>nd</sup> Installment) for the year 2008-2009 and Report of the Estimates Committee thereon.
	5. Resumption of Discussion on Special Report of the Committee of Privileges.
Friday, the 13 <sup>th</sup> February, 2009 (2:00 P.M) (2 <sup>nd</sup> Sitting)	Presentation of Budget Estimates for the year 2009-2010.
Saturday, the 14 <sup>th</sup> February, 2009	Holiday
Sunday, the 15 <sup>th</sup> February, 2009	Holiday
Monday, the 16 <sup>th</sup> February, 2009 (2:00 P.M)	1. Questions Hour.
	2. Presentation of Reports of

	the Assembly Committees.
	3. Discussion on Budget Estimates for the year 2009-2010.
Tuesday, the 17 <sup>th</sup> February, 2009 (9:30 A.M)	1. Question Hour.
	2. Resumption of discussion on Budget Estimates for the year 2009-2010.
Wednesday, the 18 <sup>th</sup> February, 2009 (9:30 A.M)	1. Questions Hour.
	2. Resumption of discussion on Budget Estimates for the year 2009-2010 and reply by the Finance Minister thereon.
	3. Discussion and Voting on Demands for Grants on Budget Estimates for the yer 2009-2010.
Thursday, the 19 <sup>th</sup> February, 2009	Holiday
Friday, the 20 <sup>th</sup> Februayr, 2009	1. Questions Hour.
	2. Motion under Rule 15

	regarding Non-stop sitting.
	3. Motion under Rule 16 regarding adjournment of the Sabha sine-die.
	4. Papers to be laid, if any.
	5. Presentation of Reports of the Assembly Committees.
	6. The Haryana Appropriation Bill in respect of Supplementary Estimates (2 <sup>nd</sup> Instalment) for the year 2008-09.
	7. The Haryana Appropriation Bill in respect of Budget Estimates for the year 2009-2010.
	8. Legislative Business.
	9. Any other Business.

**Mr Speaker:** Now, the Parliamentary Affairs minister will move the motion that this House agrees with the recommendation contained in the first Report of the Business Advisory Committee.

**Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala):**  
Sir, I beg to move-

That this House agrees with the recommendations contained in the first Report of the Business Advisory Committee with the modification that the sitting fixed for the 11<sup>th</sup> February, 2009 will be off day and the business fixed for 11<sup>th</sup> February, 2009 will be taken up on first sitting of the 13<sup>th</sup> February, 2009.

**Mr Speaker:** Motion moved-

That this House agrees with the recommendations contained in the first Report of the Business Advisory Committee with the modification that the sitting fixed for the 11<sup>th</sup> February, 2009 will be off day and the business fixed for 11<sup>th</sup> February, 2009 will be taken up on first sitting of the 13<sup>th</sup> February, 2009.

**Mr Speaker:** Question is-

That this House agrees with the recommendations contained in the first Report of the Business Advisory Committee with the modification that the sitting fixed for the 11<sup>th</sup> February, 2009 will be off day and the business fixed for 11<sup>th</sup> February, 2009 will be taken up on first sitting of the 13<sup>th</sup> February, 2009.

*The motion, as amended, was carried.*

**सदन के कार्यक्रम में परिवर्तन**

**Sh Randeep Singh Surjewala:** Speaker Sir, I have one more suggestion through you to the House that as per the business listed in the List of Business, there will be very less left for discussion on Governot's Address so, on 12<sup>th</sup> February,

2009, the non official day may be converted into an official day so that large number of Members who want to speak on Governor's Address they can express their opinion. This is only a suggestion subject to if the House feels.

**डा० सु गील इन्दौरा:** अध्यक्ष महोदय, इस पर मेरा ऐतराज है क्योंकि गैर सरकारी कामकाज के दिन ही सदस्य अपनी बात कह सकते हैं और एक ही दिन होता है।

**श्री अध्यक्ष:** क्या आप गवर्नर एड्रेस पर नहीं बोलना चाहते हैं?

**डा० सु गील इन्दौरा:** अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर एड्रेस पर भी बोलूंगा इसलिए आप सैंशन का समय और बढ़ा लीजिए इसमें क्या दिक्कत है सरकार के पास बहुत समय है 20 की बजाए सैंशन और बढ़ा लीजिए।

**श्री अध्यक्ष:** सरकार के पास या मैम्बर्ज के पास आप सरकार और पार्टी की बात बहुत करते हैं और हाउस की बात कम करते हैं।

**डा० सु गील इन्दौरा:** अध्यक्ष महोदय, क्योंकि सैंशन का समय घटाना और बढ़ाना सरकार की कौन्सिल से होता है इसलिए मैं यह कहता हूँ कि सरकार के पास फालतू टाइम है काम तो कुछ है नहीं सैंशन का समय और बढ़ा लिया जाए।

**बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला):** अध्यक्ष महोदय, श्री औम प्रकाश चौटाला जी बी० ए० सी० के सदस्य हैं वे न तो कभी बी० ए० सी० की मीटिंग में आते हैं और न ही कभी अपना कोई सुझाव रखते हैं। वे डाक्टर इन्दौरा को अपनी जगह क्यों नहीं नोमिनेट कर देते।

**डा० सु गील इन्दौरा:** अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि हम जैसे सदस्यों को बहुत कम ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर कोई बिल लेकर आना है, कोई रैजोल्यूशन लाना है और हरियाणा प्रदेश के हित में कई अनेकों ऐसी बातें हैं जिस दिन कोई अपनी बात कहना चाहते हैं। एक ही तो दिन होता है वह दिन भी अगर सरकार खा जाए तो बताओ बचेगा क्या।

**श्री अध्यक्ष:** चलो अब तो हाउस पर इस बात को छोड़ दिया यह तो हाउस का काम है हाउस जैसा कहेगा वैसे कर लेंगे।  
( गोर एवं व्यवधान)

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला:** अध्यक्ष महोदय, मैं इन्दौरा साहब की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि चौटाला साहब की सरकार के समय पांच सालों में आफिशियल डे को नाने आफिशियल में कभी क्वॉर्ट नहीं कराया गया इनकी सरकार ने सारा समय ऐसे ही निकाल दिया। ये सारे समय को ही खाते रहे।

**श्री अध्यक्ष:** इन्दौरा जी, आपका सुझाव आ गया है।

**श्री कर्ण सिंह दलाल:** अध्यक्ष महोदय, आप इतनी उदारता दिखा रहे हैं सभी सदस्यों को बोलने का समय भी दे रहे हैं। 12 तारीख को जो गैर सरकारी कामकाज का दिन है अगर आप ठीक समझे तो उसमें ज्यादा रैजोल्यूशन नहीं है आधा घण्टा या पौना घण्टा है जो हमारे गैर सरकारी संकल्प है उनके उपर चर्चा हो जाए और उसके फौरन बाद आप सरकारी काम काज कर लें। सर, अगर इसको आप अडोप्ट कर ले तो अच्छा रहेगा।

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला:** अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव तो यह है कि नॉन आफिशियल डे को आफिशियल डे में कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि गवर्नर एड्रेस पर ज्यादा मैम्बर्स को बोलने के लिए समय मिल जाए।

**श्री अध्यक्ष:** दलाल साहब, आप अपने नॉन आफिशियल रैजोल्यूशन के बारे में गवर्नर एड्रेस पर डिस्कशन के समय ही बोल लेना। You can speak on Governor's Address.

**श्री कर्ण सिंह दलाल:** ठीक है जी।

**Mr Speaker:** Hon'ble Members, with the sense of the House and keeping in view the feelings expressed by the Members in the House that instead of transacting non-official business on the non-official day i.e. 12<sup>th</sup> February, 2009. official business will be transacted and the Governor's Address will be discussed so that more members could speak on motion of thanks on the Governor's Address.



सदन की मेज पर रखे जाने वाले / पुनः रखे जाने वाले  
कागज-पत्र

**Mr Speaker:** Now, the Parliamentary Affairs Minister will lay/re-lay papers on the Table of the House.

**Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala):**  
Sir, I beg to lay on the Table of the House-

The Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Ordinance, 2009 (Haryana Ordinance No. 1 of 2009).

The Haryana Fire Service Ordinance, 2009 (Haryana Ordinance No. 2 of 2009).

The General Administration Department Notification No. S.O. 31/HA/3/1975/S.8/2008, dated the 16<sup>th</sup> April, 2008 regarding amendment in Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Allowances Rules, 1997, as required under section 8(2) of the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances Act, 1975.

The General Administration Department Notification No. S.O 31/H.A. 3/1970/S. 8 and 9/2008, dated the 16<sup>th</sup> April, 2008 regarding amendment in Haryana Ministers Allowances Rules, 1972, as required under section 9(2) of the Haryana Salaries and Allowances of Ministers Act, 1970.

The Personnel Department Notification No. G.S.R 5/Const./ Art. 320/2008, dated the 6<sup>th</sup> February, 2008

regarding amendment in Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1973, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Personnel Department Notification No. G.S.R 27/Const./Art. 318/2008, dated the 7<sup>th</sup> August, 2008 regarding amendment in Haryana Public Service Commission (Conditions of Service) Regulations, 1972, as required under Article 320(5) of the Constitution on India.

The Personnel Department Notification No. G.S.R 30/Const./ Art 320/2008, dated the 18<sup>th</sup> August, 2008 regarding amendment in Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1973, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

Sir, I also beg to lay on the Table of the House-

The Personnel Department Notification No. G.S.R 31/Const./ Art 320/2008, dated the 21<sup>st</sup> October, 2008 regarding amendment in Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations , 1973, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O 79/ H.A-6/2003S.60/2003, dated the 22<sup>nd</sup> May, 2003 regarding the Haryana General Sales Tax Rules, 1975, as required under section 60(4) of the Haryana Value Added Tax Act, 2003.

The Excise and Taxation Department Notification No S.O 113/H.A-6/2003/S.60/2003, dated the 21<sup>st</sup> November,

2008 (Second Amendment) Rules, 2008, as required under section 60(4) of the Haryana Value Added Tax Act, 2003.

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O 115/H.A-6/2003/S.60/2008, dated the 27<sup>th</sup> November, 2008 regarding amendment in the Haryana Value Added Tax (Third Amendment) Rules, 2008, as required under section 60(4) of the Haryana Value Added Tax Act, 2003.

The Revenue and Disaster Management Department Notification No. S.O 2/H.A-38/2008 S.18/2009, dated the 6<sup>th</sup> January, 2009 regarding the Haryana Regulations of Property Dealers and Consultants Rules, 2009, as required under section 18(3) of the Haryana Regulation of Property Dealers and Consultants Act, 2008.

The Annual Accounts of the Haryana Khadi and Gramodyog Board for the year 2003-2004, as required under section 19(3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The Annual Accounts of the Haryana Khadi and Garmodyog Board for the year 2004-2005, as required under Section 19(3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The 8<sup>th</sup> Annual report of Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam Limited for the year 2006-2007, as required under section 619-A(3)(b) of the Companies Act, 1956.

The Annual Report for the year 2007-2008 (1.4.2007 to 31.3.2008) of Lokayukta, Haryana, as required under section 17 (4) of the Haryana Lokayukta Act, 2002.

The Audit Report on the Accounts of Haryana Financial Corporation for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2008, as required under section 37 (7) of the State Financial Corporations Act, 1951.

The Revised Explanatory Memorandum pertaining to PRIs as to the action taken on the interim Report of Third State Finance Commission Haryana, as required under Article 243-I(4) and 243-Y(2) of the Constitution of India.

The Finance Accounts of the Government of Haryana for the year 2007-2008 in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Appropriation Accounts of the Government of Haryana for the year 2007-2008 in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2008 (Civil) of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2008 (Revenue Receipts) of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2008 (Commercial) of

the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

वि शेषाधिकार मामलो के संबंध मे वि शेषाधिकार समिति का प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढाना

**Mr Speaker:** Now, Sh Karan Singh Dalal, M.L.A, Chairperson, Committee of Privileges, will present the Fourth Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Sh Randeep Singh Surjewala, Parliamentary Affairs Minister, Haryana against Shri Om Parkash Chautala, MLA in respect of misconduct, misbehaviour and disorderly disrupting the proceedings of the House, unbecoming of a Member of the House, thereby committing the contempt of the House/breach of privilege on 20.03.2007 and on earlier occasions also and will also move that the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

**Sh Karan Singh Dalal (Chairperson, Committee of Privileges):** Sir, I beg to present the Fourth Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Sh Randeep Singh Surjewala, Parliamentary Affairs Minister, Haryana against Shri Om Parkash Chautala, MLA in respect of misconduct, misbehaviour and disorderly disrupting the proceedings of the House, unbecoming of a Member of the House, thereby committing the contempt of the House/breach of privilege on 20.03.2007 and on earlier occasions also.

Sir, I beg to move-

That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of the next session.

**Mr Speaker:** Motion moved-

That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of the next session.

**Mr Speaker:** Question is-

That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of the next session.

The motion was moved.

वर्ष 1999-2000 से 2004-2005 तक की अवधि के दौरान सार्वजनिक सम्पत्तियों के हस्तांतरण/ नीलामी/ आबंटन की विस्तृत जांच करने के लिए हरियाणा विधान सभा की समिति का प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना

**Mr Speaker:** Hon'ble Member, now, Sh Phool Chand Mullana, Chairperson, Committee of the Haryana Vidhan Sabha to inquire into the details of public properties transferred/ auctioned/ allotted during the year 1999-2000 to 2004-2005 will present the Second Preliminary Report of the Committee and will also move that the time for the

presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

**Sh Phool Chand Mullana (Chairperson, Committee of the Haryana Vidhan Sabha, to inquire into the details of public properties transferred/ auctioned/ allotted during the year 1999-2000 to 2004-2005.):** Sir, I beg to present the Second Preliminary Report of the Committee of the Haryana Vidhan Sabha to inquire into the details of public properties transferred/auctioned/allotted during the years 1999-2000 to 2004-2005.

Sir, I also beg to move-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

**Mr Speaker:** Motion moved-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

**Mr Speaker:** Question is-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा

**Mr Speaker:** Hon'ble Members, now discussion on the Governor's Address will take place. Shri Venod Kumar Sharma, M.L.A will move his motion.

**Sh Venod Kumar Sharma (Ambala city):** Sir, I beg to move-

“That the members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 6<sup>th</sup> February, 2009 at 2:00 P.M.”

स्पीकर सर, मेरे दोस्त इन्दौरा जी इस बात को मान रहे थे और इस बात का जिक्र कर रहे थे कि इन्डवटेंटली या बाई को—इंसीडेंट ओबीच्यूरी रैफरेंसिज के दौरान वह और उनकी पार्टी के दूसरे सदस्यगण भाामिल नहीं हो सके तो मुझे उम्मीद थी कि भाायद वे इसके लिए हाउस से क्षमा मांगेंगे। हाउस में इस बात का बड़ा भारी भाोक था क्योंकि इनके गैरहाजिर होने की वजह से हमारी परम्परा पर एक बड़ा आघात लगा था। फिर भी मैं इन्दौरा जी की इस बात को मानता हूँ कि भले ही उन्होंने क्षमायाचना की बात नहीं कही लेकिन अपनी गलती को जरूर माना है और उसको देखते हुए श्री करण सिंह दलाल जी ने अपना रैजोल्यूशन वापिस ले लिया है। इसके साथ ही इन्दौरा जी ने जो बात कही है कि चौधरी रणबीर सिंह जी की जीवनी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए मैं उनके इस विचार से भी सहमत हूँ क्योंकि चौधरी रणबीर सिंह ही ऐसी भाखिसयत थे जिनहोने परिवार की रिवायतों का अनुसरण करते हुए इस देश की आजादी के लिए अपने



आपको महज 22 वर्ष की उम्र में ही दे 1 के प्रति समर्पित कर दिया था। दे 1 की आजादी के लिए उन्होंने हिन्दुस्तान की 7 जेलों में साढ़े तीन साल तक लगातार सजा काटी और नजरबंद रहे। वे कांस्टीच्यूट असैम्बली के आखिरी जीवित मैम्बर होने के साथ साथ पंजाब विधान सभा, हरियाणा विधान सभा, लोकसभा और राज्य सभा के सदस्य भी रहे। चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा महज मुख्यमंत्री के पिताश्री ही नहीं थे बल्कि नौजवानों और दे 1 के करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी थे। मैं खुद उनकी जीवनी पढ़ रहा था। यह बात आज हम सभी लोग मानते हैं कि राजनीति में कुछ उसूल होने चाहिए अर्थात् राजनीति उसूलों के उपर करनी चाहिए। हमें इस बात की खुशी है कि चौधरी रणबीर सिंह जी ने उन उसूलों को समक्ष रखते हुए अपना सम्पूर्ण राजनीतिक जीवन व्यतीत किया। इसके साथ ही 65 साल की उम्र में उन्होंने यह फैसला ले लिया कि अब वे राजनीतिक से सन्यास लेंगे। मैं समझता हूँ कि आज के राजनीतिक व्यक्तियों को उनसे ज्यादा से ज्यादा शिक्षा लेनी चाहिए। राजनीति में अपने स्वार्थों से उपर उठकर दे 1, समाज और जनसाधारण की सेवा किस तरह से की जाती है यह शिक्षा हमें उनसे लेनी चाहिए और उनका अनुसरण करना चाहिए। इसके साथ ही मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में चर्चा करना चाहूँगा कि उन्होंने अमेरिका और दूसरे देशों के साथ जो न्यूक्लियर समझौता किया है उसकी वजह से दे 1 में प्रगति और उन्नति का एक बहुत बड़ा समुन्द्र हमें देखने को मिलेगा। 16:00 बजे। इसके साथ ही मैं

अपनी सरकार द्वारा पिछले चार साल में किए गए कार्यों के बारे में भी बताना चाहूंगा। वर्ष 2004-05 में हरियाणा प्रदेश का जो प्लान साईज था वह 2236 करोड़ रुपये था और आज 2009-10 में हरियाणा प्रदेश का जो प्लान साईज है वह 10 हजार करोड़ है जो पिछली सरकार से लगभग 5 गुणा ज्यादा है। जो प्रोग्रेस, जो उन्नति हरियाणा प्रदेश में पिछले 4 वर्षों में हुई है उसको हम प्लान साईज से नहीं आंक सकते। हरियाणा प्रदेश की जो उन्नति पिछले 4 वर्षों में हुई है वह इस प्लान साईज से कई गुणा ज्यादा है। जब वर्ष 2004-05 में 2236 करोड़ रुपये का प्लान साईज था उस समय और उससे पहले भी तो हरियाणा में कहीं सड़कों का काम, नहरों का काम, स्वास्थ्य का काम, शिक्षा का काम देखने को नहीं मिलता था। यह बात समझ में नहीं आती कि 2236 करोड़ रुपये में वर्ष 2004 में कितना पैसा सरकार ने लोगों की भलाई के लिए लगाया और इसमें से कितना पैसा अपनी भलाई के लिए लगाया। इस बारे में आंकड़े प्राप्त नहीं हुए लेकिन इस बात की गवाही लोगों की तरफ से मिलती है। जितना पैसा अब हरियाणा में लगाया गया है और आने वाले वर्षों में लगेगा, पिछले 40 वर्षों में भी इतना पैसा नहीं लगा होगा और इतनी उन्नति हरियाणा में कहीं नहीं हुई होगी। कुछ आंकड़े और कुछ तथ्य अवश्य मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इससे पहले मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार में नीयत और नीति में अंतर था। न तो लोगों की सेवा की सरकार की नीयत थी और न ही ऐसी नीति निर्धारित की गई जिससे लोगों को फायदा हो। पिछली सरकार ने

अपने स्वार्थों के लिए जो कार्य किए हैं उनको हरियाणा की जनता आज तक भूली नहीं है। लोग आज भी त्राहि त्राहि कर रहे हैं। हमारी सरकार ने जो वायदे किये वे पूरे किये और जो वायदे नहीं किए थे वे भी पूरे किये। हमारी सरकार लोगों की कसौटी पर खरी उतरी। जिन वायदों के साथ हमारी सरकार ने प्रदेश के भासन की बागडोर सम्भाली थी पिछले 4 वर्षों में न केवल उन्हें हकीकत में बदला है बल्कि जन-कल्याण एवं विकास के कार्य किए हैं। किसानों की भलाई के लिए भी ऐतिहासिक फैसले लिये हैं। वह सरकार जो किसानों के हित की सरकार कहलाती थी उस सरकार के बारे में अगर ज्यादा कुछ न कहा जाये तो ही अच्छा है क्योंकि पिछली सरकार ने न तो किसानों को किसानों की पैदावार के असली मूल्य दिये और न ही किसानों के लिए कोई अच्छे कार्य किए। न किसानों को बिजली दी और न ही और न ही किसानों को पानी दिया। हमारी सरकार ने सबसे पहले किसानों के 1600 करोड़ रुपये के बिजली के कर्जे माफ किये। स्पीकर सर, यह वायदा हमने लोगों के साथ नहीं किया था। यह कोई चुनाव के लिए किया हुआ कार्य नहीं था क्योंकि चुनाव तो अभी बहुत दूर थे। यह कार्य लोगों की उन मुश्किलों को देखते हुए किया गया जिन मुश्किलों में पिछली सरकार ने उनको डाल दिया था। यह कह कर कि आप बिजली के बिल मत भरना हम बिजली के बिल नहीं चाहते। जब उन लोगों ने बिजली के बिल नहीं दिये तो उनके ऊपर गोलियां चलाई गईं। हमारी सरकार ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया कि जो लोग बिजली के बिल नहीं भर सकते हैं

उनको इन बिलो से माफी दी जाये। स्पीकर सर, यह एक ऐतिहासिक फैसला था जो हमारी सरकार ने सबसे पहले लिया। हमारी सरकार ने किसानो को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए केन्द्र सरकार के साथ बातचीत की। केन्द्र सरकार ने पिछले चार साल मे गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मुल्य मे 450 रुपये प्रति क्विंटल बढाए है जबकि एन० डी० ए० की पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल मे केवलमात्र 40 रुपये की बढौतरी की थी। वह सरकार जो अपने आपको किसानो की हितैशी सरकार कहती थी उसने किसान के लिए पिछले पाचं साल मे 40 रुपये बढाए जबकि हमारी सरकार ने और पांच साल मे 450 रुपये बढाए। इन दोनो का आपस मे मिलान करके देखें कि कौन सी सरकार किसानो के हित की सरकार है। कोन सी सरकार किसानो की हितैशी सरकार है और कौन सी सरकार किसानो के हित को समझती है। इसमे कुछ कहने की जरुरत महसूस नही होती। अध्यक्ष महोदय हमारे अनुरोध पर यू पी ए सरकार ने हमारी सरकार ने चावल की 1121 पूसा धान की किस्म के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटवाया तथा उसको बासमती का दर्जा दिलवाया। हमारे जिन किसानो ने यह फसल बोई थी उनको इस वजह से बहुत लाभ हुआ और वे जिन्स को प्याप्त मात्रा मे बाहर भेजन में सफल हुए। स्पीकर सर, गन्ने का सर्वाधिक भाव किसान को दिया गया। पिछले चार वशों मे हमारी सरकार ने गन्ने की विभिन्न किस्मो के लिए 170, 165 और 160 रुपये का भाव दिया है जो पूरे देा मे सबसे ज्यादा है। पिछले चार वशों मे पहले हरियाणा मे जो सरकार थी उस सरकार

ने अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में मात्र 10 या 12 रुपये की बढ़ोतरी की है। 56 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी पिछले चार साल में की गई है। मैं समझता हूँ कि किसानों के लिए जो गन्ने के भाव दिये गये हैं उससे हमारे हरियाणा के किसान बहुत खुश हैं। किसानों की सबसे बड़ी समस्या यह भी थी कि बहुत से डिपार्टमेंट्स बहुत से कार्यों के लिए जमीन का अधिग्रहण करते थे लेकिन किसानों को उनकी भूमि का पर्याप्त मूल्य नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने इसको मददेनजर रखते हुए दो बार फ्लोर रेट संशोधित किए हैं। अब स्थान विशेष के आधार पर ये दरें 20 लाख, 16 लाख और 8 लाख रुपये प्रति एकड़ निर्धारित की गई हैं और मुआवजा में दूसरे लीग मिलने से यह राशि बढ़कर 26 लाख रुपये, 20.80 लाख रुपये और 10 लाख 40 हजार रुपये हो जाती है। इसके साथ ही साथ सरकार ने नया सिस्टम बनाया है जिसके जरिये किसानों की नियमित आय सुनिश्चित करने के लिए 33 वर्ष तक के लिए 15000 रुपये प्रति वर्ष प्रति एकड़ रायल्टी और इसमें हर वर्ष 500 रुपये की बढ़ोतरी करने का निर्णय किया है। स्पीकर सर, इसमें एक बहुत ही जरूरी पक्ष है। हमारे किसानों भाईयों को जब मुआवजा मिलता था तो वे उस पैसे को परिवार में कहीं न कहीं लगा देते थे। वह पैसा परिवार में खर्च होने के बाद किसान भाईयों की परिवार की तरफ उतनी अहमियत नहीं रहती थी क्योंकि न तो उनके हाथ में जमीन थी और न ही उनके हाथ में पैसा था। इसी बात को देखते हुए सरकार ने एक नया फैसला किया कि आने वाले 33 साल के लिए उसी भूमि के उपर उनको

जो पैसा मिला है उस पैसे के बावजूद उसके अलावा उनको 15 हजार रुपये प्रतिवर्ष प्रति एकड़ उनको दिया जाएगा ताकि वह किसान अपनी जमीन जाने के बाद किसी के उपर निर्भर न रहे। किसान को अपनी जमीन से बड़ा प्रेम होता है और अपनी जमीन जाने के बाद वह किसी पर आश्रित न रहे इसलिए सरकार ने यह फैसला किया है। हमारी सरकार ने पहली बार नहर के पानी का समान बंटवारा किया है। स्पीकर सर, पिछले वर्षों में देखा गया कि हरियाणा प्रदेश के कुछ ऐसे इलाके हैं जिन में पानी की भरमार थी उन इलाकों में जरूरत से ज्यादा पानी जाया करता था और कुछ ऐसे इलाके थे जहां पर भायद देखने को भी पानी नहीं मिलता था। कृषि योग्य भूमि में जब हमें सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती थी तो किसान आसमान की तरफ देखते थे। बारिश के उपर निर्भर करते थे क्योंकि राज्य में नहरों का जाल नहीं था। यहां पर मुझे इस बात को कहने में बड़ा गर्व महसूस होता है कि पंजाब और हरियाणा की सिंचाई स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू की सोच और स्वर्गीय रणबीर सिंह हुंडड़ा जी के प्रयासों से सम्भन हुई है। भाखड़ा डैम जब बना उसके बाद हरियाणा और पंजाब में नहरों का जाल बिछा और सिंचाई की वजह से बंजर जमीनें उपजाऊ जमीनें बनीं। उसकी वजह से हमारे इलाके में खुशहाली आई। लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोगों के स्वार्थ की वजह से कुछ लोगों के लालच की वजह से इन इलाकों में कभी पानी की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। हमारी सरकार ने पहली बार नहरों के पानी के समान बंटवारे के लिए भाखड़ा डैम

लाईन हांसी-बुटाना नहर का निर्माण कार्य पूरा किया है। इस नहर से अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, हिसार जिले के हांसी मण्डल, भिवानी, महेन्द्रगढ़ फरीदाबाद, झज्जर, रोहतक, सोनीपत ओर पानीपत के किसानों को लाभ होगा। अध्यक्ष महोदय, लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से अम्बाला सिंचाई परियोजना तैयार की गई है और केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति के लिए भेजी गई है। इस परियोजना से वर्षा ऋतु में यमुना नदी के अतिरिक्त पानी के उपयोग से यमुनानगर, अम्बाला ओर पंचकूला जिले की 1 लाख 35 हजार 628 हैक्टेयर जमीन की सिंचाई हो सकेगी और भू-जल स्तर में भी सुधार होगा। स्पीकर सर, बहुत से प्रश्न यहां पर उठाए जाते हैं। और बहुत सी राजनैतिक पार्टियां अपने अपने नेताओं के द्वारा एस वाई एल कैनल के बारे में बहुत चर्चा करती हैं। एस वाई एल कैनल का फैसला कांग्रेस की सरकार ने किया था। 1982 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसके निर्माण कार्य का उद्घाटन किया था। एस वाई एल कैनल काफी हद तक पंजाब में बनाई भी जा चुकी थी। अध्यक्ष महोदय, 15 जनवरी 2002 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस वाई एल के माध्यम से हरियाणा के पक्ष में फैसला भी दिया। इस फैसले में निर्देश भी दिए कि अगर पंजाब सरकार निर्धारित समय में नहर का निर्माण करने में असफल रहती है तो केन्द्र सरकार अपनी किसी एजेंसी से यथा सम्भव भीघ्नता से इसका कार्य पूरा करवाए। उस वक्त केन्द्र में एन डी ए की, पंजाब में अकालियों की और हरियाणा में आई एन एल डी की सरकारें थीं। आई एन एल डी

और अकालियो मे आपसे मे सांझा है, आपस का जो भाईचारा है उसको हम भूले नहीं है। लेकिन इनके आपस के भाईचारे और आपस की सांझ की वजह से जो नुकसान हरियाणा को हुआ है भायद उसकी भरपाई कभी न हो सके। इसकी जवाबदेही उस वक्त की आई एन एल डी की सरकार को और आज उनकी पार्टी के याहं बैठे हुए मेरे दोस्तो को देनी पडेगी। अगर उस वक्त एस वाई एल कैनाल ये बना देते तो आज हरियाणा के लाखो करोडो लोगो को फायदा होता। सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए उनके साथ दोस्ती रखने के लिए हरियाणा मे एस वाई एल के पानी को नहीं जाने दिया गया। (विधन)

**डा० सु गील इन्दौरा:** स्पीकर सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अभी भार्मा जी ने कहा कि उस वक्त सैंटर मे एन डी ए की सरकार थी, हरियाणा मे आई एन एल डी की सरकार थी और पंजाब मे अकाली दल की सरकार थी। अगर उस वक्त एस वाई एल नहर बना देते तो आज हरियाणा की जनता को बहुत फायदा होता। चलो मै मानता हूं कि उस वक्त नहीं बना प्प लेकिन आज केन्द्र मे कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा मे भी कांग्रेस की सरकार है। लेकिन मै इनसे यह पूछना चाहता हूं कि आज ये कब तक एस वाई एन एल नहर को बनवा देंगे। इस बारे मे ये सीधा जवाब दे दें। (विधन)

**श्री अध्यक्ष:** इन्दौरा जी, आपको पता है कि यह सारा मामला सब—ज्यूडिस है। (विधन) आप फिर भी यहां पर इस तरह



की बाते कर रहे हो। आप तो इस तरह से बात कर रहे हो जैसे कि आपको कुछ भी पता नहीं है। (विधन) You know the whole position. (विधन)

**डा० सु गील इन्दौरा:** अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ एक बात कहता हूँ कि नहर निर्माण के मामले में कोई सब ज्यूडिस नहीं है।

**श्री विनोद कुमार भार्मा :** अध्यक्ष महोदय, मैं इन्दौरा जी का बहुत भाुकगुजार हूँ कि ये इतने यूनानमस है इतने लार्ज हार्टिड है कि ये अपनी गलती मानते हैं।

**श्री अध्यक्ष:** इन्दौरा जी, आप ऐसा कह सकते हैं। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजिज को राष्ट्रपति जी ने रैफरेंस किया हुआ है। यह सारा मामला फुल बेंच के पास है। (विधन)

**डा० सु गील इन्दौरा:** यह नहर निर्माण के मामले में नहीं है।

**श्री अध्यक्ष:** डा साहब, ऐसा है कि इसके टैंडर हो चुके थे और यह नहर बार्डर तक बनानी थी। उसके बाद ही सारा रैफरेंस आया है। डा० साहब आपको सारा पता है।

**डा० सु गील इन्दौरा:** स्पीकर सर, इस नहर के निर्माण के मामले में कोई भी मामला कोर्ट में पेंडिंग नहीं है। (विधन)

**श्री अध्यक्ष:** इन्दौरा साहब, आप अभी बैठें। (विधन)

डा० सु गील इन्दौरा: \*\*\*\*\*

**Mr Speaker:** Nothing is to be recorded.

श्री विनोद कुमार भार्मा: स्पीकर सर, डा साहब की सबसे बड़ी खुबी यही है कि ये अपनी बात को मान लेते हैं, अपनी गलती को युनानीमसली मान लेते हैं। यह बहुत अच्छी बात है। (विध्न) डा० साहब, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ कि आपने कहा कि चलो, हम नहीं बना पाए और आप कब तक यह बना देंगे। यही इनका प्र न है। इनके प्र न का सिर्फ एक ही जवाब है कि इसको बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, हम इसको बनायेंगे। वक्त की बात नहीं है लेकिन ये मान गए हैं कि ये इसको बनाना नहीं चाहते थे। इस बात को ये मानते हैं कि ये इसको बनाना नहीं चाहते थे।

डा सु गील इन्दौरा: स्पीकर सर, कांग्रेसी अगर रोडा नहीं अटकाते तो हमने तो कब की यह नहर बनवा दी होती।

श्री विनोद कुमार भार्मा: स्पीकर सर, हमारे पास तो रोड ही नहीं है तो अटकाएंगे कहां से? आजकल कई यात्राएं चल रही हैं। कोई आके । यात्रा चल रही है और कोई जन-आके । यात्रा चल रही है। जन आके । तो है लेकिन वह जन आके । इनकी पुरानी सरकार के खिलाफ हैं उस यात्रा में जिस तरह से लोग इनको बताते हैं कि वर्ष 2004-05 में पहले जिस प्रकार से पिछली सरकार ने कार्य किए, वह आके । अभी तक लोग भुला

नहीं पाए हैं। इस आक्रोश का खामियाजा तो ये आने वाले चुनाव में देख लेंगे कि लोगों में इनके प्रति कितना आक्रोश है। (विधन) स्पीकर सर, अब मैं बिजली के बारे में कहना चाहूंगा। पिछली सरकार ने पता नहीं क्यों बिजली की जरूरत को नहीं समझा। पिछली सरकार ने इस बात को नहीं समझा कि हरियाणा को बिजली की जरूरत पड़ेगी। अपने भाषनकाल में उन्होंने कोई भी नये बिजली के संयंत्र लगाने की कोशिश नहीं की। हमारी सरकार ने पिछले चार सालों के दौरान यह फैसला किया है कि इस समय जो बिजली की उत्पादन क्षमता लगभग 4753 मैगावाट है उसको हमारी सरकार आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ाएगी। स्पीकर सर, हिसार जिले में खेदड गांव में 4297 करोड़ रुपये की लागत से लग रहे 1200 मैगावाट की क्षमता का राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट का 50 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। इसकी 600 मैगावाट की पहली ईकाई दिसम्बर, 2009 में और 600 मैगावाट की दूसरी ईकाई मार्च 2010 तक तैयार हो जाएगी। इसी तरह से फतेहाबाद में कुम्हारिया गांव में 2800 मैगावाट का परमाणु संयंत्र लगाने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। (विधन) हम चाहेंगे कि ये भी इस बारे में हमारा समर्थन करें

**डा० सु नील इन्दौरा:** स्पीकर सर, \*\*\*\*\*

**Mr Speaker:** Nothing to be recorded.

**श्री विनोद कुमार भार्मा:** स्पीकर सर, हमारी सरकार बिजली क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए लगभग चालीस हजार करोड़ खर्च कर रही है। (विधन)

**श्री अध्यक्ष:** डा साहब, वा पालिसी बात रहे है और पालिसी बताने मे झूठ नही होता।

**श्री विनोद कुमार भार्मा:** स्पीकर सर, यह तो हमारी सरकार की पालिसी है। पूरी सिंसियरिटी के साथ हम काम करेंगे, इसका हम इनको विवास दिलाते है। (विधन) ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना मे राज्य मे बिजली उत्पादन, प्रसारण और वितरण मजबूत बनाने के लिए 25524 करोड रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इतनी राशि का पहले कभी भी प्रावधान नही किया गया। नये संयंत्र लगाने के लिए और उत्पादन क्षमता बढाने के लिए इतनी राशि का प्रावधान किया गया है। (विधन)

**बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला):** अध्यक्ष महोदय, इन्दौरा जी और सीता राम जी सीनियर सदस्य है इनको बैठे बैठे टिप्पणी नही करनी चाहिए। इन जैसे सदस्यो को बैठे बैठे अनाप भानाप टिप्पणी करना भाभा नही देता। (विधन)

**श्री विनोद कुमार भार्मा:** स्पीकर सर, हमारी सरकार ने किसानो के साथ साथ मजदूरो के साथ साथ व्यापारियो के साथ भाहरो मे जो कार्यक्रम चालू किए है उनके जरिए अर्बन एरियाज मे उन्नति के नये आयाम हमारी सरकार ने कायम किए है। यह बहुत

सराहनीय है। पहले जिन एरियाज में सीवरेज की लाईनें नहीं थी, वहां अब सीवरेज की लाईनें पड़ रही हैं। जहां सड़कें नहीं थी, वहां सड़कें बनावाई जा रही हैं। हमारी सरकार ने अप्रैल 2008 में गृहकार्य हटाकर 9 लाख परिवारों को 35 करोड़ रुपये की राशि का लाभ दिया है। पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को सुविधाएं दी हैं। पेयजल प्रदान करने पर खासतौर पर ध्यान दिया है। गांवों में पेयजल की विशेषतौर पर दिक्कत थी। हमारी सरकार ने इंदिरा गांधी पेयजल स्कीम शुरू की है और इस स्कीम के तहत तीन वर्षों में सरकार ने इंदिरा गांधी पेयजल स्कीम शुरू की है। और इस स्कीम के तहत तीन वर्षों में 8 लाख अनुसूचित जाति के परिवारों को मुफ्त कनेक्शन दिये जाएंगे। अब तक 4.5 लाख से अधिक कनेक्शन दिये जा चुके हैं। ऐजुकेशन के क्षेत्र में पिछले 4 वर्षों में सरकार ने बहुत से काम किए हैं। कॉलेज शिक्षा, स्कूल शिक्षा, विश्वविद्यालय, मेडिकल, तकनीकी तथा आई टी आई के दृष्टिकोण से हटकर भविष्य की जरूरत के अनुसार हमारी सरकार ने क्रांतिकारी पहल की है और ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। वर्ष 2008 को शिक्षा वर्ष के रूप में मनाया गया है। हमारे प्रदेश में इससे पूर्व शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका था कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद विद्यार्थी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। स्पीकर सर, हमारी सरकार ने शिक्षा को आगे बढ़ावा देने के लिए जो कार्य किए हैं उसके बाद वर्ष 2007-08 में जो ऐजुकेशन इंडेक्स बना है उसमें वर्ष 2006-07 में हरियाणा प्रदेश में 20वें से 7वें स्थान पर पहुंच गया है। आने वाले समय में इससे भी आगे

हम जाएंगे लेकिन शिक्षा के माध्यम से जो कार्य हम अपने विद्यार्थियों के लिए करना चाहते हैं उसमें हम कुछ कमी अवश्य महसूस करते हैं। विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करते समय वह मौके नहीं मिलते तो मिलने चाहिए। विशेषतौर पर गावों में रहने वाले विद्यार्थियों और गरीब बच्चों को जो मिलने चाहिए। लैवल प्लेयिंग फील्ड जो एक तरह की समान शिक्षा है वह विद्यार्थियों को नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वे बच्चे जब शिक्षा ग्रहण करके कंपिटीशन में जाते हैं तो पीछे रह जाते हैं नौकरियां न मिलने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी मैं समझता हूँ कि एक तरह का वातावरण, एक तरह का माहौल, एक तरह की शिक्षा और एक तरह के टीचर्स सबको मिलने चाहिए ताकि शिक्षा ग्रहण करते समय किसी तरह का भेदभाव न हो और आगे चलकर वह बच्चे हमारे देश के कर्णधार बनें। हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी निकलकर देश में और विदेशों में जाये और हमारा नाम रोशन करें। आज मंत्री जी ने प्रश्नकाल के दौरान यह बातें कही कि जो विद्यार्थी गरीब हैं उनके नम्बर कम आते हैं और वे फेल हो जाते हैं तो उनको पास करने के लिए ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। पिछले कई वर्षों से यह कार्य किया जा रहा है। फिर हम अपने बच्चों को ग्रेस मार्क्स देकर पढाएंगे तो यह सही है कि कुछ हद तक बच्चे शिक्षा तो ग्रहण कर लेंगे लेकिन जब शिक्षा का फायदा लेना चाहेंगे यह कम्पिटीशन के एग्जाम में जायेंगे और जब उनको नौकरी की तलाश होगी तब वहाँ पर हमारे द्वारा दिया गया फायदा, हमारे द्वारा दिये गये ग्रेस मार्क्स उनके काम नहीं

आयेंगे। ग्रेस मार्क्स की प्रक्रिया को छोड़कर हमें शिक्षा के म्यार को, शिक्षा के स्टैण्डर्ड को आगे बढ़ाना चाहिए। एक जैसा मौका सबको देना होगा ताकि शिक्षा के फील्ड में सबको बराबर का हम मिले। हमारी सरकार ने गरीब परिवार के बच्चों के लिए अनूठी मासिक वजीफा स्कीम बनाई है। हमारी सरकार ने अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग की ए श्रेणी और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बच्चों को स्कूल और कॉलेज के स्तर पर 500 करोड़ रुपये की अनूठी मासिक वजीफा स्कीम शुरू की है। जिसके तहत अनुसूचित जाति के पहली कक्षा से पांचवी तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 100 रुपये और लड़कियों को 150 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं और छठी कक्षा से आठवी तक की कक्षा में पढ़ने वाले लड़कों को 150 रुपये और लड़कियां को 200 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं। नौवी कक्षा से बाहरवी तक की कक्षा में पढ़ने वाले लड़कों को 200 रुपये और लड़कियों को 300 रुपये प्रति महीना दिये जा रहे हैं। इसके अलावा ग्याहरवी और बाहरवी कक्षा के विज्ञान विषय में पढ़ने वाले लड़कों को 300 रुपये और लड़कियों को 400 रुपये प्रति माह दिये जा रहे हैं। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को स्कूल खर्च के लिए कक्षा के अनुसार 740 रुपये और 1450 रुपये वार्षिक एकमु त एलाउंस भी दिया जा रहा है। हमारी सरकार ने यह फैसला उन लोगों को सामने रखकर किए हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हैं। यह हमारी सरकार का वायदा है कि इस में सुधार किया जायेगा लेकिन साथ ही मेरा सुझाव है कि जो विद्यार्थी हमारे सरकारी

स्कूलों में पढ़ते हैं, जिन स्कूलों का नतीजा अच्छा न हो जहाँ पर  
मुतवातर लगातर अच्छे नजीते न आते हो, वहाँ पर पढाने वाले  
टीचज, साहेबन पर भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। उनकी भी इस बारे  
में रिस्पोंसिबिल्टी बनती है क्योंकि वे चन्द लोग हरियाणा प्रदेश में  
इस देश में और विद्यार्थियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं।  
अगर उनको कोई ढंग से नहीं पढाता है तो उनके अधिकारों से  
उन्हे वंचित किया जाता है। जो अधिकार हमारे संविधान में और  
हमारे समाज ने उनको दिए हुए हैं उन अधिकारों से उनको वंचित  
किया जाता है जिसके लिए दोशियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी  
कार्यवाही की जानी चाहिए। इस संदर्भ में शिक्षा के प्रसारण के  
लिए नये विविद्यालय हरियाणा सरकार ने अपने प्रदेश में खोले  
हैं जिनमें सोनीपत में दीन बंधु छोटूराम इंजीनियरिंग कालेज को  
डी बंधू साईंस एण्ड टेक्नोलोजी विविद्यालय का दर्जा दिया  
गया है। गुरु जम्भे वर विविद्यालय का दर्जा भी बढ़ाकर  
साईंस एण्ड टेक्नोलोजी विविद्यालय कर दिया गया है और गुरु  
जम्भे वर विविद्यालय में बिजनैस स्कूल और नालेज पार्क की  
भी स्थापना की जा रही है। खानपुर कलां में भगत फुल सिंह  
महिला विविद्यालय स्थापित किया गया है। ये विविद्यालय  
देश का ऐसा पहला विविद्यालय है जिसमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी  
का सब सेंटर खोला गया है। जिला रोहतक के गांव गरनावठी में  
आई आई एम स्थापित किया जायेगा। यह देश का छठा आई  
आई एम होगा जो कि 165 एकड़ भूमि पर 250 करोड़ रुपये की  
लागत से स्थापित किया जायेगा। इसके अलावा कुण्डली में राजीव



गांधी ऐजुके ान सिटी भी स्थापित की जा रही है। इस सिटी मे आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज वि वविद्यालय की तर्ज पर उच्च कोटी की ि ाक्षण संस्थाएं स्थापित होगी ताकि हरियाणा और एन सी आर के नोजवानो को अच्छी उच्च ि ाक्षा के लिए विदे ा न जाना पडे। यह एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तर्ज पर ये संस्थाएं स्थापित होगी और उनमे हरियाणा के विद्यार्थियो को 25 प्रति ात आरक्षण दिया जायेगा। हरियाणा के बच्चो को हायर स्टडी के लिए अच्छा मौका उनको घर पर ही मिलेआ और उनको विदे ा जाने की जरुरत नही होगी। अध्यक्ष महोदय, तकनीकी ि ाक्षा का प्रसार आज के युग की जरुरत है। पूरी दुनिया मे तकनीकी ि ाक्षा का प्रसार हो रहा है। दुनिया मे सबसे ज्यादा नौजवान है, पढे लिखे लोग है। जो मुल्क तरक्की याफता है आज वे मुल्क हिंदुस्तान की तरफ देख रहे है, हिन्दुस्तान के बच्चो की तरफ देख रहे है और यहां के पढे लिखे नौजवानो की तरफ देख रहे है। पिछले 40 सालो मे राज्य मे 257 तकनीकी संस्थाएं स्थापित हुई थी और आज प्रदे ा मे 610 तकनीकी संस्थाए है यानि कि पिछले 40 सालो के दौरान तकरीकी संस्थाओ में प्रवे ा पानपे वाले विद्यार्थियो की संख्या 40 हजार थी जबकि पिछले चार सालो मे यह संख्या 80 हजार हुई है। 40 सालो मे 40 हजार विद्यार्थी और 4 सालो मे 80 हजार विद्यार्थी यह अपने आप मे एक मापदण्ड है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह इंजीनियरिंग कालेज 40 सालो मे 40 बने है जबकि इन 4 सालो मे 38 इंजीनियरिंग कालेज नये खोले गए है। यह भी अपने

आप में एक मिसाल है कि जितने कालेजिज 40 सालों में खुले उतने ही कालेजिज इन सरकार ने 4 सालों में 61 और एम बी ए कालेजिज खोले गए हैं यानी कुल मिलाकर अब 93 एम बी ए कालेजिज हैं। शिक्षा की तरफ हमारी सरकार का ध्यान है ताकि शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के प्रसार से हम अपने बच्चों के लिए नौकरियों का प्रावधान कर सकें और हमारे बच्चे नौकरियां पर कर अपने देश की सेवा कर सकें। लड़कियों और गरीब बच्चों के लिए सुविधाएं इस सरकार ने दी हैं। सभी आई टी आई और तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश हेतु लड़कियों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। रोजगार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या हरियाणा और दूसरे प्रदेशों में है। हरियाणा में खासतौर पर नौजवान विद्यार्थी जब पढ़ लिखकर आते हैं, वे रोजगार न मिलने की भावना में नाउम्मीद हो जाते हैं। रोजगार दिलवाने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। रोजगार दिलवाने के लिए हमारी सरकार ने जो कार्य किया है वह यह है कि नई उद्योग नीति से एक दिन एक में 10 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त करवाने का लक्ष्य रखा है। अध्यक्ष महोदय, लाडली स्कीम बड़ी लोकप्रिय स्कीम है। इस स्कीम के तहत परिवार में दूसरी लड़की के जन्म पर 5 वर्ष की अवधि तक प्रति वर्ष 5000 रुपये दिये जाते हैं। अभी तक इस योजना के तहत 87841 परिवारों को लाभ प्रदान किया जा चुका है। यह आमतौर पर देखा गया है कि जिन परिवारों में सिर्फ लड़कियां होती हैं उन परिवारों में लड़कियों के प्रति उदासीनता परिवार की तरफ से दिखाई जाती है। इस चीज को

सामने रखते हुए लाडली सामाजिक सुरक्षा पैं इन स्कीम नामक एक नई योजना भुरु की गई है। ऐसे माता पिता को 60 वर्ष की बजया 45 वर्ष की आयु मे 500 रुपये प्रति माह पैं इन देने का निर्णय किया गया है। यह सही बात है कि सिकी भी समाज और प्रदे ा को आगे बढाने में हमारे नवयुवको का हाथ है। खेलो का विकास हमारे नवयुवको को आगे ले जाने मे और सक्षम करने मे अहम रोल प्रदान करता है। इसी बात को ध्यान मे रखते हुए बीजिंग ओलम्पिक मे मुक्केबाजी मे कांस्य पदक जीतने वाले भिवानी के श्री विजेन्द्र सिंह को 50 लाख रुपये हमारी सरकार की तरफ से नकद ईनाम दिया गया है, इसी जिले के मुक्केबाजी मे ही क्वार्टर फाईनल मे पहुंचने वाले श्री अखिल कुमार व श्री जितेन्द्र कुमार को भी 25-25 लाख रुपये की राशि बतौर ईनाम देकर सम्मानित किया गया। कु ती मे क्वार्टर फाईनल मे पहुंचने वाले सोनीपत के श्री योगे वर दत्त को भी 25 लाख रुपये की राशि ईनाम के तौर पर दी गई। यह राशि हमारी सरकार ने ओलम्पिक मे गये मुक्केबाजो और दूसरे खिलाडियो का भी दी है। यह सब कुछ खेलो का सम्पूर्ण विकास करने के लिए किया गया है। मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि इससे पहले जो सरकार थी उसने खेलो का विकास की तरफ कोई ध्यान नही दिया जिससे हरियाणा मे जितना खेलो का विकास होना चाहिए था उतना विकास नही हो पाया। खेलो के विकास की तरफ उन्होने को तवज्जोह नही दी क्योंकि न तो वे खिलाडी थे और न ही खेलो के बारे मे कुद जानते थे। वे सिर्फ राजनीति जानते थे और अपने राजनीतिक

लीग के लिए खेलों के अदयरो में बहुत ज्यादा इंटरफियरेंस करते थे जिससे कि हरियाणा में पिछले समय में जो खेलों का विकास हो सकता था वह नहीं हुआ। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हम अपने नोजवानों को बेहतर और आधुनिक सुविधाओं के साथ सीमांत अंतर्राष्ट्रीय खेलों को अच्छे से अच्छा प्रोत्साहन दिलवाएंगे जिससे कि वे खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़कर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर प्रदर्शन के साथ साथ देश का नाम भी रोशन कर सकें। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ हमारी सरकार ने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। प्रदेश सरकार द्वारा जम्मू के मीर से हरियाणा राज्य में आए प्रत्येक के मीरी परिवार को एक हजार रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जा रही है। यह कैसी विडम्बना है कि हमारे देश में हमारे ही देश के लोगों को अपने ही प्रदेश के कुदरत पसंद लोगों की कार्यवाही से अपना घर छोड़ना पड़ा और जब तक कि वहां के हालात ठीक नहीं हो जाते वे अपने प्रदेश में वापिस भी नहीं जा सकते। हमारी सरकार द्वारा उनकी मुश्किलों को देखते और समझते हुए उनके समर्थन में उनकी मदद करने के लिए एक हजार रुपये प्रति मास की दर से उनको राशि दी जा रही है। इस बारे में मेरी सलाह है और मैं अपनी तरफ से सरकार से गुजारिश करूंगा कि सरकार को इस राशि को बढ़ाना चाहिए क्योंकि आज के युग में एक हजार रुपये प्रतिमास देने से किसी परिवार का गुजारा नहीं हो सकता। एक हजार रुपये प्रति महीना उन लोगों के लिए बहुत ही कम राशि है जो अपना घर बार छोड़ कर हमारे

पास आकर बसे है। उनकी भरपूर मदद करना आज हमारा धर्म है। अध्यक्ष महोदय, गरीब आदमी का अपना मकान हो यह सपना महात्मा गांधी जी ने देखा था। उनके इस सपने को पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने 2300 करोड़ रुपये की लागत से महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना तैयार की है। अध्यक्ष महोदय, यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2004-05 में तत्कालीन सरकार का टोटल प्लान आउटलेअ 2236 करोड़ रुपये था और उस 2236 करोड़ रुपये में से कितना पैसा उस सरकार ने लोगों की भलाई के लिए खर्च किया, कितना सड़को पर लगाया और कितना अन्य विकास कार्यों में लगाया यह तो मैं नहीं बता सकता लेकिन मैं यह जरूर कह सकता हूँ कि वह पैसा कहीं लगा हुआ हमें दिखाई नहीं दिया। वह सारा पैसा कहा गया इस पर तो भायद इन्दौरा जी ही रोशनी डाल सकते हैं। हम इंतजार करेंगे कि वे इस पर रोशनी डालें। अध्यक्ष महोदय, एक बात इन्दौरा जी को माननी ही पड़ेगी कि जो उनकी सरकार के समय में पूरा प्लान आउटले था 2236 करोड़ रुपये और उससे ज्यादा राशि यानि 2300 करोड़ रुपये की लागत से हमारे सरकार द्वारा गरीब आदमियों के परिवारों को 100-100 गज के मुफ्त प्लॉट देने की योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के परिवारों को, बी सी ए कैटेगरी के परिवारों को और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट मुफ्त दिये जाएंगे। पिछली सरकार का जितना प्लान बजट था उतने पैसों में हमारी सरकार द्वारा गरीब लोगों को मुफ्त प्लॉट दिये जा रहे हैं

ताकि वे अपना घर बसा सके। इस योजना के तहत दो साल में 6 लाख परिवारों को मुफ्त प्लॉट दिये जाएंगे और 27 जनवरी 2009 तक एक लाख 18 हजार से अधिक प्लॉट आबंटित किये जा चुके हैं। इन बस्तियों में सभी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करवाई जायेगी। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जातियों तथा विमुक्त व टपरीवास जातियों के लोगों को मकान बनाने के लिए दिये जाने वाले अनुदान की राशि को भी हमारी सरकार द्वारा 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 50000 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह से इंदिरा गांधी पेयजल स्कीम के तहत 977000 अनुसूचित जातियों के परिवारों को निजी कनेक्शन और पानी की टंकी मुफ्त प्रदान की जा रही है और अब तक साढ़े 4 लाख कनेक्शन दिये जा चुके हैं। उन परिवारों के लिए सरकार की बहुत बड़ी सोच थी कि जो लोग पीने के पानी से महारूम थे उन परिवारों के लिए पीने के पानी की टंकी और कनेक्शन लगा कर दिये जाये ताकि उनको पीने का पानी मिल सके। इसके तहत 9 लाख 77 हजार लोगों को इसका फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे व्यापारियों की भलाई के लिए बहुत से कार्य हमारी सरकार ने किये हैं। छोटे से छोटे व्यापारी से लेकर बड़े से बड़े व्यापारी तक को हमने राहत दी है। चाहे हलवाई हो, विक्रेता हो, खुद्रा विक्रेता हो, टूल विक्रेता हो, जूता विक्रेता हो या छोटा दुकानदार हो, सबके लिए वर्ष में एक लाख रुपये से कम कर अदा करने वाले व्यापारियों को वार्षिक कर वितरण दाखिल करने वाले व्यापारियों को वार्षिक कर विवरणी दाखिल करने की छूट दी

गई। वैंट डी-3 ज़री करने की न्यूनतम सीमा 10 हज़ार रुपये से बढाकर 25 हज़ार रुपये कर दी गई है। देरी से अदा करने के मामले में ब्याज की दर 90 दिन तक 1.5 प्रति ात कम करके 1 प्रति ात कर दी गई है और 90 दिन बाद यह दर 3 प्रति ात से घटा कर 2 प्रति ात कर दी गई है। घोशणा फार्म का प्रयोग किए बिना मैन्यूफैक्चरिंग में प्रयोग होने वाले 159 मदों पर कर की दर घटा कर 4 प्रति ात की गई है। चावल के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्यात पर कर वापसी का प्रावधान कर दिया है। जैसे राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण में सबसे पहले कहा गया कि पूरी दुनिया में मंदी के हालात पैदा हुए हैं। उस मंदी का असर हमारे हरियाणा प्रदेश पर भी है। यह असर खासतौर से उन लोगों पर जो व्यापारी भाहरों में बैठे हैं। और छोटे छोटे सन्नतकार जो छोटी छोटी चीज़ें बनाकर इस देश से दूसरे देशों में भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते थे पर हुआ है। आज उनका कारोबार बंद होने के कारण पर आ गया है। आज इस मैल्ट डाउन का असर पूरे हरियाणा में, पूरे देश में और हर सूबे में देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार उन लोगों के लिए और भी कुछ ऐसे प्रावधान करेगी जिससे उनको राहत मिलेगी। ऐसी टैक्स कन्सैशन हम उनको दे जिसकी वजह से जो व्यापारी आज मुश्किल में हैं उन व्यापारियों के उपर जो बोझ है वह थोड़ा सा कम हो सके और वह मंदी के सफर से निकल कर फिर अपना अच्छा व्यापार कर सके। इसकी वजह से फिर से सरकार को अच्छी आमदनी होने लगेगी और हमारी सरकार हमारे प्रदेश में और

अधिक उन्नति कर सकेगी। जो लोग आजादी के लिए लडे उन लोगों ने अपने लिए देा की आजादी नही मांगी थी आज अगर हम आजाद देा मे रह रहे है, आज अगर हम आजाद देा मे रह रहे है, तो इसकी वजह से है क्योंकि उन लोगों ने हमारे लिए और अपनी आने वाली नस्लो के लिए लडाई लडी थी। भले ही उनको बहुत सी कुर्बानियां देनी पडी और उन लोगों के परिवारो को जितना ज्यादा लाभ हो सके मिलना चाहिए। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। उसी फर्ज को सामने रखने हुए हमारी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियो को 1525 रुपये की जो पैँान मिलती थी उसको बढ़ाकर 5500 रुपये कर दिया है। हरियाणा सरकार द्वारा 60 वर्ष से अधिक उम्र के भूतपूर्व सैनिको तथा उनकी विधवाओ को जो कोई पैँान प्राप्त नही कर रहे थे, को एक हजार प्रति मास की वित्तीय सहायता भी दी जाती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भुपेन्द्र सिंह हुड्डा एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंध रखते है। उनके दादा और उनके पिताजी ने इस देा की आजादी के लिए कुर्बानियां दी थी और अपने परिवार मे उन्होने एक ही शिक्षा दी कि हम देा के लिए लडेंगे, देा की आजादी के लिए लडेंगे और उन्ही का अनुसरण करते हुए आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे देा की आजादी के उन परिवारो के खानदानो को चलाते हुए आज अपनी सरकार के जरिये इस प्रदेा के लिए और इस प्रदेा के लोगों के लिए लड रहे है। मुझे उम्मीद और विश्वास है कि जिस राह पर वे चल रहे है, जिस राह को हमारी सरकार ने पकडा है,



उस राह पर चलते हुए जैसे हमारे प्रदेश के लोग खुश हैं आज से पहले कभी इतने खुश नहीं हुए हैं, मेरे साथ बैठे हुए लोगों को आने वाले समय में इसका उदाहरण मिलेगा। इससे पहले कि मैं अपने भाषण को विराम दूँ मैं आपके सामने एक बात जरूर रखना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति आज से करीब 4 वर्ष पहले कैसी थी। 4-5 वर्ष पहले जैसी कानून व्यवस्था की स्थिति थी उसको बोलने बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। उस वक्त ऐसा लगता था कि हरियाणा दिल्ली के पास होते हुए भी एक ऐसा प्रदेश है जहाँ रहना दूभर और बहुत मुश्किल था। ऐसे लोग, जो सरेशाम गुनाह करते थे, सरेशाम जुल्म करते थे और गरीब आदमी को लूटते थे सरेशाम दूसरों की जायदाद पर नजर रखते थे। स्पीकर सर, ऐसे लोगों का उस समय बहुतायत था और इस प्रकार के इंसिडेंट्स आम होते थे। लेकिन इलाके में कुछ ऐसा वातावरण बना कि दूसरे लोगों और बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने यह मन बना लिया कि हरियाणा से पलायन करके किसी दूसरी जगह पर अपनी इंडस्ट्री और बिजनेस ले जाएंगे। स्पीकर सर, मुझे आज यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा में हमारी सरकार की नीतियों की वजह से पूरे देश में और विदेशों में भी हजारों लोगों ने यहाँ आकर अपनी इंडस्ट्री लगाने का मन बनाया है और इस प्रदेश में अपना धन लगाने की इच्छा व्यक्त की है। स्पीकर सर, इन भावों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ तथा सदन के सभी सदस्यों से यह

रैजोल्यू इन पास करने की प्रार्थना करता हूं और इसको स्पोर्ट करता हं।

**श्री उदयभान (हसनपुर, अनुसूचित जाति):** अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। 06 तारीख को महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिशाण सदन में रखा और उसके संबंध में माननीय साथी श्री विनोद भार्मा जी ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, उसके अनुमोदन के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने हमारे प्रदेश के महान सपूत चौधरी रणबीर सिंह जी, जो हमारे स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख सेनानी थे, के संबंध में जिक्र किया है। अध्यक्ष महोदय, चौधरी रणबीर सिंह जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को हम कुछ भावों में बयान नहीं कर सकते। स्पीकर सर, उनका संघर्ष तो इतनी बड़ी गाथा है कि उनकी प्रशंसा में कितनी ही किताबें लिखी जा सकती हैं। वे बहुत ही बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। वे हमारे देशभक्ति, ईमानदारी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति थे और एक आदर्शवादी और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। उनका जीवन राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और धार्मिक तौर पर बहुत बड़े संघर्षों की गाथा है। उन्होंने अपने जीवन काल में अपनी जवानी के दिनों में अंग्रेजों के शासन के खिलाफ संघर्ष किया। स्वाधीनता संग्राम के आन्दोलनों में भाग लिया और साठे तीन वर्षों के लिए कैद रहे और दो वर्षों तक नजरबन्दी की जेल में रहे। उन्होंने आठ साल तक अम्बाला, रोहतक, लाहौर, मुल्तान, स्यालकोट, हिसार,

फिरोजपुर, आदि जेलो मे हमारी आजादी के लिए अपनी जवानी के दिन गुजारे। स्पीकर सर, मै समझता हूं कि हिन्दुस्तान के वे प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो सात साल तक विधाई संस्थाओ के सदस्य रहे। वे संविधान सभा के एकमात्र जीवित सदस्य थे। जहां वे संविधान सभा के सदस्य रहे, वही पर वे अस्थाई लोक सभा, राज्य सभा, पंजाब विधान सभा और हरियाणा विधान सभा के सदस्य भी रहे। सभी अदायरो मे रहते हुए उन्होने दे 1 और प्रदे 1 की सेवा की है जिसकी कोई तुलना नही की जा सकती है। उन्होने सिंचाई मंत्री के रुप में पंजाब और हरियाणा के किसानो को जो कुछ दिया है उसको भुलाया नही जा सकता है। आज हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के अंदर जो खु 1हाली नजर आती है वह सब उनकी ही देन है। उनकी वजह से ही इन प्रदे 11 मे हरिज क्रांति आई है। स्पीकर सर, भाखडा बांध परियोजना भी उनके समय मे पूरी हुई और उसकी वजह से ही पंजाब और हरियाणा के किसानो ने बहुत तरक्की की है। इसके साथ साथ व्यास नदी पर पोंग डैम परियोजना भी उन्ही की देन है। हमारे यहां फरीदाबाद, गुडगांव, मेवात ओर पलवल चारो जिलो के साथ साथ राजस्थान के लोगो को भी गुडगांव कैनाल के माध्यम से सिंचाई सुविधा मिली है जिसका एकमात्र श्रेय श्री रणबीर सिंह जी को जाता है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के ये चारो जिले उनका यह अहसान कभी नही उतार सकते है। स्पीकर सर, उन्होने अपने पिता चौधरी मातुराम जी, अपने दादा चौधरी बचतावर सिंह जी से और आर्य समाज से सामाजिक मंच पर बोलने की प्रेरणा ली थी। अध्यक्ष महोदय, हमारे

स्वतंत्रता संग्राम के नायक लाला लाजपत राय जी और भाहीद आजम भगत सिंह जी के परिवारों से उनके संबंध थे उसका ही परिणाम था कि उन्होंने सामाजिक मोर्चे पर संघर्ष किया। उन्होंने गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी। हरिजनो और बैकवर्ड क्लासिज के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। वे हरिजन सेवक संघ और अखिल भारतीय पिछड़ा संघ के भी अध्यक्ष रहे। उन्होंने पिछड़े वर्ग के प्रति, जातिवाद के प्रति जो पाखंड था अवि वास था उसका विरुद्ध लड़ाई लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। चौधरी रणबीर सिंह जी हमारे इस प्रदेश के लिए और देश के लिए हमें प्रेरणा स्तोत्र बने रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने हरियाणा प्रदेश की सरकार के नीतिगत दस्तावेज का जो बयौरा पेश किया है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनके मंत्री मण्डल को बधाई देता हूँ कि उन्होंने चार साल के अंदर हरियाणा प्रदेश को कहा से कहाँ पहुँचा दिया है। अध्यक्ष महोदय, भार्गवा जी ने जिक्र किया था कि चार साल पहले वर्ष 2004-05 का प्लान बजट 2236 करोड़ रुपये था और अब 2009-10 में 10 हजार करोड़ रुपये का प्लान बजट है। यह इस बात को दर्शाता है कि हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कितना बेहतरीन और भावदार कार्य किया है। यह जो पाँच गुण प्लान बजट में वृद्धि हुई है उसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा पिछले साल 6650 करोड़ रुपये का प्लान बजट था जो कि इस बार 10 हजार करोड़ रुपये का है। इस बजट में

50 प्रति आत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है इस प्रकार से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सपना देखा था और कहा था कि हरियाणा प्रदेश को नम्बर एक पर लाउंगा उसको कार्यान्वित करते हुए आज जो प्रति व्यक्ति आय हरियाणा प्रदेश की है वह पूरे देश में गोवा के बाद दूसरे नम्बर पर है। यह आय 58 हजार 531 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है जो कि अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। इसी प्रकार से इन्वैस्टमेंट के रूप में सी एम आई (सेन्टर फार मानिट्रिंग आफ इंडियन इकोनोमी) की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक हरियाणा प्रदेश इन्वैस्टमेंट के मामले में नम्बर एक पर है। रिपोर्ट के हिसाब से 78 हजार 5 सौ रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से इन्वैस्टमेंट हुई है। अध्यक्ष महोदय, पांच साल पहले जो इनेलो की सरकार थी उनके समय में हरियाणा प्रदेश इन्वैस्टमेंट के मामले में 13वें नंबर पर था और आज वही हरियाणा प्रदेश पहले नम्बर पर है। इसके लिए मैं इस सरकार को और सरकार के मंत्रिमण्डल को बधाई देता हूँ। जहाँ तक सरकार का आम आदमी को लीजा देने का सवाल है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है बिजली के बिलों के ब्याज के बारे में पिछली सरकार बनने से पहले वे कहते हैं कि न मीटर रहेगा और न रीउर रहेगा। वे उस समय कहते हैं कि बिजली तो आएगी लेकिन मीटर नहीं रहेगा। उनका उस समय यह भी कहना था कि बिजली के बिल देने की जरूरत नहीं है। ये लोगों को भडकाते थे और कहते हैं कि जब हमारा राज आएगा तो बिजली के बिल किसी को भरने की जरूरत नहीं होगी और अगर बिजली वाले बिजली के बिल मांगने

आए तो आ उनके नाम कान काट लेना। वे लोगों को कहते हैं कि आप उस्तरा रखो और एक ब्लेड रखों उसके बाद लोगों ने बहकावे में आकर बिजली के बिल भरने बंद कर दिए। भारतीय किसान युनियन के अध्यक्ष और दूसरे लोगों ने अपनी झौली फैलाकर गांव गांव जाकर इनके लिए वोट मांगे राम गुप्ता और इनकी सरकार बनी। अध्यक्ष महोदय, इनका बिजली के बिल न भरने का बिल्कुल झुठा आ वासन था। जिन्होंने इनके लिए वोट मांगे राम गुप्ता थे जब उन्होंने इनसे कहा कि आपकी वजह से लोगों ने बिजली के बिल नहीं भरे और अब उनके उपर ब्याज का बोझ चढ गया है इसलिए अब आप कम से कम ब्याज तो माफ कर दें। स्पीकर सर, आपको भी पता है कि इनके राज में एक दो नहीं बल्कि नौ नौ किसानों को गोलियों से उठाया गया था। स्पीकर सर, भारतीय किसान युनियन के अध्यक्ष घासीराम नैन ने घर घर जाकर इनकी सरकार बनवाने के लिए वोट मांगे थे। लेकिन जब उन्होंने बिजली के बिलों के ब्याज माफ करने के लिए कहा तो उन पर केस दर्ज करके वे धाराएं लगायी गयी जो दे । द्रोहियों, उग्रवादियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों पर लगाई जाती है। इस तरह की धाराएं लगाकर उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। मैं चौधरी भुपेन्द्र सिंह हुडडा जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने बगैर किसी मांग के बिजली के बिल माफ किए। कांग्रेस पार्टी का इस बारे में कोई वपायदा नहीं था फिर भी उन्होंने एक कलम से ही 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ कर दिए। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। इसी प्रकार से

823 करोड रुपये के कोओपरेटिव बैंक के, लैंड मार्टगेज के, हरियाणा हरिजन कल्याण निगम के, बैकवर्ड क्लासिज निगम के या लाई गई लोगों के जो लोन थे, जो ब्याज था वे सभी उन्होंने माफ कर दिए। हाउस टैक्स चाहे वह देहात में रहने वालों का हो या भाहर में रहने वालों का हो, सभी का माफ करने का भी काम किया है। मैं इसके लिए सरकार का धन्यवाद करता हूँ और अगार व्यक्त करता हूँ स्पीकर साहब, बिजली, सडक और पानी एक बुनियादी आवयकता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और बिजली मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि बिजली जैसे मामले में जहां पिछली सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया उन्होंने एक भी प्रोजैक्ट नहीं लगाया वही हमारी सरकार ने बिजली के चार चार प्रोजैक्ट टेअप किए हैं। पहले केवल 1857 मैगरावाट बिजली का ही अपने लेवल पर उत्पादन होता था। स्पीकर सर, आपको पता ही है कि एक प्रोजैक्ट तैयार करने में तीन साल तो कम से कम लग ही जाते हैं क्योंकि सबसे पहले जमीन एक्वायर करनी पडती है। उसके लिए धन मुहैया करवाना पडता है। जो मूलभूत आवयकताएं हैं उनको उपलब्ध करवाना पडता है। जो रॉ मैटीरियल है उसके लिए इंतजाम करना पडता है और यह देखना होता है कि यह प्लांट कोल बेस्ड होगा, नैप्था बेस्ड होगा या गैस बेस्ड होगा। मैं आ चर्यचकित हूँ कि चार चार प्रोजैक्ट इस सरकार ने टेकअप किए हैं। यमुनानगर का जो थर्मल प्लांट है यह पहले बीस पच्चीस साल से उलझा पडा था क्योंकि पहले वाली सरकार लेनदेन के चक्कर में पडी थी, उनका सौदा नहीं पटा था।

अब इस सरकार के आते ही उसका काम भुरु हुआ है। न केवल काम भुरु हो गया है बल्कि आज वह रिकार्ड समय में पूरा भी हो गया है और अब उससे उत्पादन भी भुरु हो गया है। स्पीकर सर, इसी तरह से हिसार जिले में खेदउ गांव में 1200 मैगावाट के राजीव गांधी थर्मल प्लांट की 600 मैगावाट की पहली ईकाई का कार्य दिसम्बर 2008 में और 600 मैगावाट का दूसरी ईकाई का कार्य मार्च, 2010 में पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार से झाडली में 1500 मैगावाट का एक ओर प्रोजैक्ट है इसमें से आधी बिजली हमें मिलेगी। इसी तरह से 1320 मैगावाट का एक ओर प्रोजैक्ट है इसमें से आधी बिजली हमें मिलेगी। इसी तरह से 1320 मैगावाट का एक ओर प्रोजैक्ट झज्जर में आ रहा है। इसके अलावा 3835 मैगावाट बिजली केन्द्र सरकार की विभिन्न परियोजनाओं से मिलने की व्यवस्था की गई। मैं इसके लिए सरकार को बधाई देता हूं क्योंकि सरकार ने यह मामला बहुत गंभीरता से लिया है। इसके अलावा अक्षय उर्जा नीति के तहत 709 मैगावाट बिजली उत्पादन के लिए भी स्वतंत्र बिजली उत्पादकों के साथ समझौते किए गए हैं। इसके अलावा ट्रांसमिशन लाईन पर सब स्टेपों की क्षमता बढ़ायी गयी है जो कि बिजली विभागी की तरफ से बहुत सराहनीय कार्य हुआ है। मैं इसके लिए सरकार को बहुत बधाई देता हूं। जहां तक सड़कों की बात है, वर्ष 2008-09 में सड़कों का बजट 670 करोड़ रुपए था जो अब बढ़कर 1540 करोड़ रुपए कर दिया गया है यानि दोगुने से भी ज्यादा सड़कों का बजट इस सरकार ने किया है। **17:00 बजे** अब सड़कों के बारे में चर्चा हुई है। सरकार



ने जो कदम उठाए हैं उन पर चैक करने की जरूरत है ताकि कहीं क्वालिटी से कोई समझौता न हो, यह तो अलग बात है लेकिन सरकार ने जो काम किया है वह नजर आता है। सड़को के लिए वर्ष 2009-10 में बजट दुगना किया गया है, 1540 करोड़ रुपये का बजट किया है। एन सी आर, नाबार्ड और पी एम जी एस वाई की स्कीम के तहत 2200 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य शुरू किए गए हैं जिनके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को इनके इस प्रयास के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि वर्ष 1966 से 2005 तक 16 आर और बी बने और इन चार सालों में 33 आर और बी पर काम चल रहा है जिनमें से 9 पूरे भी हो चुके हैं और 7 आर और बी दिसम्बर 2009 तक पूरे हो जाएंगे। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं बधाई भी देना चाहूंगा और साथी ही साथ एक रिकवैस्ट भी करना चाहूंगा। मुझे इस बारे में आवासन भी दे रखा है कि होडल हसनपुर रोड पर जैसे आर और बी के बारे में लिखित उत्तर में बताया, वह आर और बी 25 करोड़ 14 लाख रुपये की लागत से सैंगलान किया गया है उसमें रेलवे विभागी के अधिकारी की इस्पैक्टान रिपोर्ट बाकी कची है उसको भी जल्दी से पूरा कराएंगे, ऐसी उम्मीद है। इसकी हमारे इलाके में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। खुद मंत्री जी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं। हमारे होडल हसनपुर वाले आर और बी को जल्दी से शुरू करवाने की कृपा करें दूसरी जो सड़के हैं रसुलपुर से वाया गुलाबपुर हसनपुर इसके अलावा

पालरी, मुंडफटी, मानपुरा और कौंडल गांव की सडक है। ये सडके पी एम जी एस वाई से मंजूर हुई थी और इनकी बहुत ही खस्ता हालत है। इन सडको के लिए फंड चाहे नाबार्ड से लो, चाहे एन सी आर या पी एम जी एस वाई से ले लेकिन इन सडको को जल्दी से जल्दी बनवाने का कश्ट करें जहां तक पानी का मामला है, उसके लिए भी सरकार ने बहुत प्रयास किए है। चौधरी रणबीर सिंह जी के समय से रेणुका और किसान बांध की प्रपोजल चली थी, पिछली सरकार ने इस आरे बिलकुल ध्यान नहीं दिया था। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और सिंचाई मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। ये कई बार इस सिलसिले में दिल्ली में मीटिंग्स में गए और इस मामले को पूरे जोर भाोर से उन मीटिंग्स में उठाया। रेणुका बांध हमारे हाथ से खिसक चुका था। उसको इन्होंने दोबारा से सिरे लगाने का प्रयास किया और उसके लिए 100 करोड रुपए की राशि भी दी। मुख्यमंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी के प्रयासों और इंटरवेंशन से हमें इस मामले में काफी कुछ कामयाबी मिली है। अध्यक्ष महोदय, रेणुका, किसान और लखवार डैम हमारे दक्षिणी हरियाणा की जीवन रेखा है। जहां तक हमारे फरीदाबाद और गुडगांव एरिया में सिंचाई का सवाल है, जब इनमें कुछ पानी स्टोर हो जाए तो पुरा पानी इधर से ही आ सकता है। सिंचाई के पानी की सबसे बुरी हालत हमारे गुडगांव, फरीदाबाद और मेवात के हिस्से में है। जैसा कि मंत्री जी के नोटिस में भी है कि मेरा जो क्षेत्र है उसमें तीन रजवाहे हैं जो आगरा कैनल से जाते हैं उनमें एक तो होडल रजवाहा है, दूसरा

हसनपुर रहवाहा है और तीसरा हथीन रजबाहा है। इन तीनों की टेल मेरे हल्के में जाती है और टेल पर पानी नहीं है। इसलिए मेरा क्षेत्र इससे सबसे ज्यादा अफैक्टिड है। होडल के आसपास जो 15 किलोमीटर के रेडियस के गांव है, वे सारे के सारे अफैक्टिड है उनमें किसी में भी पानी नहीं है मैं बताना चाहूंगा कि बंचारी, सौंगा, डाडका, बोराका, सोमवास, गोडा पट्टी, होडल, बलवाना और डकोरा ये ऐसे गांव है जहां न तो सिंचाई के लिए पानी है और न पीने का पानी है। जहां तक अंडरग्राउंड वाटर की बात है, वह खारा है। ये बहुत बड़े बड़े गांव है और सीधे तौर पर अफैक्टिड है। जो गोश्टी ड्रेन है उस पर लिफ्ट चैनल लगाकर डाडका माइनर के माध्यम से इनकी सिंचाई हो सकती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि क्या वे इस बारे में जांच करवाएंगे और इस स्कीम के माध्यम से उन गांवों में सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाने की कृपा करेंगे? मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि बन्चारी, सराये, सोन्ध, होडल आदि गांवों में पीने का पानी जरूर पहुंचाये। इन गांवों के बारे में 18 दिसम्बर, 2005 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार की घोषणा में कहा था कि होडल सब डिवीजन के किसी भी गांव में पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन पांच छह गांवों में पीने के पानी की सही व्यवस्था नहीं है। बन्चारी गांव में तो पानी बिल्कुल नहीं है। हालांकि वहां पर पीने के पानी की स्क्रीम मंजूर हो गई है और 10-12 किलोमीटर से पानी आयेगा लेकिन उसमें बहुत डिले हो रही है। वह स्कीम पूरी होने वाली थी

लेकिन कान्द्रक्टर बीच में ही काम छोड़कर चला गया है। इस स्कीम को थोड़ा सा काम बाकी है उसको भी पूरा करवाने की जरूरत है। आपके माध्यम से मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस तरफ भी ध्यान दिया जाए। जहां तक भाहरी विकास का मामला है, इसमें सरकार ने सराहनीय कार्य किया है इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे हल्के की नगरपालिका को पिछली सरकार के समय चौटाला साहब ने भंग कर दिया था लेकिन इस सरकार ने उस नगरपालिका को दोबारा से बहाल कर दिया है इसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ।

**श्री अध्यक्ष:** क्यों भंग कर दी थी?

**श्री उदय भान:** स्पीकर सर, चौटाला साहब भेदभाव का रवैया रखने वाले थे इसलिए हमारी नगरपालिका को भंग कर दिया गया था और उनको इन कर्मों की सजा भी मिल गई। अभी तो इनके पल्ले कुछ नहीं है। अभी तो इनको इस बात के लिए खेदना है। इन्होंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है कि ये अकेले दम पर कांग्रेस पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। ये तो कोई न कोई बै ग़ाखी ढुंढते हैं चाहे हाथी का सहारा मिल जाये चाहे बी जे पी का कमल मिल जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी याददा त ताजा करना चाहूंगा। हमारे फरीदाबाद में बी जे पी नेता चाहे उस समय के अध्यक्ष श्री रतन लाल कटारिया हो, या बीजे पी पार्टी के विधायक दल के नेता श्री कुशुणपाल गुर्जर हो

इनमे से कोई भी ऐसा नेता नहीं था जिसके लठठ नहीं लगे हो, जिनकी पिटाई न हुई हो और गोली न चली हो। सबके कुर्ते फाड़ दिए और इन्होंने अटल जी और आडवाणी जी को जाकर त्राहि माम न किया हो कि हमें चौटाला जी के जुल्मों से बचाओ। उस जालिम से बचाओ। ये लोग बहुत बुरी तरह से जाकर रोए और अब जाकर इन्होंने एक अवैध गठबंधन कर लिया। अध्यक्ष महोदय, अवैध रि तो का तो पता है उनका हाल तो वही होना है जो चांद मोहम्मद और फिजा का हुआ है। वह गठबन्धन ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इनकी तो नेवला और सांप वाली दोस्ती है। ( गोर) अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को और मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसी पापुले उन जो विलेजिज और भाहरा में थी जहां 50 प्रति 100 से ज्यादा आबादी थी उनके डिवलपमेंट के लिए 50 लाख रुपये दिये गये जोकि बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। उसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। मेरे हलके में होडल में वार्ड नम्बर 9 किसी वजह से रह गया है उसके लिए सरकार से मेरा निवेदन है कि वहां पर पोपुले उन 60 प्रति 100 से ज्यादा है और उसके लिए पैसा अभी तक नह पहुंचा है। मंत्री जी से निवेदन है कि वहां पर पैसा पहुंचाया जाए। दो गावों बुधराना और पिंगोठ भी इसी कंडी उन में आते हैं। जो सुविधा मंत्री जी ने धोशित की है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वहां पर सुविधा मुहैया करवाई जाए। मैं इस सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दलित परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट देकर इतना बड़ा काम किया है। अध्यक्ष महोदय, यह काम 40 साल पहले

श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। हरियाणा प्रदेश में पूरे हिन्दुस्तान के अंदर पहला प्रदेश है जहां पर यह योजना लागू की जा रही है और लगभग एक लाख 18 हजार लोगों को महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत प्लॉट अलॉट कर दिए गए हैं। यह बहुत बड़ा कार्य किया गया है और इसको भुलाया नहीं जा सकता। गरीब आदमी अगली बार ब्याज समेत सरकार को इसकी भरपाई करेगा, इसको कोई दो राय नहीं है। 40 साल पहले लोगों के पास गुंजाई नहीं होती थी। जितनी आज एक गज जमीन की कीमत है उस समय इतनी कीमत में दो एकड़ जमीन आ जाती थी। आज एक गज, एक फुट तो क्या एक इंच जमीन के पीछे गोलियां चल जाती हैं। आज के जमाने में एक आदमी के चार बेटे हों और उनके अलग अलग रॉयल्टी कार्ड हों और उनको अगर 500 गज जमीन मिलती है तो 500 गज जमीन की जितनी वैल्यू है उतनी वह सारी जिंदगी में भी नहीं कमा सकता। गरीबों को प्लॉट देना सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें निश्चित तौर पर सरकार ने 6 लाख 7 हजार परिवारों को लाभ होना बताया है जो कि एक सराहनीय कार्य है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें थोड़ा संतोष किया जाए कि जो लोग इस लाभ से किसी न किसी तरह वंचित रह गए हैं और उनको हक बनता है तो उनकी एप्लीकेशन लेकर जांच करवाकर उनको ये प्लॉट दिये जाए। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में आज सरकार ने अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। खासकर भीमराव अम्बेडकर ने सबसे पहले शिक्षित बनो का नारा लगाया था उसको हमारे

मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुडडा जी ने अमलीजामा पहनाया है। जो गरीब बच्चे पढाई न छोड जाते थे, कोई 5वीं पढकर, कोई 8वीं पढकर और कोई 10वीं कक्षा तक पढकर वे पढाई न छोड जाए उसके लिए उनको वजीफा देने का बहुत बडा काम इस सरकार द्वारा किया गया है। जो एस सी/ बी सीज के पहली क्लास मे बच्चे पढने जाएंगे, उनको पीले कार्ड की जरूरत नही है और साथी ही बी पी एल वाली दूसरी जातियो के बच्चो को किताबे फ्री, वर्दी फ्री और साथ मे लडके को 100 रुपये वाली दूसरी जातियो के बच्चो को किताबे फ्री, देना का काम किया है। छठी से आठवीं कक्षा तक के लडको को 100 रुपये और लडकिया को 150 रुपये प्रति मास देने का काम किया है। छठी से आठवीं तक के लडको को 150 रुपये और लडकी को 200 रुपये प्रति माह और ग्याहरवी और बाहरवीं कक्षा तक के विज्ञान पढने वाले लडको को 300 रुपये प्रति माह तथा लडकियो को 400 रुपये प्रति माह वजीफे के रुप मे देने का जो काम किया गया है, वह एक सराहनीय कदम है और इसको एस सी और बी सी क्लास की पीढियां और खासकर दलित वर्ग के लोग कभी भुला नही सकते। अध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन बातें और कहना चाहूंगा। अगर सरकार इनको पूरा करवा दे तो न कोई हाथी बिगाड सकेगा, न कोई डायनोसार बिगाड सकेगा और न ही कोई अष्टावक हमारा कुछ बिगाड सकेगा। इन मे से किसी के बस मे भी कुछ नही रहेगा। अध्यक्ष महोदय, दो तीन काम आप हमारे और करवा दें। एस सी और बी सी कैटेगरी के रिजर्वे इन मे जो बैकलाग है उसको पूरा कर दिया जाए तो बहुत

अच्छा होगा। अध्यक्ष महोदय, संविधान का जो 85वां संशोधन सरकार ने किया है जो 16.3.2006 से प्रोसपैक्टिड है उसको रिट्रोसपैक्टिव करो। 17 जून, 1985 के संविधान की जो मूल भावना है इसको पूरी तरह से पूर्ण भावना के साथ लागू करें अध्यक्ष महोदय, क्लास-1 और क्लास 2 की प्रमोशन में रिजर्वेशन दी जाए तो आप देखेंगे कि इसके बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप से यह अनुरोध करूंगा कि आप हमारी इन मांगों पर गौर करें और मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि मैंने जो बताया है उन बातों को नोट कर लें और इनको पूर्ण करवा दें। धन्यवाद

**Mr Speaker:** Motion moved-

That an address be presented to the Governor in the following terms:

“That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 6<sup>th</sup> February, 2009 at 2:00 P.M.”

**डा सु लिल इन्दौरा:** अध्यक्ष महोदय, माननीय विनोद भार्मा जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर दिया है मैं उस पर चर्चा करने के लिए खड़ा हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं अभिभाषण की शुरुआत चौधरी रणबीर सिंह जी से करूंगा जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे। चौधरी रणबीर सिंह जी ने जिस तरीके से अपने व्यक्तित्व को उभारा और संवारा,



वह किसी समुदाय और किसी संस्था में सुकुचित होकर नहीं रह सकता, कहने को भले ही वे कांग्रेसी थे लेकिन पूरे समाज का हित उनके अपने चिंतन में समाहित था। मैं समझता हूँ कि आज दे आ को इसकी आवश्यकता है। इसके साथ ही मैं उन लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि आज प्रदेश को दि आ देने का दावा करने वाले नेताओं को अगर चौधरी रणबीर सिंह जी के जीवन से कुछ सीखना है तो सबसे पहली चीज यह है कि वे अपने समस्त चिंतन को समाज के हित में लगाये। मैं चौधरी रणबीर सिंह जी के बारे में कुछ भाव्य कहना चाहूँगा कि सच्चाई की बात कहने वाली एक राजनीतिक, दे आभक्त आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। ऐसे दे आ भक्तों और राजनीतिज्ञों को ही याद किया जाता है। स्पीकर सर, इस सदन की एक परम्परा है कि जब भी वर्ष के प्रारम्भ में विधान सभा का प्रथम सत्र आन भुरु होता है तो सर्वप्रथम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से सरकार अपनी नीतियों और कार्यक्रमों का उल्लेख करके बताती है कि वह भविष्य में प्रदेश के लोगों के लिए क्या करने जा रही है और प्रदेश के लोगों के प्रति सरकार की क्या सोच है। अभिभाषण के माध्यम से समाज को आईना दिखाया जाता है कि सरकार किस तरह की नीतियाँ और कार्यक्रम बनाकर हर वर्ग का भला और हर प्रकार के विकास के कार्य करती है। स्पीकर सर, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अभिभाषण में कहीं कोई ऐसी झलक नहीं है। सरकार का गुणगान तो बहुत है और सरकार की प्रगति के कसौड़े भी

बहुत पढे गये है। जैसे अभी माननीय विनोद भार्मा ही कह रहे थे कि घुमारियां मे परमाणु बिजली घर लगा देंगे। यह तो कोसो दूर की बात है। ऐसी बाते तो कही गई है लेकिन हकीकत और सच्चाई की बात यह है कि गरीब आदमी को कैसे अपना पेट भरने के काबिल बनाया जायेगा और जो लोग काम की तलाश में आज दर दर भटक रहे है उन बेरोजगारो को कैसे रोजगार देकर लोगों का सम्पूर्ण जीवन संवारा जाएगा, इसके बारे में अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया है। स्पीकर सर, अभी एक माननीय सदस्य विनोद भार्मा जी ने चुनावी वायदो का जिक्र किया। मैं चुनावी वायदो पर तो बाद में आउगा लेकिन अभिभाषण में आर्थिक मंदी की भी बात की गई है। अभिभाषण में भुरु में कहा गया है कि आज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक मंदी है और अगर देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है तो प्रदेशों का भी आर्थिक मंदी से गुजरना स्वाभाविक है। प्रदेशों भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। आर्थिक मंदी के क्या कारण है यह कही नहीं बताया गया है। आर्थिक मंदी की परिभाषा भी नहीं दी गई है सिर्फ आर्थिक मंदी का जिक्र किया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए सरकार का असफल प्रयास होते है कि अपनी असफलताओं को कैसे छिपाया जाये। हरियाणा सरकार ने भी अपनी असफलताओं को छिपाने के भरपूर प्रयास किए है लेकिन असफलताओं को दिपाना बहुत मुश्किल है। इन्ही कारणों से बेकारी और भुखमरी बढ़ रही है और किसान आत्महत्याये कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, मुझे एक रिपोर्ट पढने को

मिली जिसमे बताया गया था कि दे 1 में 17 हजार किसानों द्वारा आत्महत्याए की गई है। कांग्रेस पार्टी की जो राज्य और केन्द्र सरकार किसानों का मसीहा होने का दावा करे, उसके राज में किसानों द्वारा आत्महत्याए करना बड़ी चिंता की बात है। विव 1 लोग सरकार से जो उम्मीदे करते है कांग्रेस के लोग उनको कैसे पूरा कर सकते है? अध्यक्ष महोदय, आज आर्थिक मंदी का रोग रोया जा रहा है। आर्थिक मंदी का मतलब अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालने की को 1 1 की जा रही है सिवाय इसके और कुछ भी नहीं है। आर्थिक मंदी का मतलब होता है उत्पादित वस्तु का मूल्य कम हो जाना और जो उत्पादित वस्तुएं है उनका बहुतायात हो जाना। दे 1 में इतनी मात्रा में वस्तुएं हो कि उनको कोई खरीदने वाला ही नहीं हो। मैं तो समझता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आज कहीं नहीं लग रहा कि दे 1 में जो उत्पादित वस्तु है उनकी कीमत कम है या कहीं पर ऐसा भी नहीं लग रहा कि आर्थिक मंदी के नाम पर जो चीजे है वे बहुतायात में है और हमें खुले तौर पर मिल रही है। लेकिन फिर भी एक ढकोसला बनाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री और यू पी ए अध्यक्ष सोनिया गांधी को धन्यवाद दिया जाता है कि हमने इस आर्थिक मंदी पर कंट्रोल कर लिया है। आर्थिक मंदी के नाम पर पैकेज दिये जा रहे है। लेकिन वे पैकेज भी बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिये जा रह है न कि किसी गरीब किसान को। यह हकीकत भी है ओर सभी जानते है कि कांग्रेस की सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, गरीब आदमी और गरीब किसान के लिए उनके दिल में

कोई जगह नहीं है। किसानों के लिए यह सिर्फ ढकोसला करती है और किसान के लिए काम नहीं करती। मैं मजदूर का बेटा हूँ मजदूर तो किसान के खेत में काम करता है और मुझे पता है कि किसान के खेत में कैसे काम किया जाता है। आर्थिक मंदी अगर देखने को मिली है तो यहाँ बड़े बड़े भोयर बाजारों पर देखने को मिली है। बड़े औद्योगिक घरानों को दे 1 में 150000 करोड़ रुपये की हानि देखी गई है। इसमें दो राय नहीं या म्यूचुअल फंड में मंदी देखी गई है। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया था कि जितने भी सरकारी बैंक हैं अप्रैल से लेकर दिसम्बर 2008 तक उन्होंने मुनाफा कमाया है और उसके बावजूद भी रिजर्व बैंक आफ इंडिया उनको आर्थिक पैकेज दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, 3 लाख हजार करोड़ रुपये के करीब रिजर्व बैंक ने सिर्फ बैंकों को पैकेज दिया है जबकि बैंक मुनाफा कमा रहे थे। आर्थिक मंदी का रौना रौने वाले लोगों को बता रहा हूँ कि कांग्रेस सरकार ने आर्थिक मंदी के लिए क्या किया है? स्पीकर सर, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये जो लाभ कमाने वाले बैंक हैं उनको रिजर्व बैंक ने कैसे पैकेज दे दिया, यह कोई आर्थिक प्रबंधन नहीं है।

**श्री अध्यक्ष:** इन्दौरा जी, आप पार्लियामेंट में बोल रहे हैं या असेम्बली में बोल रहे हैं?

**डा सु गील इन्दौरा:** अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो भुरुआत में बात कही गई है मैं उसी पर

बोल रहा हूँ। अगर भगुरु मे आप कुछ पन्ने पलट कर देखे तो यही बाते लिखी हुई है। मै भी वही बात कहते हुए हरियाणा की ओर जा रहा हूँ कि ऐसे आर्थिक प्रबंधन का दावा करने वाली यह हरियाणा प्रदेा की सरकार है, वह भी इसी तरह की गतिविधियों से अछूती नहीं है। इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेा की जो आर्थिक कहानिया घडी जा रही है जैसे कहा गया है कि वर्ष 2007-08 मे प्रति व्यक्ति आय 58531 रुपये आंकी गई है। (इस समय सभापतियो की सूची मे से एक माननीय सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल पदासीन हुए) सभापति महोदय, वर्ष 2007-08 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) का आंकलन 153087 करोड रुपये किया गया जबकि वर्ष 2006-07 मे यह 130033 करोड रुपय था और वर्तमान मूल्यो पर 17.7 प्रति शत वृद्धि दर्ज की गई है। जो पर कैपिटा इन्कम दिखाई गई है वह औसतन दिखाई गई है लेकिन उसमे यह तो बताया ही नहीं है कि कौन इससे नीचे है और कितने परसेंट लोग इससे उपर है। मेरी मान्यता है कि अगर हम सही आंकलन करे और सही ढंग से देखे तो पर कैपिटा इन्कम में हरियाणा आगे नहीं है जबकि सरकार कहती है कि गोवा के बाद हमारा दूसरा नम्बर है। हम इस बात को मान भी ले तो पर कैपिटा इन्कम मे कितने ऐसे लोग है इसकी कोई दर भी नहीं बताई गई है। थोडे से लोग हो सकते छे जिनके पास पैसो की कोई कमी नहीं होगी लेकिन ज्यादातर लोग गरीब है फिर भी हम बडे गर्व के साथ कहते हे कि हम नम्बर एक है। चेयरमैन साहब, दूसरी बात यह है कि मै हरियाणा न्यूज

देखता हूँ और हरियाणा न्यूज में पर कैपिटल इन्कम भी आती है। दूसरी जगहों से भी आंकड़े आते हैं मैं उनका भी जिक्र करूंगा। बड़े दावे के साथ ये लोग उंगली उठा कर यह कहते हैं कि हरियाणा नम्बर वन पर है लेकिन हरियाणा नम्बर वन पर कहां से है? जिस प्रदेश में किसान को वक्त पर खाद नहीं मिलती, जिस प्रदेश में किसानों की लागत मूल्य बीज से ज्यादा है वह हरियाणा प्रदेश में किस प्रकार से नम्बर वन पर आ पाएगा? चेयरमैन साहब, बड़े दावे किए जाते हैं कि इतनी बिजली पैदा कर दी। बिजली के बारे में मैं थोड़ी देर में आता हूँ। चेयरमैन सर, मैं यह कहना चाहता था कि इस पर कैपिटल इन्कम का क्या फायदा हुआ है। इसके अधिक से अधिक भरमार उन लोगों की है जिनकी इन्कम 5800 से भी कम है वे लोग अपने बच्चों को शिक्षा कहाँ से दिलवाएंगे क्या उनके लिए सरकार ने कोई इंतजाम किया है। मुझे तो नहीं लगता कि सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान दिया है। ऐसे बच्चे जिनकी आमदनी कम है वे अपने अभिभावकों को जीवनयापन के साधन कैसे मुहैया करवा पाएंगे, कैसे उनकी देख रेख कर पाएंगे? यह सब कैसे होगा? जिन बेचारों के पास झोपड़ी तक नहीं है और सिर ढंकने के लिए छत नहीं है इस महंगाई के दौर में वे लोग अपने सिर छिपाने के लिए किस प्रकार से झोपड़ी तैयार कर पाएंगे यह तो सरकार ने बताया ही नहीं। बड़े बड़े दावे के साथ एक बात कह दी कि हरियाणा प्रदेश में नम्बर एक पर है। चेयरमैन साहब, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि ये लोग गरीबों की बात करते हैं। हरियाणा प्रदेश की सरकार और

केन्द्रीय सरकार इस दे 1 का हिस्सा है। अगर यहां पर हम केन्द्र सरकार की बात कर रहे हैं तो कृषि के नाम पर सरकार ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहे दे 1 में हो या प्रदेश की हो ये लोग राजनीतिक रोटियां सेंकने में कोई गुरज नहीं करते हैं। चेरमैन सर, ये लोग कोई न कोई ऐसा भी 11 छोड़ देते हैं जिससे किसानों को कम फायदा होता है और उनके बीच के दलालों को ज्यादा फायदा होता है। आज अगर हम सही मायनों में देखें तो किसानों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही हैं। अगर खाद की बात करें तो किसानों को खाद वक्त पर नहीं मिलता। अभी हमारे साथी उदय भान जी कह रहे थे कि तीन नहरे लगती हैं लेकिन टेल पर आत तक पानी नहीं पहुंचा है। जब जरूरत होती है तो खाद के वक्त खाद नहीं और बीत के वक्त किसानों को बीज नहीं मिलता। यहां तक कि जब बेचारा किसान डीजल से अपनी फसल पकाने का काम कर रहा होता है तो वह भी समय पर नहीं मिलता है। चेरमैन सर, इस प्रकार से किसानों का भला कैसे होगा? अगर हम आंकड़ों में देखें तो हमें सबसिडी के नाम पर क्या मिलता है? केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही सबसिडी की बात करें तो सबसिडी का असर सीधे हरियाणा सरकार पर भी पड़ता है। सबसिडी के नाम पर करोड़ों रुपये दिये जाते हैं लेकिन किसानों को उसका कोई फायदा नहीं मिलता है। करोड़ों रुपये की सबसिडी दी जाती है लेकिन उसमें हमने किसानों के लिए कभी प्रयास नहीं किया कि किसानों की जो फसल है उसका लागत मूल्य कम हो और उसकी उपज है उसके भाव को

बढाने का काम करते। हमने पिछली बार 46 रुपये कपास का समर्थन मूल्य बढाने का काम किया था। केन्द्र सरकार समर्थन मूल्य बढाकर किसान की आस जगा देती है कि सरकार कुछ तो देगी। चाहे गेहूं की बात हो चाहे दूसरी फसलो की बात हो, लेकिन उस अहास मे मिलता क्या है। अभी यहां पर ये कह रहे थे कि हमने पूसा धान पर प्रतिबंध हटा दिया आज 100 रुपये की जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी वह घटा दी लेकिन इससे किसानो को क्या मिला। किसान के हाथ से निकल कर वह धान तो अब बिचौलियो के हाथ मे चला गया है तो आपने एक्सपोर्ट ड्यूटी घटा दी और वाहवाही लूट ली लेकिन यह ड्यूटी तो किसानो का भला नही कर सकती है। आपने उस वकत प्रतिबंध हटाया जब उसके भाव गिर रहे थे। आज आप मुच्चदल धान का भाव जाकर पूछो। (विघ्न) किसानो की जीरी किस भाव मे बिकी थी, आप वह भी देख ले और आज किस भाव मे बिक रही है वह भी देख लें। आज जीरी को 1300-1400 रुपये प्रति क्विंटल मे भी कोई नही पूछता। किसानो ने अपनी जीरी को घरो मे तुडी की तरह रखा था लेकिन उसका उनको कोई फायदा नही हुआ। उन्होने गिली जीरी घरो मे रख ली थी और वह सुख कर आधी हो गई लेकिन उनको उसका कुछ भाव नही मिला और आज यह सरकार किसानो के भले की बात करती है। चेयरमैन साहब, कृशि वि ेशज्ञो की जो रिपोर्ट है मै उसके अनुसार बताना चाहता हूं कि गेहूं कि प्रति एकड लागत 22700 रुपये थी और बिकी 18000 रुपये प्रति एकड के हिसाब से। यानि कि किसान को 4700 रुपये प्रति एकड का नुकसान हुआ है।



अगर धान की बात की जाए तो किसान की प्रति एकड लागत 27265 रुपए आती है और आमदनी 25000 रुपए प्रति एकड होती है। चेयरमैन साहब, ऐसे कैसे चलेगा? हमने कभी प्रयास नहीं किए कि उनको अच्छे दाम मिले। चेयरमैन सर, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में नहीं हैं, वे कुछ करोड रुपये सोनिया गांधी जी से माफ करवा कर ले आए और सोनिया गांधी जी के कंधे पर हल रख कर कह देते हैं कि सोनिया गांधी किसानों की सबसे बड़ी हितैशी है। बेचारी सोनिया को क्या पता कि कनक क्या होती है, चने क्या होते हैं। उनको तो यह पता है कि यह आटा है, यह कनक का है और यह चने का है। तो ऐसे में किसानों का भला नहीं हो सकता। अगर सरकार सही मायने में किसानों का भला चाहती है तो यह जो खाद की कालाबाजरी है पहले इसको बंद करना होगा। यह जो बीत के कटटे टाईम पर नहीं मिलते हैं उनको पूरा करना होगा। दूसरे जो सिंचाई के पानी की बात यहां पर आई मैं उस बारे में कहना चाहूंगा। अब विनोद भार्मा जी सदन में बैठे हुए नहीं हैं वे कह रहे थे कि एस वाई एल का पानी हमारी पार्टी लाई है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर एस वाई एल नहर का पानी हरियाणा में कोई लाएगा तो चौधरी देवी लाल जी के पद चिन्हों पर चलते हुए चौधरी औम प्रकाश चौटाला जी ही लाएंगे यह कांग्रेस के बस की बात नहीं है। मैं तो यह कहता हूँ कि कांग्रेस के लोगों ने सिर्फ एस वाई एल कैनल के नाम पर एक विवाद खड़ा कर दिया है। इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। इनकी सरकार के वक्त के चार साल के अभिभाषणों को मैं पढ़

रहा हूँ। आखिरी साल मे भायद इस सरकार का एक और अभिभाषण आएगा। उसके बाद आएगा कि नहीं आएगा। (विघ्न)

**श्री नरे । कुमार प्रधान:** चेयरमैन सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैं आपके माध्यम से अपने साथी से जानना चाहता हूँ कि ये जो इतना इतरा कर किसानों की बात कर रहे हैं क्या ये वही लोग नहीं हैं जिन्होंने किसानों से वायदे किए थे कि जब भी औम प्रका । चौटाला की सरकार आएगी तो न मीटर रीडर होगा और न ही मीटर होंगे? जब इनकी सरकार आई तो किसानों ने इनको इनका वायदा याद करवाया तो इन हत्यारों ने बिजली बिल माफ करने की बजाय किसानों का भला करने की बजाय, उन पर गोलियों की बौछार करवा दी थी। 'वाह रे चौटाला तेरा कानून, पानी महंगा सस्ता खून'। आज ये किस मुहं से यहां पर किसानों के भले की बात कर रहे हैं। आज इनसे भार्म भी भार्मा रही है। ये यहां पर बोलते हुए सोनिया जी तक पहुंच गए। छोटा मुहं बड़ी बात करते हैं। जिस सोनिया गांधी ने 60000 करोड रुपए का किसानों का कर्जा माफ करवाया उसके उपर ये कटाक्ष कर रहे हैं। चेयरमैन साहब, इनके लिए बड़े भार्म की बात है। पता नहीं किस मुहं से ये बात कर रहे हैं, कौन से गांग जल मे ये मुहं धोकर आते हैं? औम प्रका । चौटाला जी ने चुनाव जीतने के लिए तीन तीन साल के बच्चों पर महम के अंदर गोलियां चलवा दी थी लेकिन आज ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं। आज अखबारों मे कई कई पेजों पर जन आक्रो । यात्रा के बारे मे इन्होंने

विज्ञापन दे रखे है। क्या ये उस जन आक्रोश को भूल गए जब इनकी सरकार के वक्त बहादुरगढ के अंदर पांच पांच साल की बच्चियों का रेप कर उनको कुचल दिया जाता था और उनकी हत्या कर दी जाती थी? वाहवाही लूटने के लिए यह कह कर कि हमने हत्यारो को पकड़ा है, राह चलते पागल कुत्तो पर मुकदमे बनवा दिए जाते थे लेकिन आज ये किसान की बात कर रहे है, जन आक्रोश की बात कर रहे है। क्या लोग यह भूल गए कि इनकी सरकार के वक्त मे दुलीना के अंदर चार चार हरिजन के बच्चो को जिंदा जलवा दिया गया था तब जन आक्रोश करने वाले कहां गए थे? क्या हरियाणा के लोग उस बात को भूल जाएं? आज किस मुंह से ये इतरा रहे है। बड़े दुख की बात है भार्म की बात है। (विघ्न)

**डा० सु गील इन्दौरा:** चेयरमैन साहब, क्या प्वायंट आफ आर्डर इतना लम्बा होता है? (विघ्न)

**श्री रामफल चिडाना:** चेयरमैन साहब, आप मेरी बात सुनें।

**श्री सभापति:** चिडाना साहब, आप बैठिए क्योंकि आपके नेता अपनी बात कहने लग रहे है डा० साहब, आप अपनी बात पूरी करिए।

**डा० सु गील इन्दौरा:** सभापति महोदय, अगर प्वायंट आफ आर्डर इतना ही लम्बा होगा तो मुझे ऐतराज नहीं है, मुझे

दिवकत नही है। आप मेरे से पहले उनको भाषण दिलवा दिजिए। प्वायंट आफ आर्डर तो केवल क्लैरिफिके इन के लिए होता है। सरकार मे चमचो की कमी नही होती है और चमचो का इलाज मेरे पास नही है। (विघ्न)

**श्री सभापति:** वे आपके लिए कुछ नही कह रहे है।

**डा० सु गील इन्दौरा:** सभापति महोदय, वे मेरे लिए तो नही कह रहे है लेकिन जिस किसी के लिए भी वे कह रहे है उससे एक प्रकार की झलक तो मिलती ही है। सर मै यह कह रहा था कि यह बात हकीकत है और सारा दे । इस बात को जानता भी है कि अगर कोई किसान के हित की बात करता था तो उसका नाम चौधरी देवी लाल ही है। अगर यह सच नही है तो आप बताओ। चौधरी देवी लाल जी ने हमे गा किसानो के लिए लडाई लडी। किसानो की बहुत सी स्कीमज चौधरी देवी लाल जी ने चलाई । चाहे ओलावृष्टी का मुआवजा देने की बात हो, चाहे और कोई बात हो, चौधरी देवी लाल जी ने ही किसानो के लिए यह स्कीम भुरु करवाई। इन्होने बुढापा पैं इन 500 रुपये करने की बात कही थी लेकिन एक अठन्नी भी नही बढाई। सर, मै यह कह रहा था कि एस वाई एल कैनाल हरियाणा प्रदे । के लिए जीवन रेखा है। उसका पानी लाना हर सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। जहां तक मेरी जानकारी है कि एस वाई एल कैनाल के निर्माण का कोई मामला आ भी कोर्ट मे लंबित नही है। ये चौधरी औम प्रका । चौटाला जी के प्रयास ही थे कि वर्ष 2002

में कोर्ट से यह निर्णय हुआ कि एक साल के अंदर पंजाब सरकार यह नहर बनवाएगी और अगर एक साल के अंदर पंजाब सरकार यह नहर नहीं बनवा सकती तो केन्द्रीय सरकार किसी केन्द्रीय एजेंसी के माध्यम से यह नहर बनवाएगी। अगर निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा फिर पानी तो आ ही जाएगा। सभापति महोदय, मैं इस बात को नहीं कहता। 19 दिसम्बर, 1991 को तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल जी ने हरियाणा विधान सभा में खुलकर स्वीकार किया था कि एस वाई एल कैनल पर अगर सबसे ज्यादा काम हुआ है तो वह चौधरी देवी लाल जी की सरकार के समय में हुआ है। उन्होंने यह भी कहा था कि मेरी चौधरी देवी लाल जी से कोई दोस्ती नहीं है कि मैं दोस्ती में यह कह रहा हूँ। चौधरी बंसी लाल जी की एक आदत थी कि वे सही बात को सही बात कहते थे इसलिए उन्होंने कहा था कि एस वाई एल कैनल पर अगर सबसे ज्यादा काम हुआ है तो वह चौधरी देवी लाल जी के टाइम में ही हुआ था। एस वाई एल कैनल की अगर पैरवी हुई है तो वह औम प्रकाश चौटाला जी के टाइम में हुई है। कांग्रेस के लोग सिर्फ और सिर्फ विवाद पैदा करने का ही काम करते हैं।

**Shri Tajender Pal Singh Mann:** Chairman Sir, I have a point of order. यह जो देवी लाल जी वाली बात कही है, यह गलत है। मैं भी उस समय सदन का सदस्य था लेकिन उस समय चौधरी बंसी लाल जी ने यह नहीं कहा था कि देवी लाल जी के समय में इस बारे में कुछ हुआ था। बंसी लाल जी उन दिनों कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। उस समय उन्होंने सारे पंचों को, सरपंचों

को बैंकस मे ले जाकर नहर का कंस्ट्रक्शन दिखाया था and which was almost 90% completed. Indoraji must make this correction in his record. यह रिकार्ड की बात है।

**डा० सु गील इन्दौरा:** सर, यह भी रिकार्ड की बात है जो मैं बता रहा हूँ।

**शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता):** जो मान साहब कह रहे हैं यह भी रिकार्ड की बात है।

**डा० सु गील इन्दौरा:** आप रिकार्ड निकालकर देख लें यदि मेरी बात सच नहीं होगी तो मैं इनकी बात मान लूँगा। यह हकीकत है कि पैरवी की है तो औम प्रकाश चौटाला साहब ने की है। देश के लोग और प्रदेश के लोग इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस ने तो सिर्फ विवाद पैदा करने का काम किया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि हांसी-बुटाना लिंक चैनल बनवाकर विवाद पैदा कर दिया। पानी का समान बंटवारा ही करना था। यह बात तो सारा प्रदेश कहता है, कौन इसके लिए मना करता है लेकिन नहर बनाकर प्रदेश का 500-700 करोड़ रुपये बेफिजूल खर्च कर दिया गया है। उस समय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी कहाँ गए थे? चाहिए तो यह था कि दूसरे राज्यों की सरकारों के साथ बैठक करके पहले उस मामले को सुलझाते कि हमने पानी लेना है। (विधन)

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): चेयरमेन साहब, इन्दौरा जी पहले यह बताए कि ये बी एम एल हांसी बुटाना के हक में है या खिलाफ है? इनके नेता जनआको 1 यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने यह कहा कि यदि बी एम एल हांसी बुटाना लिंक नहर बन जाती है तो हरियाणा में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। ये इस प्रकार की भाशा का इस्तेमाल करते हैं खुद पीछे होकर बादल को आगे कर रखा है और पीछे लोकदल के ये लोग हैं। ये नहीं चाहते कि जो हरियाणा की असली जीवन रेखा है जिसके बनने से 16 जिलों को लाभ होगा, वह बने। यह आज उसकी निंदा कर रहे हैं। इनको थोड़ी बहुत भार्म आनी चाहिए। इनको प्रदेश के हित की कोई चिंता नहीं है।

डा० सु गील इन्दौरा: हम पूरी चिंता करेंगे।

**Mr Chairperson:** No running commentaries, please.

कैप्टन अजय सिंह यादव: बी एम एल हांसी बुटाना लिंक नहर हरियाणा की असली जीवन रेखा है जिसके बनने से 16 जिलों को लाभ होगा। इस नहर का बनना निहायत जरूरी था। हमने अपने इलैक्शन मैनीफैस्टो में भी कहा था कि हम पानी का समान बंटवारा करेंगे।

**Mr. Chairperson:** No running commentaries, please.

कैप्टन अजय सिंह यादव: सभापति महोदय, उन्होंने कोई भी ऐसी कार्यवाही नहीं की जिससे पानी का समान बंटवारा

हो सके। नारनौल में पीने के पानी की बहुत कमी है। रिवाड़ी, फरीदाबाद और मेवात के इलाके में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं इन्होंने उसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इन्होंने उस समस्या के हल के लिए कुछ करने की बजाय लिटिगेशन डाली जिसके परिणामस्वरूप ये हाईकोर्ट में भी आँधे मुहं पड़ गए और सुप्रीमकोर्ट में भी आँधे मुहं पड़ेंगे। (विघ्न) नहर तो बनेगी ही और पानी का समान बंटवारा भी होगा।

**डा० सु गील इन्दौरा:** मैं खुले भावों में एक बात कहना चाहता हूँ कि पानी के समान बंटवारे के हक में सारा प्रदेश है। हर आदमी इसके हक में है लेकिन पानी का समान बंटवारा करे तो सही। ये लोग बंटवारा करने की बजाय विवाद पैदा करते हैं। मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी कहां गए थे जब बैठकें हो रही थीं। पहली बैठक में ही भाखड़ा को पेंक्चर करने की परमिशन क्यों नहीं ली। बजाय उसके कोर्ट में कहते हैं कि हमें तो पीने का पानी दे दो हम लिफ्ट उठा लेंगे। (विघ्न) यह हाल है सरकार का जो कोर्ट में जाकर कहती है कि हम पम्प लगाकर लिफ्ट से पानी उठा लेंगे। सभापति महोदय, अगर सरकार अच्छे कार्य करेगी तो मैं कहता हूँ कि मैं उसका समर्थन करूंगा। लेकिन ये कुछ करके तो दिखायें। हाईकोर्ट में मामले में सरकार एक प्रस्ताव लेकर आई थी अगर उसमें हमने समर्थन नहीं किया हो तो बताओ। हमने उस प्रस्ताव का खुले दिल से समर्थन किया था। सरकार कोई भी प्रस्ताव लेकर आये मैं कहना हूँ कि पार्टी की तरफ से दावा कर



रहा हूं कि अगर एस वाई एल बनाने की बात है तो चलो मेरे साथ सारे विधायक चलो हम कार सेवा करने के लिए भी तैयार है। लेकिन सरकार विवाद पैदा करने के लिए अगर यह काम करती है तो हम उसे कैसे बर्दा त करेंगे। फिर ये कहते है कि जनआक्रो । रैली मे कहा है। यह बात तो भायद पहले कभी कही हो। लोगों मे इस बात का आक्रो । है। जब चुनाव मे ये लोग जाएंगे तब पता चलेगा कि आक्रो । हमारे प्रति है या सरकार के प्रति। यह जन आक्रो । रैली लोगों की मांग थी। लोग अजय सिंह चौटाला जी के पास गये और कहा कि इस सरकार ने हमारी बहुत बर्बादी कर दी है प्रदे । की बहुत बर्बादी कर दी है। इस सरकार ने बुरा हाल कर दिया है, न कानून व्यवस्था है न कोई और चीज है इसलिए इस सरकार से बचाओ और लोगों को साथ लेकर चलो।

**श्री विनोद कुमार भार्मा:** सभापति महोदय, माननीय इंदौरा जी जन आक्रो । का पता करना चाहते है किसके खिलाफ है तो मै इनको खुला न्यौता देता हूं कि ये आये और आकर अभी चुनाव लड लें। दूर तक जाने की क्या जरूरत है हम इंतजार करने को तैयार नही है। ये कल आ जायें भेजो अपने नेता को मेरे खिलाफ चुनाव लउ लें, मै तैयार हूं।

**डा० सु गील इंदौरा:** सभापति महोदय, चुनाव तो आएंगे।

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला:** सभापति महोदय, भार्मा जी ने जो आफ़र दी है इससे फ़ेयर आफ़र और क्या हो सकता है। ये चौटाला जी को कहे कि वे इस्तीफ़ा दें। ( गोर एवं व्यवधान)

**श्री सभापति:** डा सीताराम जी, आप किस की इजाजत से बोल रहे है। Dr. Sita Ram Ji, no running commentary, first you should seek permission from the chair and then speak. Dr. Indora Ji, continue your speech.

**डा.0 सु गील इंदौरा:** सभापति महोदय, ये चुनाव तो आने वाले ही है, कांग्रेस के लोगों को पता चल जायेगा कि उनकी क्या हस्ती है। जब जनता इनके पीछे होगी तो ये लोग भागते नहर आयेंगे।

**श्री सभापति:** डा0 इंदौरा जी, आप पांच मिनट मे अपनी स्पीच खत्म किजिए।

**डा0 सु गील इंदौरा:** सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी जिस स्टेज पर जाते थे एक बात ही कहते थे कि अगले तीन साल मे हरियाणा प्रदे 1 को पूरी बिजली दे दूंगा। आज हालात क्या है। क्या मुख्यमंत्री जी बतायेंगे कि आज प्रदे 1 मे बिजली के क्या हालात है?

**श्री सभापति:** डाक्टर साहब, आप अपनी सुजै 1 न दीजिए और पांच मिनट मे अपनी स्पीच को कन्कलूड कीजिए।

**डा० सु लिल इंदौरा:** सभापति महोदय, मैं भूमिका बांधता हूँ, उससे पहले ही आप मेरी बात को काट देते हैं तब मेरा दिमाग कहीं और चला जाता है। हमारी सरकार पर यह लांछन लगाया गया है कि पिछली सरकारों ने बिजली के मामले में कुछ नहीं किया। हकीकत यह है कि यमुनानगर का जो प्लांट अभी सरकार ने भुंरु किया है उसकी भुंरुआत चौधरी और प्रकाश चौटाला जी ने की थी। इसका श्रेय ये ले लें हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हरियाणा प्रदेश को बिजली तो दें। उसका श्रेय इन लोगों ने लेने की कोशिश की और फायदा बड़े घराने को भी पहुंचाने का काम किया। (विधन) इन्होंने उसका श्रेय लेने का काम किया। (विधन)

**Mr. Chairperson:** No running commentary. let him complete डा० साहब, आपके पांच मिनट बाकी हैं आप अपने सुझाव दीजिए और अपनी स्पीच को कन्क्लूड कीजिए।

**डा सु लिल इंदौरा:** सभापति महोदय, अगर प्रदेश की बात मुझे कहने की इजाजत नहीं दी जाती है तो मैं बैठ जाता हूँ। मैं सुझाव ही दे रहा हूँ, सर। अगर आप मुझे इजाजत नहीं देते तो जब आप कहेंगे मैं एक सैकेण्ड में उसी समय बैठ जाऊंगा। I will not take even a single second और मैं बैठ जाऊंगा।

**Mr. Chairperson:** Indora Ji, don't waste your time, please give your suggestions.

**डा० सु गील इंदौरा:** सभापति महोदय, अगर आप यहां पर हमें बोलने नहीं देंगे तो हम प्रदे 1 की जनता के सामने जाकर बोलेंगे। मैं बिजली की ही बात कह रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब वह नहीं कहते। सरकार को आज बने हुए कितने साल हो गये, चार साल हो गये हैं। जब सरकार बनी तो मुख्यमंत्री जी हर स्टेज से कहते थे कि बिजली दे दूंगा, बिजली दे दूंगा। जो लाईन लोसिज है अगर उसको आप देखें तो कई फीडर्स ऐसे हैं जिनमें लाईन लोसिज 98 फीसदी से ज्यादा है। ये आंकड़े इनकी रिपोर्ट के मुताबिक हैं। 14 फीडर्स ऐसे हैं जिनमें 90 फीसदी लाईन लोसिज है। 48 फीडर्स ऐसे हैं जिनमें 70 से 90 फीसदी लाईन लोसिज है। बिजली मंत्री जी यहां पर बैठे हैं और ध्यान से सुन रहे हैं कि कायदे कानून के हिसाब से 25 परसेंट से ज्यादा लाईन लोसिज होना ठीक नहीं है। 280 फीडर्स ऐसे हैं जिनमें 50 फीसदी लाईन लोसिज है। ये लाईन लोसिज क्यों है, ये लाईन लोसिज इसलिए है क्योंकि कृषि के लिए बिजली मिलती नहीं और लाईन लोसिज का सारा बोझ बिना मीटर के जो कनेक्शन है, उन पर डाल दिया जाता है। ये लाईन लोसिज कृषि वालों के नहीं है बल्कि यह मिली भगत से होता है। अधिकारी बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिलकर चोरी करवाते हैं। सभापति महोदय, इस चोरी को बंद करवाओ। ये लाईन लोसिज किसान पर डाल देते हैं कि कृषि में खपत हो गई। बेचारा किसान वैसे ही मारा जाता है और आंकड़े आ जाते हैं। आंकड़ों में लिख दिया जाता है कि कृषि क्षेत्र में इतनी बिजली दी गई। हम सवाल पूछते हैं कि कितनी

बिजली दी गई, कहा जाता है कि इतनी बिजली दी गई जबकि मिला कुछ नहीं और सरकार की वाह वाह और बल्ले बल्ले हो जाती है। किसान बेचारा रोता रहता है और इधर ये लोग पैसे बनाते रहते हैं, ठगी करते रहते हैं। सभापति महोदय, इस चीज को रुकावाइये। बिजली के लाईन लोसिज कम हो, ऐसे प्रबंध किए जाए। बिजली के रेट नहीं बढ़ने चाहिए। बिजली महंगी होगी तो किसान की उत्पादन लागत बढ़ेगी, उद्योगों की लागत बढ़ेगी और हर चीज की लागत बढ़ेगी। सस्ती बिजली पैदा करने के लिए हमारी सरकार को कोशिश करनी चाहिए। सभापति महोदय, ये स्टेजों पर जाकर झुठे वायदे करते हैं कि बिजली के चार प्लांट लगा दिए। खेदड का प्लांट लगा दिया, झाडली का प्लांट लगा दिया। झाडली के प्लांट में दिल्ली का डिस्प्यूट है जो कभी भी सुलझ नहीं सकता। सभापति महोदय, मैं एक दिन झाडली प्लांट के बारे में अखबार में पढ़ रहा था कि दिल्ली वालों ने कह दिया कि हम इस प्लांट के लिए पैसा नहीं देंगे। सभापति महोदय, वे पैसा नहीं देंगे तो ये प्लांट कैसे पूरा होगा। ये 2011 की बात कहते हैं, 2011 में इनको कौन आने देगा।

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला:** अध्यक्ष महोदय, मैं क्लैरीफिकेशन करना चाहता हूँ। वैसे तो बाकी जो बात है वो ये कह सकते हैं। झाडली के दिल्ली विवाद की बात इनहोंने की तो मैं सदन में कहना चाहता हूँ कि अगर दिल्ली बिजली नहीं लेगा तो 750 मैगावाट जो उनका हिस्सा है वह भी हम रख लेंगे, इसमें हमें

कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हम पूरा पैसा देंगे और सरकार के पास पूरा पैसा है।

**श्री सभापति:** इन्दौरा जी, आप 3 मिनट में कन्कलूड करें

**डा० सु गील इन्दौरा:** सभापति महोदय, अभी तो मेरे पास सरकार के बहुत मुद्दे हैं अगर सब मुद्दों को गिनाने लगूं तो सारी रात हो जाएगी और इसके लिए हाउस की सीटिंग को एक्सटेंड करना पड़ेगी तभी बात बनेगी। ( गोर एवं व्यवधान) सभापति महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। मेरा सुझाव बिजली के मामले में है। बिजली मंत्री जी बैठे हैं ये देखें कि आज बिजली की उत्पादन क्षमता कितनी है। आज हमारे बहुत सु यूनिट बन्द पड़े हुए हैं। बिजली की उत्पादन क्षमता क्या है और उस उत्पादन क्षमता के अनुरूप हम बिजली पैदा कर रहे हैं या नहीं। अगर उसी हिसाब से बिजली पैदा कर ले तो प्रदेश के लोगों को पूरी बिजली मिल सकती है। कई बार तो हालात बहुत खराब हो जाते हैं।

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला:** सभापति महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। माननीय सदस्य को अपनी बात कहने का अधिकार है और वे कह भी रहे हैं। मैं आपकी अनुमति से सदन को बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रान्त देश में अकेला ऐसा प्रान्त है जिसने वर्ष 2008 से शुरू करके वर्ष 2012 तक बिजली का एक

नया कारखाना बनाने का निर्णय लिया है। हम हरियाणा प्रदेश के किसान, गरीब, व्यापारी और मजदूर को बिजली देंगे। व्यापारी को बिजली देने में इनको ऐतराज हो सकता है लेकिन हमें कोई ऐतराज नहीं है। व्यापारी और दुकानदार भी हरियाणा प्रान्त के हिस्से हैं। हम हर व्यक्ति को बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बिजली का 600 मैगावाट का एक कारखाना यमुनानगर में चालू हो गया है। इस साल राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, खेदड जिला हिसार में चालू हो जायेगा। मैं माननीय सदस्य को आश्चर्य करना चाहता हूँ कि इस प्लांट से इस साल में 1200 मैगावाट बिजली हरियाणा के गरीब, व्यापारी, किसान और दुकानदार को मिलेगी। इसके बाद हमे झाडली के पावर प्लांट से बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। माननीय सदस्य को भ्रम है कि इस पावर प्लांट पर कोई विवाद है। मैं इनको बताना चाहूँगा कि इस पावर प्लांट पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। इस पावर प्लांट के दोनो युनिटों से कम 1: जुलाई, 2010 और दिसम्बर 2010 में हरियाणा के लोगों को बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर वर्ष 2011 में महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट आयेगा और वर्ष 2012 में जो निजी क्षेत्र की और बिजली है वह भी आ जायेगी। इस प्रकार से वर्ष 2012 तक हरियाणा में 6 हजार मैगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन शुरू हो जायेगा। मुख्यमंत्री जी ने एक समय कहा था कि हम तीन से चार हजार यूनिट अतिरिक्त बिजली पैदा करेंगे लेकिन वायदे से बढ़कर आने वाले समय में उनके नेतृत्व में 6 हजार मैगावाट बिजली के उत्पादन का लक्ष्य 24 हजार करोड़

रुपये से अधिक की लागत से पूरा करने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। 600 मैगावाट बिजली पैदा हो गई है और 1200 मैगावाट बिजली हम इस साल में पैदा करके दिखाएंगे। ये हमारा प्रयास है। जहां तक हमारे बंद पड़े यूनिटों का सवाल है, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमारे यूनिट्स का जो पी एल एफ इस साल आया है जब से पावर जैनरेटिंग कम्पनी आस्तित्व में आई अर्थात् जब से हरियाणा में बिजली के कारखाने लगे हैं तब से लेकर आज तक का सबसे ज्यादा है। चेयरमैन साहब हमारे कई यूनिट ऐसे हैं जो 103 और 104 परसेंट पी एल एफ के ऊपर चले। चेयरमैन सर, इस बात के लिए आपको मुझे और हरियाणा को अढ़ाई करोड़ लोगों को फ्रस्ट्र होना चाहिए कि वे पावर प्लांट जो कभी 60 से 65 पी एल एफ से ज्यादा नहीं गये आज वे 78 से 79 परसेंट एवरेज पी एल एफ तक चलते हैं और कई ऐसे प्लांट जो कि 101, 102, 104 परसेंट पी एल एफ तक चले हैं। यह अपने आप में एक नया रिकार्ड है और आज तक ऐसा किसी अन्य सरकार के समय में नहीं हुआ। सभापति महोदय, मैं केवल जानकारी के आधार पर सम्मानित सदस्य को सूचित करना चाहता हूँ।

**डा सु गील इन्दौरा:** सभापति महोदय, माननीय बिजली मंत्री जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ लेकिन इसके साथ ही इनसे यह भी बताना चाहिए कि अगर हरियाणा में इतनी बिजली है तो फिर वह कहां



गई और हरियाणा के लोग आज अंधेर `मे क्यों बैठे है? ये यह क्यो नही बता पा रहे है?

**श्री सभापति:** इन्दौरा जी, प्रदेश मे बिजली की कमी को दूर करने के लिए आप अपने सजै ांज दे। आप इनको बताइए कि ऐसी हालत मे इनको क्या करना चाहिए।

**डा० सु गील इन्दौरा:** सभापति महोदय, मै अपने सुझाव भी दे रहा हूं। जैसे मैने लाईन लोसिज के बारे मे बताया है कि यह अधिकारियो की मिलीभगत से हो रहा है।

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला:** सभापति महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय सदस्य हो बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार के कार्यकाल मे 7 प्रति ात लाईन लोसिज उत्तरी हरियाणा मे और इसी प्रकार से तकरीबन 5 प्रति ात लाईन लोसिज दक्षिणी हरियाणा मे कम हुए है।

**श्री सभापति:** आनॅरेबल मिनिस्टर साहब, माननीय सदस्य द्वारा जो भी प्वायंटस उठोय जा रहे है उन्हे आप नोट कर लीजिए और उसके बाद आप कोई स्टेटमेंट देना चाहे तो आप दे दें। Mr Indora, now you please conclude.

**डा० सु गील इन्दौरा:** सभापति महोदय, मै एक बात और कहना चाहता हूं। सरकार कहती है कि बिजली पानी के मुददे के अलावा कई और मुददे है और हम आने वाले चुनावो मे विकास के नाम पर वोट मांगेगे। हरियाणा न्यूज पर एक गीत आता है कि

तने राम की भुं। ये राम की भूं दिखाते दिखाते सडके दिखाते है और अगर आप हरियाणा सरकार की वर्ष 2008 और 2009 का कलेण्डर देखे तो उसमे तीन चीजें बडी प्राथमिकता के आधार पर दिखाई है। कैलेण्डर मे सरकार का विजन होत है कि सरकार दिखाना चाहती है कि हम क्या करना चाहते है। उसमे एक तो धुआ उगलती हुई चिमनी दिखाई गई है, एक बडी सी नहर दिखाई गई है और सडके दिखाई गई है। अगर विकास की बात देखनी है तो आप मेरे क्षेत्र मे चले। मै पिछले चार साल से लगातार कह रहा हूं कि जाखन से कुलां तक सडक बना दी जाये। उपरोक्त सडक बनाने के लिए मुझे हर बार आ वासन दे दिया जाता है लेकिन वह सडक आज तक नही बनवाई गई है। मै सरकार पर यह भी आरोप लगाना चाहूंगा कि सरकार विधान सभा मे माननीय सदस्यो को दिये गये आ वा नो की कोई परवाह नही करती। हमे दिये गये आस्वा नो को कभी पूरा नही किया गया। आज तक हमारे पास कोई चिटठी नही आई। मंत्री जी की तरफ से एक बात कह दी जाती है कि मिल लेना और जब हम मिलने जाते है तो बताया जाता है कि मंत्री जी दौरे पर गये है। हम अपने आ वासनो पर कार्यवाही करवाने के लिए कब तक मंत्रियो के पीछे पीछे घूम सकते है। अगर विकास की बात की जाये तो मंगाला से टीटू खेडा तक की सडक बना दी जाये, सिरसा से ऐलनाबाद की सडक बना दी जाए जो कि आज तक नही बनी। मुझे यह बताया जाये कि कहां पर विकास हुआ। एक फलडी नहर बनी के पैरेलल बन कर पूर तरह से तैयार है लेकिन

उसमे अभी तक पानी नहीं छोडा गया है। इससे बडी चिंता की बात और क्या हो सकती ह। चेयरमैन साहब, सरकार कहती है कि प्रदे 1 मे सौहार्दपूर्ण वातावरण है व्यापारी काम कर रहे है लेकिन हालात यह है कि व्यापारियो पर तो सरेआम गोली मार दी जाती है।

**श्री सभापति:** इन्दौरा जी, आपका समय समाप्त हो गया है। डा0 सीता राम जी अब आप बोलिए।

**डा0 सीता राम:** सभापति महोदय, मै आज नहीं बोल पाउंगा। इसलिए इन्दौरा साहब को ही बोलने दीजीए।

**डा सु णील इंदौरा:** सभापति महोदय, मै बोल रहा हूं इसलिए मुझे ही कुछ समय और दे दीजिए। ग्रामीण राजगार गारंटी योजना की बात की जा रही है लेकिन कही भी लोगो को कम नहीं दिया जा रहा। भारत निर्माण, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के इतने बडे बडे होर्डिंगज लगाये जाते है लेकिन हो तो कुछ भी नहीं रहा है। लोगो के कार्ड तक पुरे नहीं बने। कही कही पर तो काम तक पुरा नहीं होता। इसी प्रकार से सरकार स्वच्छता की बात करती है। स्वच्छता के बारे मे सरकार बताये कि सिरसा वालो को आज तक ट्राफी नहीं मिली। जब हिसार मे महामहिम राष्ट्रपति जी आई थी तो सिरसा वालो को वहा पर ठहरने के लिए स्थान तक नहीं मिला था। अगर आपको स्वच्छता देखनी है

तो फतेहाबाद की कालोनी के जो सरकारी मकान है उनके सामने सुबह 6 बजे देखो की स्वच्छता क्या चीज है?

**श्री सभापति:** आप चेयर को एड्रैस कीजिए।

**डा० सु गील इन्दौरा:** सभापति महोदय, पीने के पानी की और टंकियों की बात की जा रही है कि अनुसूचित जाति के लोगों को पीने के पानी का मुफ्त कनेक्शन और पानी की टंकी दी जाती है लेकिन यह भी गलत है क्योंकि दो दो घरों के लिए एक ही पानी की टंकी लगाई जा रही है। अगर उनके टवायलटस की बात करें तो वे उपर रखे हुए होते हैं और उनकी चारदीवारी तक नहीं बनाई जाती। आंकड़े पूरे कर लिये जाते हैं कि एक एक घर में हमने स्वच्छता अभियान चलाया है हर बार एक ही बात कही दी जाती है कि सरकार ने 1600 करोड़ रुपये कि बिजलीके बिल माफ कर दिये। इसी प्रकार से किसानों के 71 हजार करोड़ रुपये के कर्जें माफ करने की बात की जाती है। बिजली के बिल माफ तो दूर किसी का एक पैसा भी माफ नहीं किया गया। मुझे एक किसान मिल गया मैंने उससे पूछा कि आपका कितना पैसा माफ हुआ है तो उसने कहा कि मेरा तो 5 पैसे भी माफ नहीं हुए। कहां की सरकार, सरकार बताये तो सही सरकार क्या कर रही है। आज सड़को की बात की जा रही है, सड़के बिल्कुल टूटी पड़ी है। कानून व्यवस्था की बात की जा रही है लेकिन उसका भी बुरा हाल है। आपके सामने खरक में कुछ लोग मांग कर रहे थे लेकिन उन पर गोलियां चलवा दी। एक राजरानी थी उसको बिना बात के

मार दिया। लोकतंत्र में कैसे अपने अधिकारों की बात करने वाले को मार दिया जाता है?

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला:** सभापति महोदय, आपने डा इन्दौरा जी को दो बार एक्सटेंशन दे दी है लेकिन बहुत से सदस्य अब भी बाकी हैं, जो बोलना चाहते हैं। इसलिए आप उनके अधिकारों का भी ध्यान रखें।

**श्रीसभापति:** इंदौरा साहब, आप 45 मिनट बोल चुके हैं, आप कनक्ल्यूड कीजिए।

**डा सु गील इन्दौरा:** सभापति महोदय, मैं तो डेढ़ घंटा भी बोल सकता हूँ आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए मैं अपनी बात को खत्म कर लूँगा। आप से ज्यादा समय तो हमें माननीय अध्यक्ष महोदय जी दे दिया करते थे। आप तो पहली बार चेयर पर बैठे हैं आपको तो ज्यादा दरियादिल होना चाहिए। माननीय बिजली मंत्री जी से मेरा सवाल था कि बिजली के बिलों में पिछली बार का बिल जोड़ कर दे दिया जाता है और अब उसको ठीक करवाने के लिए जाओ तो उसमें भी सरकार का जवाब नहीं मिलता है। सरकार द्वारा हकीकत जानने की बजाय लीपापोती की जाती है। अगर इसी प्रकार से लीपापोती की जाएगी तो हरियाणा नम्बर एक नहीं बन सकता। अगर हरियाणा को नम्बर एक राज्य बनाना है तो उसके लिए मेहनत करनी होगी और मेहनत करना कांग्रेस वालों के बस की बात नहीं है। कांग्रेस वाले तो ड्राईंग रूम में बैठकर फोली

फोली खा सकते हैं ये जनता का क्या भला कर सकते हैं? मेहनत तो हम जैसे लोग कर सकते हैं।

**सभापति महोदय:** इंदोरा जी, आप खत्म करें। बहुत से मैम्बर्ज और भी बोलना चाहते हैं। अगर आप ही बोलते रहेंगे तो औरो को कैसे मौका मिलेगा?

**डा० सु ल इन्दौरा:** सभापति महोदय, मैं एक दो बात और कहना चाहता हूँ। एक तो मैं बी पी एल पर बोलना चाहता हूँ और दूसरा 100-100 गज के प्लाटो के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ।

**श्री सभापति:** ठीक है, अगर बी पी एल पर बोलना चाहते हो तो एक मिनट में बोल लो।

**डा० सु ल इन्दौरा:** सभापति महोदय, बी पी एल के मामले में और पीने के पानी के मामले में हालत यह है कि लोग हर रोज प्रदूषित कर रहे हैं। मेरे पास ऐसे गावों की लिस्ट है। (विधन) इन गावों में पीने के पानी की बड़ी भारी दिक्कत है। नेजिया खेडा गांव समाबार और चन्दकावास गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस लिस्ट में आने से रह गये हैं।

**श्री सभापति:** डा० साहब, आप इस बारे में सुझाव दे की क्या किया जाये।

**डा० सु गील इन्दौरा:** सभापति महोदय, मैं सुझाव दे रहा था कि जो सही ओर वाजिब लोग हैं वे बी पी एल की सूची में आने से रह गये हैं।

**श्री सभापति:** आप इस बारे में सुझाव दें कि सरकार क्या करे

**डा० सु गील इन्दौरा:** चेयरमैन साहब, वे लोग जो बी पी एल सूची में आने से वंचित रह गये हैं उनके नाम शामिल करने के लिए सरकार एक एजेंसी बनाए और जो लिस्ट बनी है उसकी जांच करवाए। हालांकि सरकार इस प्रकार की कार्यवाही चार बार कर चुकी है। चार बार कार्यवाही होने के बावजूद भी यह विवाद अभी तक बना हुआ है। सरकार कोई एजेंसी गठित करके इसका सर्वे करवाए जो जायज और पात्र लोग हैं उनको उनका हम मिलना चाहिए। जहां तक 100-100 गज के प्लॉट्स देने की बात है, वह एक ढकोसला मात्र है। सिर्फ गांवों की जमीन हड़पने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। सिर्फ पंचायतों की जमीनों पर ही ये प्लॉट क्यों दिए जा रहे हैं। अगर सरकार ऐसे प्लॉट्स देना ही चाहती है तो जमीन खरीद कर प्लॉट्स दें। सभापति महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जहां बी सीज कैटेगरी में ए और बी का वर्गीकरण है वहां पर तो कोई विवाद नहीं है लेकिन एस सीज और ए और बी का वर्गीकरण करके एक रोला मचा दिया और यह कह दिया कि इसमें कोर्ट का मसला आ गया है। सरकार ने ऐसा क्यों किया, दो भाईयों को आपस में

लडा दिया और एक विवाद खडा कर दिया। एस सीज की कैटेगरी बनी हुई थी और वह चल रही थी। (विध्न)

**श्री फूल चनद मुलाना:** सभापति महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। ये decision of the court पर बात कर रहे है। इनका यह कहना है कि सरकार ने ए और बी वर्ग का झगडा करवा दिया। Sir, on a point of order. मै यह कहना चाहता हूं कि this is the decision of the Court and not of the Government. सर, there can be no caste within the caste. How can he say that Government is doing all this? this is the wrong allegation and he should withdraw it.

**डा० सु गील इन्दौरा:** सभापति महोदय, अगर ऐसी बात है तो ए और बी कैटेगरीब भी संवैधानिका है। (विध्न)

**श्री सभापति:** डा साहब, आप सुझाव दीजिए कि इसमे क्या होना चाहिए?

**डा० सु गील इन्दौरा:** सर, मेरे विचार से यह होना चाहिए कि ए कैटेगरीज वालो को भी कैटेगरी के हिसाब से लाभ दिया जाना चाहिए।

**श्री सभापति:** इन्दौरा साहब, ठीक है, अब आप अपनी सीट पर बैठें। अब श्री अरजन सिंह जी बोलेंगे। (विध्न)

**डा० सु गील इन्दौरा:** सभापति महोदय, \*\*\*\*\*



**श्री सभापति:** इन्दौरा साहब, आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) अरजन सिंह जी, आप बोलें। (विघ्न) इन्दौरा जी आप बैठें। यह जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। Nothing to be recorded. (Interruptions) Indora Sahib, Please take your seat. Thank you very much. अरजन सिंह जी, अब आप बोलें।

**चौ० अरजन सिंह (छछरौली):** चेयरमैन साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। (विघ्न) चेयरमैन सर, सबसे पहले तो मैं माफी चाहूँगा कि उस दिन मैं भी उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ था जिनकी चर्चा हो रही थी। मेरा विवास कीजिए कि उस दिन जब महामहिम गवर्नर महोदय उठकर चले गये तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि सदन की कार्यवाही खत्म हो गई और अगले दिन सारा मामला डिस्कस होगा। उस दिन सारे केसारे सदस्य उठ लिये थे तो मैं यहाँ से उठ करी हुडडा साहब के पास रोहतक चला गया था। उस दिन सदन से जाने के लिए मैं सॉरी फील करता हूँ और उस दिन के श्रद्धांजलि प्रस्तावों के साथ मैं अपने आप को जोड़ता हूँ। मैं भी दिल की गहराईयों से दिवंगत आत्माओं के प्रति भाव प्रकट करता हूँ। अपने आप को चर्चा में जोड़ते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि चौधरी रणबीर सिंह जी बहुत ही महान और सादे इंसान थे। अगर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो हमें उनके पदनिन्हां पर चलना चाहिए और जो उनकी भावना थी उसकी हमें कद्र करनी चाहिए। सभापति महोदय, आज मैं न तो कांग्रेस के पक्ष में कुछ कहूँगा और न ही विपक्ष के बारे में कुछ कहूँगा। (विघ्न) जो सच लगेगा

उस पर सही बात कहूंगा ओर सही बात ही बताउंगा। (विघ्न) सभापति जी, जहां तक चौधरी देवी लाल जी की बात है, डा0 इंदौरा जी, मैं उनकी दिल से कद्र करता हूं। उन्होंने सरकार बनाने के लिए चाहे जो प्रोपोगेण्डा दिया हो लेकिन उनकी आत्मा के कोई झूठी और लूट खसोट की भावना नहीं थी। उनकी उसी भावना को देखकर लोगों ने उनको क्रेडिट दिया था और आगे उनके परिवार को भी क्रेडिट दिया था लेकिन उनके परिवार के लोगों ने जो किया उनको उसका नजीता मिल गया। चेयरमैन सर, अब जनता इतनी भोली नहीं रही। एक समय वह था जब लोग एक दूसरे के लिए जीते थे लेकिन अब लोग अपने लिए जीते हैं और अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए जीते हैं। वे अपने रास्ते पर रहते हैं कि हमें कहा फायदा हो सकता है। किसने लूटा, किसने खसोटा, किसने भला किया, हर आदमी आज अपने नफे नुकसान के साथ अटैचड है। इनदौरा साहब, पिछली सरकार का गुणगान कर रहे हैं मेरे ख्याल में यह उस समय सरकार में नहीं थे। अगर ये उस समय सरकार में होते तो उस सरकार को कुछ न कुछ सुझाव देते और उनको कुछ न कुछ समझाते लेकिन उस समय वे यहां पर नहीं थे और आज ये अपनी भडास निकाल रहे हैं। वे इनकी बात सुनते या न सुनते यह तो उनकी भावना थी लेकिन ये अच्छी सलाह देते उनको। इन्दौरा साहब यहां पर नहीं थे। जहां तक इन्होंने फसलो की बात कही कि जीरी कम रेट पर गई है। पिछली सरकार में व्यापारियों से पूछा जाता था और जो गवर्नमेंट के रेट होते थे उससे कम में बोली हो जाती थी। 100-100 रुपये प्रति

क्विंटल के कम रेट मिलते थे। चेयरमैन सर, एक एक किल्ले में 5-5 हजार रुपये का नुकसान इनके समय में होता था जो आज ये तुलना कर रहे हैं। आज ये कह रहे हैं कि 25000 रुपये की बिकनी चाहिए थी जबकि उस पर 18 हजार रुपये का खर्च हुआ है। ये बातें पिछली सरकार के वक्त में इनको क्यों याद नहीं आईं। जहां तक पानी की बात है, आज ये लोगों से जाकर पूछें। इस सरकार ने लोगों के घरों में 5-5 और 6-6 हजार रुपये की पानी की टंकी लगवा दी हैं। इनके समय में तो एक पैसा भी इस काम के लिए खर्च नहीं किया गया था। इन्होंने तो मिट्टी का दोना भी किसी को नहीं दिया था। यहां तक की जो मटके रखे हुए थे वे भी इन्होंने फुड़वा दिए थे। कभी मटका फोड़, बंटा फोड़, कभी सडक फोड़, मेरे कहने का मतलब है कि इन्होंने तोड़ने फोड़ने का ही काम किया है। इन्होंने कभी भी जोड़ने का काम नहीं किया। एक टाइम में पापुलर के रेट 550 से 600 रुपये क्विंटल तक चले गये थे और इनके समय में 150 रुपये प्रति क्विंटल तक लाकर किसानों की लुटाई हुई थी। लुटाई, किराए वाले के किराए को देकर, आढती को देकर, काटने वाले को देकर ओर जो खुंटे पीछे लगाकर ट्राली वाला ले जाता था सिर्फ वही बचते थे, इससे फालतू कुछ नहीं बचता था। आज मैं इस सरकार की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। आज वही पापुलर का रेट 800 रुपये तक जा रहा है। वही ट्राली जो 12000 में ली जाती थी आ 80000 से 90000 की लोग बेच रहे हैं। इनके वक्त में 50 और 60 हजार रुपये एक एक ट्राली में किसानों को

नुकसान हुआ था। गन्ने के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि जो ट्राली आज 10000 हजार रुपये में जा रही है इनके वक्त में वही ट्राली 4000, 4500 या 4600 रुपये में जाती थी। सभापति महोदय, जहाँ तक आज ये नहरों की बात करते हैं आज इनको नहर याद आ रही है। इस सरकार के आने से पहले साढ़े पाँच साल हरियाणा स्टेट में इनकी सरकार थी, उस वक्त इन्होंने नहरों के बारे में कुछ नहीं किया। तब क्या हरियाणा में पानी की जरूरत नहीं थी। तब चाहे पानी बादल ले जाए या धरती पी जाए। मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ। मैं तो उस बात के बारे में कह रहा हूँ जो बात आपने कही थी। जहाँ तक बिजली की बात है, इस सरकार ने जब इलैक्ट्रिक लाइन लडा था तो इनके किसी श्रमी आदमी ने इस बारे में कोई बात नहीं कही थी, कोई वायदा नहीं किया था। आपकी पार्टी ने तो यह कहा था कि जब तक हमारी सरकार नहीं आएगी तब तक किसी ने भी बिजली के बिल नहीं भरने हैं। तब तक किसी के पैसे नहीं देने हैं। चेयरमैन साहब, आज भी वही लोग धमकी देते हैं जिन्होंने किसी का ले कर देना नहीं है वर्ना और किसी में कोई आक्रोश नहीं है। पता नहीं ये किस का आक्रोश बता रहे हैं। आज एक एक गाँव में भांति ठै। आज ये सड़कों पर चलते हैं तो ये न तो किसी ट्रक वाले को न ही किसी ट्रक्टर वाले को आगे निकलने देते हैं। इनकी वजह से उन लोगों में आक्रोश है जिनको दो किलोमीटर जाना है उसकी बजाय 20-20 किलोमीटर दूर से घूम कर जाना पड रहा है। (विघ्न) सभापति महोदय, जहाँ तक बिजली की बात है, मुख्यमंत्री जी ने और इनकी

सरकार ने सबसे पहले बिजली के उपर ध्यान दिया है। सभापति महोदय, वोट लेने के लिए सभी इलैक्ट्रानों के समय में घोशणा करते हैं लेकिन इस सरकार ने ऐसी घोशणा नहीं की थी। मैं इनको यह कहना चाहता हूँ कि जो बिजली बन रही है वह देने के लिए ही बन रही हैं। अगर किसी के घर में धुंआ नहीं उठ रहा हो तो उस घर से रोटी की क्या उम्मीद करेंगे। जिस घर से धुंआ उठ रहा हो उससे उम्मीद होती है कि आधे घंटे में, एक घंटे में रोटी जरूर मिल जाएगी। आदमी सब्र तो करें इनको तो वह सब्र भी नहीं है। बिजली बन रही है और वही लोगों को मिलेगी। (विधन) चेयरमैन सर, मैं ईमानदारी से एक बात सदन में कहना चाहता हूँ कि आज लोग पापुलर लगा रहे हैं और पापुलर लगाने वालों में चर्चा हो रही है कि और वे उस बारे में जवाब भी दे रहे हैं। वे कहते हैं कि भाई पापुलर तो लगाने लग रहे हो, देख लो कहीं वे हटकर न आ जावें। इसका जवाब लोग देते हैं कि हमने उसको वोट ही नहीं देने तो वह कहां से आएगा। मतलब यह है कि ये लोग पापुलर लगाते हैं लेकिन उनमें यह भय अब भी बना रहता है कि कहीं बाद में ये लोग लौटकर सत्ता में आकर लूट खसौट करके न ले जाए। (विधन) चेयरमैन सर, मैं तो यह कहूंगा कि जिस नियत से यह सरकार चल रही है उसको देखते हुए हम तो यह कहेंगे कि परमात्मा इन्हें और मजबूती दे, ताकत दे (विधन) चेयरमैन सर, पिछली सरकार के समय में तो मेरे क्षेत्र में 50-60 टन का लोड भरकर गाड़ियों में ले जाते थे जिसकी वजह से सारी सड़कें टूट गयीं। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि सड़कों की जहां

तक बात है ओवर लोड की वजह से जो सड़के वहां पर टूट रही है उनकी तरफ भी सरकार ध्यान दें। चेयरमैन सर, बाकी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है राम राज्य है सब लोग खुश हैं क्योंकि यह बहुत बढ़िया सरकार है। मैं केवल आपका मुंह पर ही यह बात नहीं कह रहा हूँ बल्कि जो सच्चाई है वह आपको बता रहा हूँ। लोग यह बात अपने अंदर से बोल रहे हैं लोगों को पता है कि वह उसको भी याद करते हैं। चेयरमैन सर, अब लोग सब बातें जानते हैं। हर आदमी अपना दिमाग रखता है और हर आदमी की अपनी सोच है। चेयरमैन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का टाईम दिया।

**श्री रामफल चिडाना (बरोदा, अनुसूचित जाति):** चेयरमैन सर, आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का जो मौका दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ा है उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो किसान हितैशी, मजदूर हितैशी हो या कुछ भी ऐसा किया गया हो जो सराहनीय हो। चेयरमैन सर, मैं बताना चाहता हूँ कि पिछली जीरी का जब मौसम था तो भगवान की कृपा से बड़ी अच्छी फसल हुई थी लेकिन बीमारी बहुत ज्यादा लग जाने के कारण वह पकी पकायी फसल देखते देखते ही खराब होती चली गयी। सरकार ने क्या किया उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक जीरी की फसल खराब हो गई उसको मुआवजा देना तो दूर की बात है, नुकसान का सर्वे

तक नहीं करवाया गया, गिरदावरी तक नहीं करवायी गई। चेयरमैन सर, एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम किसान हितैशी हैं और दूसरी तरफ मुआवजा स्कीम होने के बावजूद भी किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। पहले लोग कहते थे कि हुडडा तेरे राज में जीरी गयी जहाज में और अब क्या हुआ, अब लोग कहते हैं कि हुडडा तेरे राज में जीरी गई ब्याज में। चेयरमैन सर, गोहाना तहसील में भी किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी थी। यह रिकार्ड की बात है।

**श्री फूल चन्द मुलाना:** चेयरमैन सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। सर, नारा यह था कि चौटाला तेरे राज में जीरी गई ब्याज में और पराली गयी लिहाज में। जबकि हमारी सरकार ने यह नारा इस प्रकार है हुडडा तेरे राज में जीरी गयी जहाज में, क्योंकि हमारी सरकार ने पैडी 1121 पूसा का एकसपोर्ट खुलवा दिया था, सर, मैं इनकी बात को सही कर रहा हूँ।

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला:** चेयरमैन सर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इस बार जो जीरी का भाव भायद किसान को इतना भाव कभी नहीं मिला। कांग्रेस की सरकार और चौधरी भुपेन्द्र सिंह हुडडा की इंटरवेंशन के चलते देना की सरकार ने पैडी 1121 पूसा को भी बासमती डिक्लेयर किया। यह अपने आप में बहुत अनूठी बात है। चेयरमैन सर, फिर भी किसी सुस्त आदमी ने अगर अपनी यह वैरायटी न बेची हो तो अलग बातें

है। 3300 रुपये पर पैडी 1121 पूसा बिकी है जबकि 1200 रुपये पर बासमती इनके समय में बिकी थी। इसलिए यह फर्क है।

**श्री रामफल चिडाना:** चेयरमैन सर, सौभाग्य से मैं भी किसान हूँ और मैंने भी जीरी लगा रखी थी इसलिए मुझे पता है। होता यह है कि यदि किसी बड़े खरीददार ने एक ढेरी की बोली 2700 रुपये लगा दी तो अगले दिन उसकी कुछ और बोली लग जाती है। कोई नियम नहीं है कोई कायदा कानून नहीं है। यदि एक किल्ले की जीरी पांच हजार पर रख दी जाए तो पांचो ढेरियो के अलग अलग रेट की बोली लगती है। बोली लगाने वालों को जीरी की कोई पहचान नहीं होती क्योंकि उनका पता नहीं कि किसान जीरी की फसल कैसे तैयार करता है। यदि एक किल्ले की जीरी की अलग अलग पांच ढेरी बना दी जाए तो एक ही बीज से पैदा की उन पांचो ढेरियो के रेट अलग अलग पांच ढेरी बना दी जाए तो एक ही बीज से पैदा की उन पांचो ढेरियो के रेट अलग अलग लगाए जाते हैं। एक दिन भाव कुछ होता है अगले दिन भाव कुछ होता है। कई कई दिन में किसान को अपनी जीरी बेचनी पड़ती है। आप कुछ कहेंगे, हम कुछ कहेंगे और सरकार कुछ भी कहे लेकिन सही बात तो लोग बताएंगे। लोगों ने सोचा कि जीरी रख लेते हैं मजबूरी थी। जो यह 1121 पूसा किस्म की बात करते हैं। 600 रुपये प्रति क्विंटल में भी उसका कोई खरीददार नहीं था। किसान की मजबूरी होती है। गेहूँ भी साथ बीजना पड़ता है। जब भाव मिलने की बात थी तो 800 रुपये एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी



जिससे किसान को कम रेट मिले। किसान ने क्या कसूर कर दिया था कि अपने घर में जीरी रख दी। रखनी इसलिए पड़ी क्योंकि कोई खरीदने वाला नहीं था।

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला:** चौधरी रामफल चिडाना जी, जिस ड्यूटी की बात आप कर रहे हैं भारत सरकार ने वह ड्यूटी वापिस ले ली है।

**श्री रामफल चिडाना:** चेरमैन साहब, वह तो बहुत बाद में वापस ली गई है। दलित बिरादरी की बात करते हैं। मैं दलित बिरादी से हूँ मुझे पता है कि क्या कुछ होता है। गरीब आदमियों के पास हम जाते हैं तो वे रोते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि पानी की टंकी दी है, टूटी दी है। पानी की टंकी से क्या होगा अगर वह खाली पड़ी रहे। खाने को उनके पास कुछ है नहीं यह ठीक है कि किसानों के लिए भाव बढ़ाया है लेकिन यह बताए कि गरीब आदमी के लिए गेहूँ का क्या प्रबन्ध किया है। क्या गरीब आदमी 11-12 रुपये किलो गेहूँ खरीद कर खा सकता है। हम इस हक में हैं कि किसान को ठीक रेट मिलना चाहिए लेकिन सच्चाई तो यह है कि गरीब आदमी को कोई लाभ नहीं मिलता है। प्लाटो की बात कही गई है। (विघ्न)

**श्री सभापति:** चिडाना साहब, आ इधर देखिये और बोलिये।

**श्री रामफल चिडाना:** चेयरमैन सर, बी पी एल कार्डों का 4-4 बार सर्वे हो रहा है और बहुत से लोगों के बी पी एल कार्ड बने हुए थे लेकिन अब उनके नाम काट दिये गये हैं। इसके अलावा गरीब आदमी को अपमानित करने का ओर क्या साधन होगा कि उसके घर के बाहर दीवार पर लिख दिया गया है कि बी पी एल परिवार। ऐसे में कोई व्यक्ति किसी के घर अपनी लडकी के रिश्ते के लिए जाएगा तो बाहर दरवाजे से देखकर ही लौट आएगा और कहेगा कि यह तो रजिस्टर्ड गरीब है, रजिस्टर्ड कंगाल है इसके घर कौन अपनी बेटी ब्याहेगा। वैसे भी यह कार्ड बनाए जा सकते थे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने गोहाना में और सोनीपत में जाते हैं और कहते हैं कि गोहाना मेरा, सोनीपत मेरा है और मैं गोहाना और सोनीपत का। सूचना के अधिकार के तहत हमने पता किया, हमारे एक वकील साथी ने पता किया। वह कागज मेरे पास है और आप चाहे तो यह कागज मैं सदन के पटल पर भी रख सकता हूँ। उन्होंने पता किया कि पुलिस के छह हजार जवानों की भर्ती हुई और उसमें सोनीपत जिले के ऐड्रेस पर मात्र तीन आदमी ही भर्ती हुए।

**चौ० जगबीर सिंह मलिक:** सभापति महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मेरे लायक दोस्त कह रहे हैं कि सिर्फ तीन आदमियों की सोनीपत से भर्ती हुई। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मैंने 30 आदमियों की लिस्ट अखबार में जारी की थी। भायद इन्होंने अखबार नहीं पढ़ा होगा। 145 व्यक्ति ऐसे

है जिनकी करैक्टर वैरीफिके ान हुई है। यह रिकार्ड की बात है। वहां के पुलिस स्टे ान मे भी यह रिकार्ड मौजूद है कि 150 लोगो की भर्ती हुई जिसमे से 45 आदमी उसमे इनके सब डिवीजन के पुलिस मे भर्ती हुए है।

**श्री रामफल चिडाना:** यह रिकार्ड की चीज है। मै बगैर रिकार्ड के नही बोल रहा हूं। इतने बडे सोनीपत जिले से 3 आदमियो की भर्ती हो और मुख्यमंत्री कहते है कि गोहाना मेरा, सोनीपत मेरा और मै गोहाना और सोनीपत का। मै यहां विकास नही कर सकता तो और कौन करेगा?

**श्री सभापति:** आप सुझाव दीजिए कि इसके लिए क्या करे?

**श्री रामफल चिडाना:** सभापति महोदय, यदि मलिक साहब के कहे अनुसार बात हम मान ले तो उस हिसाब से भी किलोई हल्के मे से ओर रोहतक हल्के के गावों से 70-70 आदमी लगते है और हमारे सब डिवीजन से 30-35 आदमी लगते है तो यह कहां का न्याय है। कहा का गोहाना और कहो का सोनीपत मुख्यमंत्री जी का हुआ। मै एक बात कहना चाहूंगा जो रिकार्ड की बात है। सभापति महोदय, हम बडे खु ा हुए थे जब यह घोशणा की गई थी कि खानपुर कलां गुरुकल को यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है। बडी उम्मीद थी कि हमारे जिले सोनीपत के बहुत लउके नौकरी लगेगें। चेयरमैन साहब, सोनीपत जिला एजूके ान के

मामले मे हमे 11 से ही अग्रणी रहा है। यह रिकार्ड की बात है। इस बारे मे सूचना के अधिकार के तहत पूछा गया कि खानपुर यूनिवर्सिटी बनने के बाद सोनीपत जिले के कितने बच्चे नौकरी लगाये गये है। उसके बारे मे लैटर आया जिसमे यह बताया गया कि अब तक 27 लैक्चररर्ज की भर्ती की गई है जिनमे से सोनीपत जिले का एक और दस हरियाणा से बाहर के लैक्चररर्ज भर्ती किए गए है। हरियाणा मे भी क्या इतने योग्य लडके नही है कि बाहर से लगाने पडे। मै यह कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी बडे जोर भाोर से कहते है कि हम हरियाणा के बच्चो को नौकरी पर लगायेंगे और फिर बाहर के बच्चो को नौकरी पर रखा जा रहा है।

**श्री जगबीर सिंह मलिक:** सभापति महोदय, इसके बारे मे मै जवाब देना चाहूंगा।

**श्री सभापति:** चौधरी साहब, आप नोट कर ले बाद मे इकटठा जवाब दे देना।

**श्री रामफल चिडाना:** सभापति महोदय वहां पर हमें हमारा हक मिलना चाहिए हमारे साथ ऐसा दोगला व्यवहार किया जा रहा है। जहां तक कानून व्यवस्था की बात करते है, सभापति महोदय, 4 दिसम्बर, 2008 को सत्याराम नाम का ए एस आई जो मेरे हल्के बडौदा का था। गांव पटवाडा मे उसकी हत्या कर दी गई ओर उस बेचारे का परिवार दर दर की ठोकरे खा रहा है लेकिन उसके हत्यारो का आज तक पता नही लगा है। उस ए एस

आई को गोली मार कर मार दिया गया। ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं और पुलिस के आदमियों को सरेआम मार दिया जाता है। एक ए एस आई और उसकी घरवाली को गोलियां मारी गईं उन हत्यारों का आज तक पता नहीं लगा। कानून व्यवस्था की डिटेल्स में जाता हूँ तो आप मुझे रोकते हैं। माननीय सदस्यजी बार बार बोल रहे हैं मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा एक मामला उनही के गांव का है। सूबेदार मेजर जयकरण जिसको उसके कार्यों के लिए राष्ट्रपति जी ने प्रोमिस्ट पत्र दिया था वे इतने योग्य आदमी थे उनका 31.8.2005 को इनके गांव के पास ही कत्ल हुआ था। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कितने दलित हितैशी है क्योंकि वह दलित बिरादरी का आदमी था। वह कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी के पेट्रोल पम्प पर काम करता था इसलिए उस बात को दबा दिया गया। जिस आदमी को राष्ट्रपति ने अवार्ड दे रखा हो उसकी भी मौत का पता न लगे यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

**श्री सभापति:** चिडाना साहब, कन्कल्यूड कीजिए क्योंकि हाउस का समय खत्म होने में केवल दो मिनट ही रह गये हैं।

**श्री रामफल चिडाना:** सभापति महोदय, मुझे पता था कि आप मुझे ऐसे समय में बोलने के लिए समय देंगे। मेरा पास मसला ही इतना था। हमारे साथ आप ऐसा ही करते हैं। आप दलितों की बात सुनें। सरकार के समय में जो हुआ है मैं वही बात बता रहा हूँ।

**श्री सभापति:** चिडाना साहब, कन्कलूड कीजिए क्योंकि हाउस का समय खत्म होने में केवल दो मिनट ही रह गये हैं।

**श्री रामफल चिडाना:** सभापति महोदय, आप समय को एक्सटेंड कर सकते हैं। जब मेरी बात पूरी नहीं हुई है तो मैं कन्कल्यूड कैसे करूँ। स्पीकर सर, जिस आदमी को राष्ट्रपति ने अवार्ड दे रखा हो और उस आदमी की हरियाणा में तेज धार हथियारों से हत्या कर दी जाए। इस बारे में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है लेकिन उसके हत्यारे का अता पता नहीं चले यह यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

**श्री सभापति:** चिडाना साहब, कन्कलूड कीजिए।

**श्री रामफल चिडाना:** सभापति महोदय, आप हमें बोलने से रोक सकते हैं लेकिन जनता जब बोलेगी उसको आप नहीं रोक सकेंगे। जनता सब कुछ हिलाकर रख देगी।

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला:** सभापति महोदय, हाउस का समय बढ़ा दीजिए। माननीय चिडाना जी अच्छा बोल रहे हैं चाहे गलत ही क्यों न बोल रहे हों।

### **बैठक का समय बढ़ाना**

**Mr Speaker:** Is it the sense of the House that the sitting of the House be extended for 5 minutes?

**Voices:** Yes, yes.

**Mr. Chairperson:** Hon'ble Members, the sitting of the House is extended for 5 minutes.

### राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

**श्री रामफल चिडाना:** सभापति महोदय, मे आपको बताना चाहूंगा कि मेरे भाई उदयभान जी ने भी अपनी बात कही। यहां कितने दलित सदस्य हैं। लेकिन कोई भी दलित की बात नहीं उठाता। सभापति महोदय, नौकरियों में रिजर्वेशन का बैकलाग बहुत है। केवल पानी की टूटी देने से, बी पी एल कार्ड देने से हमारा भला नहीं होगा। हमें नौकरियां देने से हमारा भला होगा। मैं जब नौकरी पर था तो हमने कस्टोडियन की 14 एकड़ जमीन बोली पर खरीद ली थी। यदि हमारे भाईयो को नौकरियों न मिले तो वे गंदी बस्तियों में 100-100 गज के प्लॉट लेकर क्या करेंगे। वे अपने आप से माडल टाउन में और हुडडा के सैंक्टर्ज में प्लॉट ले लेंगे। सभापति महोदय, ये हमें बहकाना चाहते हैं। जिस तरह अभी गैस्ट टीचर्ज की बात यहां आई थी। हमारे प्रधान जी ने 20 हजार गैस्ट टीचर्ज लगाए लेकिन उनमें रिजर्वेशन का नाम नहीं सरकार के पास कोई पालिसी नहीं है कि वे रैगुलर भर्ती कर सकें। स्टाफ सिलैबन कमीशन ने 4 साल से कोई भर्ती नहीं की। यह सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे बच्चों के रोजगार का कितना नुकसान हुआ है। यह रोजगार का नुकसान सरकार ने किया है। क्या हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं। सभापति महोदय, ये ग्रेस मार्क्स देकर शिक्षा की बात करते हैं। मैं तो कहूंगा कि ग्रेस

माक्स देने से तो अच्छा है कि अगर स्कूलो मे अध्यापक भर्ती नही कर सकती तो सरकार को वे स्कूल बंद कर देने चाहिए। हमारे बच्चे ग्रेस माक्स के भूखे नही है। उन्हे अच्छी एजुके ान दो, अच्छे टीचर्ज दो और उन्हे अच्छा माहौल दा ताकि वे अच्छे से अच्छा पढकर कम्पीटी ान मे भाग ले सके क्योंकि आज कम्पीटी ान का जमाना है। जो बच्चे कम्पीटी ान मे भाग लेकर आगे बढेंगे वही बच्चे तरक्की करेंगे। ग्रेस माक्स देने से कोई आगे नही बढ सकता है। ग्रेस माक्स देन से तो कोई एजुके ान की दहलीज भी पार नही कर सकता। जब हमारा टाईम था तो कोई ग्रेस माक्स नही होते थे। स्कूला मे पूरे टीचर्ज हुआ करते थे।

**श्री सभापति:** रामफल जी आप कन्कलूड करें

**श्री रामफल चिडाना:** सभापति महोदय, या तो मुझे बोलने के लिए टाईम मत दे और अगर टाईम दे तो पूरा बोलने दो। सभापति महोदय मै दलितो की बात कर रहा था। क्या दलितो की बात आपको अच्छी नही लगती। गैस्ट टीचर्ज की मैने यहो बात की। पब्लिक हैल्थ मे कितने लोग लगाए गए, क्या उनमे कोई रिजर्वे ान दी गई, नही रिजर्वे ान का कोई नाम नहीं। सभापति महोदय, दलितो को 100-100 गज के प्लाट देने के बारे मे इन्दौरा जी कह रहे थे कि हरियाण न्यूज पर ये कहते है कि हमने दलितो के लिए यह कर दिय, वह कर दिया जबकि प्रैक्टिकली क्या किया है यह आप जाकर देख लें। जहां प्लाट दिये



गए है उन बस्तियों में इतनी बदबू आती है कि आपमें से कोई वहां नहीं जा सकता। आपको वोट मिल जाते हैं। अबकी बार महंगाई में आपको पता लगेगा कि दलित लोगों के वोट कैसे मिलते हैं। सभापति महोदय, यहां सड़को की बात आई। हरियाणा में सारी सड़के टूटी पड़ी हैं। सारे प्र नकाल में सड़को के बुरे हाल के बारे में चर्चा चल रही थी और सभी माननीय सदस्य मान रहे थे कि सड़को का बुरा हाल है। परिवहन मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा और जानना भी चाहूंगा कि हमारे राज में डीलक्स बसे चली थी। सभापति महोदय, मंत्री जी का तो बहुतेरा जुगाड है ये तो कारों में चलते हैं लेकिन मैं तकरीबन बसों में चलता हूँ। बसों का बहुत बुरा हाल है। मैं तो यह कहूंगा कि हरेक सरकार अपने मंत्रियों पर यह कंडीशन लगाए कि वे बसों में जाकर देखें कि बसों का क्या हाल है। पब्लिक को बसों में क्या क्या कठिनाईयाँ होती हैं। हमारे टाईम् में डीलक्स बसों में टी वी होते थे लेकिन आज वहां टी वी की जगह कागज भरे हुए हैं। क्या डीलक्स बसे इसलिए बनाई गई थी कि उनमें टी वी की जगह कागज भरे जाएं। क्या सरकार के पास टी वी रिपेयर के लिए भी पैसे नहीं हैं। बसों की खिडकियाँ टूटी हुई हैं तथा ओर भी कोई चीज ठीक नहीं है। परिवहन मंत्री जी, आप चल कर देख ले कि बसों का क्या हाल है। ( गोर एवं व्यवधान)

**श्री सभापति:** रामफल जी, आप कन्कल्यूड करे तथा गवर्नर ऐड्रेस पर ही बोलें।

**श्री रामफल चिडाना:** सभापति महोदय, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि ये कहते हैं कि गोहाना को हम अच्छा बना देंगे। गोहाना में सीवरेज की पाईपस बिछनी थी। माननीय सदस्य बैठे हैं, ठीक है कि इनको अपने मकान के आगे से चलने का स्थान मिल गया। ये 8 महीने से कह रहे थे कि 15 दिन में सड़क बनवा देंगे और सीवरेज के पाईप डलवा देंगे। अब ये एम एल ए बन गए हैं, इनके मकान के आगे छोड़कर बाकी सारी सड़क 8 महीनों से फटी पड़ी हुई है चाहे तो मैं कल इसका फोटो उतरवाकर ले आऊंगा।

**श्री जगबीर सिंह मलिक:** सभापति महोदय, \*\*\*\*\*

**श्री सभापति:** जगबीर सिंह जी क्या आपने जवाब देना है। रामफल जी, आपका समय पूरा हो गया। (विघ्न)

**श्री जगबीर सिंह मलिक:** सभापति महोदय, मुझे पूरा जवाब देना है। गोहाना में आज सारी सड़को पर काम चल रहे हैं। ये गोहाना से बाहर रहते हैं इनको गोहाना के बारे में पता नहीं है। गोहाना में करोड़ों रुपए की लागत से ड्रेनेज के काम चल रहे हैं।

**Mr. Chairperson:** The time is over. Now, the House is adjourned till 2:00 P.M on Thursday, the 12<sup>th</sup> February, 2009.

**18:35 Hrs.**

(The Sabha then adjourned till 2:00 P.M on Thursday, the 12<sup>th</sup> February, 2009).